



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2011/वैशाख 20, 1933

No. 94]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2011/VAISAKHA 20, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2011

अंतिम जाँच परिणाम

**विषय :** चीन जन. गण. तथा जापान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सभी प्रकार के 1, 1, 1, 2-टेट्राफ्लोरोईथेन अथवा आर-134ए के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच ।

**फा. सं. 14/24/2009-डीजीएडी.**—वर्ष 1995 एवं तत्पश्चात् यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं उसके तहत बनाए गए सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन संग्रहण एवं क्षति निर्धारण), नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

**क. मामले की पृष्ठभूमि :**

मामले की पृष्ठभूमि निम्नानुसार है :

1. यतः मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड, गुडगाँव (जिन्हें एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने उक्त अधिनियम तथा नियमावली के अनुसरण में चीन जन. गण. तथा जापान (जिन्हें एतदपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सभी प्रकार के 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन अथवा आर-134ए (जिन्हें एतदपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है और सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है ।

2. और यतः, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, उपर्युक्त नियमों के उप नियम 5(5) के अनुसार सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करते हुए दिनांक 19 अगस्त, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी ।

3. प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 1, 1, 1, 2-टेट्राफ्लोरोईथेन अथवा आर-134ए के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच मै. एसआरएफ लि. जिनका कार्यालय ब्लॉक-सी-8, सेक्टर 45, गुडगाँव, हरियाणा में और फैक्टरी भिवाड़ी, तहसील तिजारा, अलवर, राजस्थान में स्थित है और जो भारत में सम्बद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं, द्वारा दिए गए एक आवेदन के आधार पर दिनांक 19 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. 14/24/2009-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी ।

4. घरेलू उद्योग के आंकड़ों के सत्यापन तथा संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों एवं भारत में संबद्ध वस्तु के सहयोगी आयातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की जाँच करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम शुल्क दिनांक 19 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 14/24/009-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे ।
5. प्रारंभिक जांच परिणाम के जरिए अनंतिम शुल्क के अधिरोपण हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था और राजस्व विभाग ने दिनांक 19 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना सं. 52/2010-सीमाशुल्क के जरिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण को अधिसूचित किया था ।
6. प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार मौखिक सुनवाई हेतु ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 10 मई, 2010 को सार्वजनिक सुनवाई (मौखिक सुनवाई) आयोजित की गई थी ।
7. मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 6952 के जरिए एक रिट याचिका दायर की थी और जाँच की शुरुआत एवं प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम को चुनौती दी थी । माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने याचिकाकर्ता को प्राधिकारी द्वारा आयोजित मौखिक सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया था और प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया था ।
8. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 10 मई, 2010 को हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक सुनवाई के तुरंत बाद याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई की और दिनांक 21 मई, 2010 की संख्या 18/8/2009-डीजीएडी के जरिए सकारण आदेश पारित किया था ।
9. मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 8901 के जरिए एक और रिट याचिका दायर की थी तथा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 52/2010, दिनांक 19 अप्रैल, 2010 पर अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया था ।
10. मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 10709 के जरिए एक और रिट याचिका दायर की थी तथा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क अधिसूचित करने वाली संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचना सहित संबद्ध जाँच की कार्यवाही पर अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया था ।
11. मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 10710 के जरिए एक और रिट याचिका दायर की थी । दिनांक 12 मई, 2010 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के जरिए उक्त रिट याचिका को वापस लिए गए के रूप में रद्द कर दिया गया था ।
12. मुम्बई स्थित एक अन्य आयातक मै. स्टैलियन इंटरप्राइजेज ने संबद्ध जाँच की शुरुआत और प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी । दिनांक 15 जून, 2010 के माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के जरिए उक्त रिट याचिका को रद्द कर दिया गया था ।

13. चेन्नई स्थित एक अन्य आयातक मै. हव्वा एक्विजिम्स ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 13438 के जरिए एक रिट याचिका दायर की थी। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 25 जून, 2010 के आदेश के जरिए अंतरिम स्थगन आदेश दिया था।

14. चेन्नई स्थित एक अन्य आयातक मै. वैल्यू रेफ्रीजेरेन्ट्स प्रा. लि. ने डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 15826 के जरिए एक रिट याचिका दायर की थी। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 21 जुलाई, 2010 के आदेश के जरिए इस मामले में भी अंतरिम स्थगन आदेश दिया था।

15. घरेलू उद्योग ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील सं. 1237 और 1238 दायर की थी। घरेलू उद्योग द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत रिट अपीलों के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रति हलफनामा और स्थगन खारिज करने संबंधी याचिकाओं की प्रति भी नत्थी की थी। माननीय खण्डपीठ ने दिनांक 16 अगस्त, 2010 को अपनी अंतिम सुनवाई में मामले की सुनवाई की थी और आदेश सुरक्षित रखा था।

16. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त अंतरिम स्थगन आदेशों के विरुद्ध घरेलू उद्योग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 के आदेश के जरिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय को 4 सप्ताह के भीतर सुरक्षित रखे गए निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र जारी करने का निर्देश दिया था :

दोनों पक्षों के सुविज्ञ वकीलों की सुनवाई की गई। हम उच्च न्यायालय से लम्बित रिट अपील सं. 2010 का 1237 और 2010 का 1238 तथा रिट याचिका सं. 2010 का 8901 और 2010 का 10709 में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय देने का अनुरोध करते हैं। इस तथ्य के मद्देनजर कि पाटनरोधी शुल्क संबंधी अंतिम जांच परिणाम के संबंध में जारी किए जाने की अंतिम तारीख 18 फरवरी, 2011 है, यह आदेश आवश्यक हो गया है। हम उच्च न्यायालय से अधिमानतः आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय देने का अनुरोध करते हैं। तदनुसार, इस विशेष अनुमति याचिका का निपटान किया जाता है।

17. दिनांक 6 जनवरी, 2011 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने निम्नानुसार निर्णय पारित किया था :

“ 17. अतः दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत एवं तर्क दिए गए विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किए बिना इस दूसरे तथ्य कि शिकायतकर्ता के दर्जे के संबंध में तथ्य पर उठाए गए गंभीर विवादों, जिसका मामले की शुरुआत पर प्रभाव पड़ेगा, इस मामले में शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हम तीसरे पक्ष द्वारा पारित दिनांक 19.04.2010 और 21.05.2010 के आदेशों को खारिज करते हैं और प्रथम पक्ष/भारत सरकार को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस मामले के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु तीसरे पक्ष के स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को नियुक्त/ नामित करने का निर्देश देते हैं। नियुक्त/नामित अधिकारी को इस विषय को प्रशासित करने वाले कानून अर्थात् सीमाशुल्क (टैरिफ) अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 का पूर्ण अनुपालन करते हुए जाँच करने और तत्पश्चात् 6 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। उस समय तक, दिनांक 19/02/2010 की प्रारंभिक रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाएगा। इस निर्देश के साथ इन सभी मामलों का निपटान किया जाता है। व्ययरहित। मामले से संबंधित विविध याचिकाएँ बंद की जाती हैं। ”

18. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेशों के विरुद्ध प्राधिकारी द्वारा सं. 2010 का 18447-18449 के जरिए दायर एसएलपी पर दिनांक 14.01.2011 को सुनवाई हुई थी और उसका निष्फल के रूप में निपटान किया गया था।

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सं. 1913-1916 के जरिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के दिनांक 06.01.2011 के अंतिम निर्णय के विरुद्ध पुनः एसएलपी दायर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2011 को उस पर सुनवाई की गई थी और निम्नानुसार निपटान किया गया था :

“ हमने सुविज्ञ अपर महाधिवक्ता के पक्ष की और पक्षकारों के सुविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की विस्तारपूर्वक सुनवाई की है।

हमारे सुविचारित मत में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। ”

20. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के दिनांक 06.01.2011 के आदेश के अनुपालन में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 3 फरवरी, 2011 के आदेश के अनुसरण में नियमों के नियम 3 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2011 से नए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति की गई थी। यथानियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध जाँच को पूरा करने के लिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 06.01.2011 के निर्णय में उनके द्वारा प्रदत्त समय-सीमा में विस्तार के लिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी।

21. नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 1 मार्च, 2011 को झूत हितबद्ध पक्षकारों की फिर से मौखिक सुनवाई की गई थी और हितबद्ध पक्षकारों को अपनी सुनवाई का तथा अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

22. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 25 मार्च, 2011 के आदेश के अनुसरण में, मै वैल्यू रेफ्रिजरेट प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2010 की रिट याचिका सं. 15826 तथा 2010 की एमपी सं. 1 तथा 2 को निरस्त कर उसके स्थान पर एसआरएफ लि0 बनाम रिफैक्स रेफ्रिजरेट लि0 मामले में दिनांक 06/01/2011 को माननीय डिविजन बेंच द्वारा 2010 की रिट याचिका सं. 1237 तथा उसके समकक्षी मामलों में पारित समान निर्णय को लागू किया।

23. 2010 की रिट अपील सं. 1237 में 2011 विविध याचिका सं. 1 तथा 1 में दिनांक 30 मार्च, 2011 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश दिया था:

“दिनांक 03/02/2011 के आदेश द्वारा माननीय अपेक्स न्यायालय की 2011 की एसएलपी सं. 1913 से 1916 को रद्द किए जाने के मद्देनजर, यह सूचना दी जा सकती है कि नए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति दिनांक 14/02/2011 को की गई है।

तदनुसार यद्यपि याचिकाकर्ता के अनुरोधानुसार छह महीने की समयावधि प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है।

हमारे विचार से जांच संपन्न करने के लिए आज की तारीख से छह हफ्तों की अवधि प्रदान कर समुचित है।

2011 की एमपी सं. 1 और 1 को तदनुसार समाप्त किया जाता है।

इसके अलावा मै0 रिफेक्स रेफ्रिजरेन्ट्स लि0, चेन्नई ने अपने एसएलआर(सी) सीसी सं. 7520-7523/2011 द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के 30 मार्च, 2011 के उपर्युक्त आदेश को चुनौती दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9 मई, 2011 को एसएलपी पर सुनवाई की और उसे रद्द मानते हुए समाप्त कर दिया।

24. पाटनरोधी नियमों के नियम 17 के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच शुरू करने की तारीख से एक साल के भीतर केन्द्र सरकार को अपना अंतिम जांच परिणाम सौंपेंगे यद्यपि केन्द्र सरकार विशेष परिस्थितियों में अपने विवेकानुसार, उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि को छह महीने के लिए आगे और बढ़ा सकते हैं। अतः नियमों के भीतर जांच संपन्न करने के लिए अधिकतम समयावधि जांच शुरू करने की तारीख से 18 महीने है। पाटनरोधी नियमों का उपर्युक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 5.10 के अनुरूप हैं जो निम्नानुसार है:

"जांच प्रारंभ होने के पश्चात विशेष परिस्थितियों को छोड़कर एक वर्ष के भीतर तथा किसी भी परिस्थिति में 18 महीने से अनधिक अवधि के भीतर जांच को संपन्न किया जाएगा।"

25. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेशों के कारण प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों तथा डब्ल्यूटीओ करार में निर्धारित समय सीमा के भीतर संबद्ध जांच संपन्न नहीं कर सके। तथापि मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय डिविजन बेंच के दिनांक 6 जनवरी, 2011 के आदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3 फरवरी, 2011 के आदेश तथा मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय डिविजन बेंच के दिनांक 30 मार्च, 2011 के आदेश के अनुसरण एवं अनुपालन में संबद्ध जांच को प्राधिकारी द्वारा डब्ल्यूटीओ करार एवं पाटनरोधी नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा से आगे जारी रखा गया है।

## ख. प्रक्रिया

26. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरुआत की सूचना देते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:-

i. उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों को उपर्युक्त जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया,

ii. प्राधिकारी द्वारा उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 19 अगस्त 2009 की जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रतियां संबद्ध देशों के भारत स्थित दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को भिजवाई गई थीं। इस जांच से संबद्ध ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। निर्यातकों को प्रेषित पत्र, याचिका तथा प्रश्नावलियों की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भिजवाई गई थी और संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।

iii. उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसरण में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रति ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी

iv. नियम 6(4) के अनुसरण में प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्बद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भिजवाई गई थीं। जापान से जहां कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, वहीं चीन ~~जून~~ गण से संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों से निर्यातक प्रश्नावली और एम ई टी प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए हैं:-

- क) झेजियांग जुहुआ कं. लि., केचेंग जिला, कोझोऊ सिटी, झेजियांग प्रान्त चीन जन गण-324004
- ख) झेझलांग कुहुआफ्लोर-कैमेस्ट्री कं.लि., जुहुआ ग्रुप, केचेंग जिला, कोझोऊ सिटी, झेजियांग प्रान्त
- ग) साइनोकेम एन्वार्यर्मेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लि. 18, साऊथ ऑफ बिनजियांग रोड, शिहुआ इण्डस्ट्रियल पार्क, ताइकांग पोर्ट, जियांगसू प्रान्त, चीन जन.गण.-215433
- घ) साइनोकेम माडर्न एन्वार्यर्मेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान), कं.लि. जिन्हे इंडस्ट्रियल एरिया, जियान इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जोन, जियान, चीन जन.गण
- ङ) ड्यू पांट ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि., 10/एफ बिल्डिंग नं. #11, 399 केयुआन रोड, झांगजियांग हाई-टेक पार्क, पूडांग न्यू डिस्ट्रिक्ट, शंघाई-201203 चीन जन.गण
- च) मेसर्स झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड-कं.लि., दूसरा तल, नं. 243, जुहुआ सेंटर रोड, कुफोऊ चीन

v. चाइना एसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन एण्ड सिलीकॉन इण्डस्ट्री से भी जांच शुरुआत उपरांत विचार/टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।

vi. नियम 6(4) के अनुसरण में भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों एवं उपभोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने हेतु उन्हें प्रश्नावलियां भिजवाई गई थीं और भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों से आयातक प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए हैं:-

- क) नेवाइन फ्लोरीन इंटरनेशनल लि., 35 सी, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015
- ख) ई.आई. ड्यू पांट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डी एल एफ साइबर ग्रीन्स सातवां तल, सी टॉवर, 25 ए डीएलएफ-सिटी, फेज III, गुडगांव- 122002, हरियाणा

vii) संबद्ध वस्तुओं के आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा मेसर्स रिफ्लेक्स रेफ्रीजिरेटर्स लि., मेसर्स चेन्नै मैरीन ट्रेडिंग प्रा.लि.एवं मेसर्स हनीवेल इंटरनेशनल प्रा.लि. से भी जांच शुरुआत उपरांत विचार/टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। उनके द्वारा किए गए निवेदनों पर इस जांच में विचार किया गया है।

(viii) प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै. अमरचंद एंड मंगलदास एवं सुरेश ए. श्राफ एंड कं. ने दिनांक 2 जून, 2010 के अपने पत्र के जरिए मै. मेक्सिकेम फ्लॉर जापान लि., जापान की ओर से निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। विलंब को माफ करने के लिए अपने अनुरोध के समर्थन में उन्होंने कहा है कि मै. मेक्सिकेम फ्लॉर जापान एसए डी सीवी एक मेक्सिकन कंपनी है जिसने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद दिनांक 31 मार्च, 2010 को मै. आईएनईओएस फ्लॉर जापान लि., जापान

(मै. आईएनईओएस यूके, यूके स्थित कंपनी की एक सहायक कंपनी जो रेफ्रीजरेन्ट एचएफसी-आर-134ए का उत्पादन करती है) का अधिग्रहण किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम 19 फरवरी, 2010 को जारी किए गए थे और उन्होंने 31 मार्च, 2010 को जापानी कंपनी का अधिग्रहण किया है और इसे ध्यान में रखते हुए वे 19 अगस्त, 2009 को प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत के संबंध में उत्तर नहीं दे सकते थे। उन्होंने सूचित किया है कि जापान स्थित कंपनी सहित विश्व भर में उक्त कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद ही उन्हें संबद्ध जांच के बारे में पता चला था। तथापि, जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना घरेलू उद्योग द्वारा उनके आवेदन में की गई घोषणा के अनुसार मै. मिशुई ड्यूपोन्ट फ्लोरो कैमिकल्स कं. लि., जापान में ज्ञात उत्पादक/निर्यातक को भेजी गई थी और भारत में जापानी दूतावास को भी भेजी गई थी। परन्तु जापान के किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। उपर्युक्त तथा मै. मेक्सिकेम फ्लॉर जापान लि., जापान की ओर से मै. अमरचंद एंड मंगलदास एवं सुरेश ए. श्रॉफ एंड कं. द्वारा विलंब को माफ करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने मै. मेक्सिकेम फ्लॉर जापान लि., जापान द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(ix) इसी प्रकार, प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै. लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन ने दिनांक 30 अप्रैल, 2010 के अपने पत्र के जरिए मै. हनीवेल फ्लोरीन प्रोडक्ट्स यूरोप बीवी, लार्डरहूगट्वेग, एम्सटर्डम, नीदरलैंड की ओर से निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि हनीवेल, यूरोप को पहले संबद्ध जांच की जानकारी नहीं थी और संबद्ध जांच के बारे में पता लगते ही उन्होंने प्राधिकारी से संपर्क किया है। तथापि, मै. हनीवेल फ्लोरीन प्रोडक्ट्स यूरोप बीवी की यह दलील कि उन्हें पहले संबद्ध जांच की जानकारी नहीं थी, विश्वसनीय नहीं लगती है क्योंकि मै. झेजियांग क्यूहुआ फ्लॉर कं. लि., चीन जन. गण. तथा मै. साइनोकैम इन्वायरोन्मेन्टल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (ताइकांग) कं. लि., चीन जन. गण., जिनसे उन्होंने संबद्ध वस्तु का क्रय किया है और भारत को निर्यात किया है, ने संबद्ध जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त तथा अनुरोध प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने मै. हनीवेल फ्लोरीन प्रोडक्ट्स यूरोप बीवी, लार्डरहूगट्वेग, एम्सटर्डम, नीदरलैंड द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ करने हेतु अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(x) प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै. स्टैलियन इंटरप्राइजेज, मुंबई ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया था, परन्तु विलंब से प्राप्त होने के कारण प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया था। तथापि, मै. स्टैलिन इंटरप्राइजेज, मुंबई द्वारा प्रस्तुत संगत सूचना एवं अभ्यावेदनों पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(xi) चाइना एसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन एंड सिलिकॉन इंडस्ट्री द्वारा भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था और उस पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ खुला रखा गया था;

(xiii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई सी एंड एस) से जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों का ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

(xiv) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने हेतु पर्याप्त होगा, याचिकाकर्ता द्वारा सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के

आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई लेखांकन सूचना के आधार पर उत्पादन लागत पर आधारित क्षति रहित कीमत की गणना अनन्तिम तौर पर की गई;

(xv) प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में गैर बाजार अर्थव्यवस्था अवधारणा के साथ जांच की शुरुआत की गई और उक्त नियमावली के अन्तर्गत संबंधित देश तथा चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों को उक्त अवधारणा के खण्डन का अवसर प्रदान किया गया। उपर्युक्त अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही के दौरान चीन जन गण में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किसी समुचित तीसरे देश के बारे में भी सूचित किया जाएगा। तथापि आवेदकों सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन हेतु प्राधिकारी के समक्ष कोई भी वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया।

(xvi) डीजीएडी द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार क्षति अवधि में जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों को शामिल किया जाता है। संबद्ध मामले में जांच अवधि 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च, 2009 (12 माह) है। तथापि संबद्ध मामले में क्षति की जांच अवधि में वर्ष 2007-08 तथा जांच अवधि (पीओआई) को शामिल किया जाएगा क्योंकि आवेदक ने वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2007-2008 में ही शुरु किया था।

(xvii) पाटनरोधी नियमों के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 10 मई, 2010 और 1 मार्च, 2011 को आयोजित मौखिक सुनवाई में सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया था। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

(xviii) प्रारंभिक जांच परिणामों की अधिसूचना से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों और प्रारंभिक जांच परिणाम के उत्तर में किए गए निवेदनों तथा दोनों मौखिक सुनवाईयों के बाद ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों/खण्डनों में दिए गए तर्कों एवं प्रकटन विवरण के उत्तर में तथा विभिन्न न्यायालयों के समक्ष हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, जहाँ तक उन्हें संगत पाया गया है, पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(xx) प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को जांच से संबंधित आवश्यक तथ्यों के बारे में सूचित करते हुए प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण जारी किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त संगत टिप्पणियाँ/निवेदनों की जांच की गई है और इस जांच में उन पर विचार किया गया है।

(क) मै0 एसआरएफ लि., घरेलू उद्योग की ओर से श्री ए.के. गुप्ता टीपीएम कन्सल्टेंट्स।

(ख) मै0 ड्यू-पोंट ट्रेडिंग (शंघाई) कं.लि. चीन जन.गण., एल ड्यू-पोंट इंडिया प्रा.लि. इंडिया तथा मै0 हनीटेल फ्लोरीन प्रोडक्ट्स यूरोप बीवी की ओर से मै0 लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरन्।

(ग) मै0 मेक्सीकेम फ्लोर, जापान लि0 जापान की ओर से मै0 अमरचन्द मंगलदास एंड सुरेश ए श्रॉफ एण्ड कं.लि.।

(घ) मै0 साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं.लि. तथा मै0 साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताईकांग) कं.लि. की ओर से मै0 सेठ एसोसिएट्स एडवोकेट्स एण्ड लीगल कन्सल्टेंट्स।



किसी भी हितबद्ध पक्षकार जिनमें वे पक्षकार जिन्होंने विभिन्न अदालतों में मामले दायर किए हैं अर्थात् मै0 स्टैलियन इंटरप्राइसेज, मुम्बई, रिफेक्स रेफ्रिजरेट्स लि0 चेन्नई, मै0 हव्वा एग्जिम्स, चेन्नई तथा मै0 वैल्यू रेफ्रिजरेट्स प्रा.लि. चेन्नई शामिल हैं ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। मै0 रिफेक्स रेफ्रिजरेट्स लि0 चेन्नई ने दिनांक 9 मई, 2011 के अपने पत्र द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने और मौखिक रूप से निवेदन करने का अवसर देने के लिए अपने पत्र की तारीख से चौबीस घंटे का समय मांगा था। तथापि इस तथ्य के मद्देनजर कि प्राधिकारी द्वारा मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया गया था और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा 6 मई, 2011 थी, प्राधिकारी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए मै0 रिफेक्सरेफ्रिजरेट्स लि0 चेन्नई को आगे और समय/अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त संगत टिप्पणियों/निवेदनों की जांच की गई है और इस जांच में उन पर विचार किया गया है।

(xix) घरेलू उद्योग तथा चीन जन.गण. के सहयोगी प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था। चूंकि जापान से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, अतः सत्यापन नहीं किया जा सका।

(xxi) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता से संबंधित दावे की जांच की गई है। वह सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उसके गैर गोपनीय सारांश सहित गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है, को गोपनीय माना गया है।

(xxii) निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस जांच में सूचना प्रस्तुत नहीं की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है और प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

(xxiii) \*\*\* इस जांच परिणाम में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना प्रदर्शित करता है, जिसे नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है।

(xxiv) जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनियम दर 45.72 रु.= 1 अम.डॉ. है।

## ग. विभिन्न न्यायालयों के समक्ष वाद

### ग.1 मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेट्स लि., चेन्नई द्वारा दायर डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 6952

27. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद चेन्नई स्थित आयातक मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेट्स लि. ने जाँच की शुरुआत एवं प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 6952 के जरिए एक रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.04.2010 के आदेश के पैरा 6 से 9 में निम्नानुसार निर्देश दिया है :

“6. जाँच को शासित करने वाले उक्त विनियम के अनुसार याचिकाकर्ताओं की एकमात्र शिकायत यह है कि जाँच में उठाए गए विभिन्न विरोधों पर विचार किए बिना अनन्तिम आदेश पारित किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता स्वयं वस्तु का आयातक है। उनके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह को ध्यान में रखते हुए

तथा उत्तरदाता के अनंतिम आदेश के विरुद्ध किसी सुधारात्मक प्रावधान के अभाव में यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता से कोई माँग किए जाने के पूर्व याचिकाकर्ता के हित पर उपयुक्त ध्यान दिया जाए ।

7. मैं सुविज्ञ महाधिवक्ता के इस निवेदन से सहमत हूँ कि नियमों में दिए गए दिशानिर्देशों और आदेश से छेड़छाड़ किए बिना व्यक्तिगत सुनवाई की माँग करते हुए अपने अभ्यावेदन में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध को ध्यान में रखते हुए दूसरे पक्ष को एतद्द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु याचिकाकर्ता को अवसर प्रदान करके दिनांक 24.09.2009 और 05.04.2010 के अभ्यावेदनों के अनुसार याचिकाकर्ता की आपत्ति पर विचार करने और आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर उस पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का अभिज्ञान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 6 के उप-खण्ड 6 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिवादी द्वारा वह सामग्री प्रस्तुत की जाएगी जिसपर विश्वास किया गया है ।

8. जारी किए गए उपर्युक्त निर्देशों पर विचार करते हुए प्रतिवादी को आदेश का कार्यान्वयन न करने का निर्देश दिया जाता है । पारित आदेश के परिणामों के आधार पर संबंधित पक्षकारों के लिए अपने समाधान निर्धारित करने का मार्ग खुला है ।

9. उपर्युक्त अभ्युक्ति के साथ रिट याचिका का निपटान किया जाता है । व्ययरहित । तदनुसार संबंधित याचिकाएँ बंद की जाती हैं । ”

28. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10 मई, 2010 को प्रातः 11 बजे कमरा सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई (मौखिक सुनवाई) के तुरंत बाद उसी स्थान पर अपराह्न 12.30 बजे याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई की गई थी । याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक सुनवाई (मौखिक सुनवाई) में भाग लिया था और उन्होंने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया था । याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में भी भाग लिया था और दिनांक 10 मई, 2010 के अपने पत्र के जरिए उन्होंने अभ्यावेदन किए थे ।

29. मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई द्वारा दायर डब्ल्यूपी सं. 2010 का 6952 के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 19.04.2010 के आदेशों के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21 मई, 2010 की सं. 18.08.2009-डीजीएडी द्वारा सकारण आदेश जारी किया गया था । माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2011 के आदेश के जरिए दिनांक 21.05.2010 के सकारण आदेश को स्थगित कर दिया गया था तथापि दिनांक 10.05.2010 को हुई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर इस जाँच परिणाम में विचार किया गया ।

**ग.2 मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यूपी सं. 2010 का 8901**

30. मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई ने संबद्ध जाँच की शुरुआत, प्राधिकारी द्वारा जारी प्रारंभिक जाँच परिणाम और अनंतिम शुल्क को अधिसूचित करने वाली सीमाशुल्क अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष डब्ल्यूपी सं. 2010 का 8901 के जरिए एक रिट याचिका दायर की थी । माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के पीठ ने मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई द्वारा दायर डब्ल्यूपी सं. 2010 का 8901 के संबंध में दिनांक 5 मई, 2010 के आदेश के जरिए याचिकाकर्ता को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 10 मई, 2010 को आयोजित की जा रही सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया था और यह भी निर्देश दिया था कि जहाँ

तक याचिकाकर्ता का संबंध है, मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक दिनांक 19 अप्रैल 2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 52/2010 को लागू नहीं किया जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेश को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है :

"6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा याचिकाकर्ता के सुविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत सुविज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को 10.05.2010 को आयोजित की जा रही सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने और कानून के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध सभी विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया जाता है तथा तत्पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे। जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक दिनांक 19 अप्रैल 2010 की विवादास्पद अधिसूचना सं. 52/2010-सीमाशुल्क को लागू नहीं किया जाएगा। संज्ञान लिया जाए।"

### ग.3 मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 10709

31. माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के पीठ ने मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई द्वारा दायर डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 10709 के संबंध में डीजीएडी द्वारा की जा रही संबद्ध जाँच की कार्यवाही, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी प्रारंभिक जांच परिणाम और दिनांक 19 अप्रैल 2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 52/2010 के जरिए राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए अनंतिम शुल्क पर अंतरिम स्थगन आदेश दिया था। माननीय पीठ का आदेश निम्नानुसार उद्धृत है :

"आदेश : यह याचिका आदेश हेतु लाई गई है, याचिका एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने एवं मै. सतीश परशरण, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश देता है :-

किए गए अनुरोध के अनुसार अंतरिम स्थगन। संज्ञान लिया जाए। निजी संज्ञान की भी अनुमति है। डब्ल्यूपी सं. 8901/2010 के साथ सुनवाई की जाएगी।"

### ग.4 मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 10710

32. मै. रेफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लि., चेन्नई द्वारा दायर रिट याचिका सं. 2010 का 10710 का माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के पीठ के 12 मई, 2010 के आदेश द्वारा वापस ली गई के रूप में निपटान किया गया था।

### ग.5 मै. हव्वा एक्जिम्स, चेन्नई द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसी सं. 13438

33. चेन्नई स्थित एक अन्य आयातक मै. हव्वा एक्जिम्स बनाम भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका सं. 2010 का 13438 के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में दिनांक 25 जून, 2010 के आदेश के जरिए अंतरिम स्थगन आदेश दिया था और निम्नानुसार आदेश पारित किया था :

"आदेश : यह याचिका आदेश हेतु लाई गई है, याचिका एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने एवं मै. मोहम्मद सलीम, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश देता है :-

अंतरिम स्थगन । संज्ञान लिया जाए । "

**ग.6 मै. वैल्यू रेफ्रीजरेंट्स प्रा. लि., चेन्नई द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 15826**

34. मै. वैल्यू रेफ्रीजरेंट्स प्रा. लि., चेन्नई बनाम भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका सं. 2010 का 15826 के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में दिनांक 21 जुलाई, 2010 के आदेश के जरिए निम्नानुसार आदेश पारित किया था :

"आदेश : यह याचिका आदेश हेतु लाई गई है, याचिका एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत संबंधित शपथ पत्र का अवलोकन करने एवं दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मै. टी. रमेश तथा दोनों याचिकाओं में प्रतिवादियों के लिए नोटिस लेते हुए श्री के. रवीचन्द्रन, अधिवक्ता की ओर से श्री एम. रवीन्द्रन, अपर महाधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद यह न्यायालय निम्नानुसार आदेश देता है :-

श्री एम. रवीन्द्रन, अपर महाधिवक्ता ने प्रतिवादियों के लिए नोटिस लिया था ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सदृश मामलों में इस न्यायालय ने डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 8901 में 2010 के एमबी सं. 2 और 3 में दिनांक 05.05.2010 को अंतरिम आदेश दिया था । यद्यपि रिट अपील दायर की गयी है परन्तु कोई स्थगन आदेश नहीं दिए जाने के कारण रिट अपील का निपटान किए जाने तक इस आदेश को स्थगित किया जाए ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए रिट अपील सं. 2010 का 1237 और 1238 का निपटान होने तक दिनांक 02.08.2010 तक के लिए अंतरिम स्थगन आदेश दिया जाता है ।

अगली सुनवाई 02.08.2010 को होगी ।

**ग.7. मै. स्टैलियन इंटरप्राइजेज, मुंबई द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 971**

35. मै. स्टैलियन इंटरप्राइजेज, मुंबई ने संबद्ध पाटनरोधी जाँच के संबंध में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 971 दायर की थी । माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा दिनांक 15 जून, 2010 के आदेश के जरिए याचिका खारिज कर दी गयी थी ।

**ग.8 मै. हव्वा एक्जिम्स, चेन्नई द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 13438**

36. चेन्नई स्थित एक अन्य आयातक मै. हव्वा एक्जिम्स द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 13438 के जरिए रिट याचिका दायर की गयी थी । माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 25 जून, 2010 के आदेश के जरिए अंतरिम स्थगन आदेश दिया था ।

**ग.9 मै. वैल्यू रेफ्रीजरेन्ट्स प्रा. लि., चेन्नई द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 15826**

37. चेन्नई स्थित एक अन्य आयातक मै. वैल्यू रेफ्रीजरेन्ट्स प्रा. लि., चेन्नई द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी सं. 2010 का 15826 के जरिए रिट याचिका दायर की गयी थी। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में भी दिनांक 21 जुलाई, 2010 के आदेश के जरिए अंतरिम स्थगन आदेश दिया था।

38. घरेलू उद्योग ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील सं. 1237 और 1238 दायर की थी। घरेलू उद्योग द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत रिट अपीलों के साथ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रति हलफनामा और स्थगन खारिज करने संबंधी याचिकाओं की प्रति भी नथी की थी। माननीय खण्डपीठ ने दिनांक 16 अगस्त, 2010 को अपनी अंतिम सुनवाई में मामले की सुनवाई की थी और आदेश सुरक्षित रखा था।

39. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त अंतरिम स्थगन आदेशों के विरुद्ध घरेलू उद्योग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 के आदेश के जरिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय को 4 सप्ताह के भीतर सुरक्षित रखे गए निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र जारी करने का निर्देश दिया था :

दोनों पक्षों के सुविज्ञ वकीलों की सुनवाई की गई। हम उच्च न्यायालय से लम्बित रिट अपील सं. 2010 का 1237 और 2010 का 1238 तथा रिट याचिका सं. 2010 का 8901 और 2010 का 10709 में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय देने का अनुरोध करते हैं। इस तथ्य के मद्देनजर कि पाटनरोधी शुल्क संबंधी अंतिम जांच परिणाम के संबंध में जारी किए जाने की अंतिम तारीख 18 फरवरी, 2011 है, यह आदेश आवश्यक हो गया है। हम उच्च न्यायालय से अधिमानतः आज से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय देने का अनुरोध करते हैं। तदनुसार, इस विशेष अनुमति याचिका का निपटान किया जाता है।

40. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 25 मार्च, 2011 के आदेश के अनुसरण में, मै वैल्यू रेफ्रीजरेन्ट प्रा० लि० बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2010 की रिट याचिका सं. 15826 तथा 2010 की एमपी सं. 1 तथा 2 को निरस्त कर उसके स्थान पर एसआरएफ लि० बनाम रिफैक्स रेफ्रीजरेन्ट लि० मामले में दिनांक 06/01/2011 को माननीय डिविजन बेंच द्वारा 2010 की रिट याचिका सं. 1237 तथा उसके समकक्षी मामलों में पारित समान निर्णय को लागू किया।

41. 2010 की रिट अपील सं. 1237 में 2011 विविध याचिका सं. 1 तथा 1 में दिनांक 30 मार्च, 2011 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश दिया था:

"दिनांक 03/02/2011 के आदेश द्वारा माननीय अपेक्स न्यायालय की 2011 की एसएलपी सं. 1913 से 1916 को रद्द किए जाने के मद्देनजर, यह सूचना दी जा सकती है कि नए निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति दिनांक 14/02/2011 को की गई है।"

तदनुसार यद्यपि याचिकाकर्ता के अनुरोधानुसार छह महीने की समयावधि प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है।

हमारे विचार से जांच संपन्न करने के लिए आज की तारीख से छह हफ्तों की अवधि प्रदान कर समुचित हैं।

2011 की एमपी सं. 1 और 1 को तदनुसार समाप्त किया जाता है।

42. दिनांक 6 जनवरी, 2011 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने निम्नानुसार निर्णय पारित किया था :

“ 17. अतः दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत एवं तर्क दिए गए विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किए बिना इस दूसरे तथ्य कि शिकायतकर्ता के दर्जे के संबंध में तथ्य पर उठाए गए गंभीर विवादों, जिसका मामले की शुरुआत पर प्रभाव पड़ेगा, इस मामले में शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हम तीसरे पक्ष द्वारा पारित दिनांक 19.04.2010 और 21.05.2010 के आदेशों को खारिज करते हैं और प्रथम पक्ष/भारत सरकार को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस मामले के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु तीसरे पक्ष के स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को नियुक्त/ नामित करने का निर्देश देते हैं। नियुक्त/नामित अधिकारी को इस विषय को प्रशासित करने वाले कानून अर्थात् सीमाशुल्क (टैरिफ) अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 का पूर्ण अनुपालन करते हुए जाँच करने और तत्पश्चात् 6 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्देश के साथ इन सभी मामलों का निपटान किया जाता है। व्ययरहित। मामले से संबंधित विविध याचिकाएँ बंद की जाती हैं। ”

43. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेशों के विरुद्ध प्राधिकारी द्वारा सं. 2010 का 18447-18449 के जरिए दायर एसएलपी पर दिनांक 14.01.2011 को सुनवाई हुई थी और उसका निष्फल के रूप में निपटान किया गया था।

44. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सं. 1913-1916 के जरिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के दिनांक 06.01.2011 के अंतिम निर्णय के विरुद्ध पुनः एसएलपी दायर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2011 को उस पर सुनवाई की गई थी और निम्नानुसार निपटान किया गया था :

“ हमने सुविज्ञ अपर महाधिवक्ता के पक्ष की और पक्षकारों के सुविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की विस्तारपूर्वक सुनवाई की है।

हमारे सुविचारित मत में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। ”

45. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न न्यायालयों के समक्ष अपनी रिट याचिकाओं में दिए गए संगत अभिकथन जिन पर प्राधिकारी ने इस जाँच परिणाम में भी विचार किया है, निम्नानुसार हैं :

क) पाटन स्वयं भर्त्सनीय नहीं है क्योंकि यह माना जाता है कि उत्पादक अलग-अलग देशों को अलग-अलग कीमतों पर अपने माल की बिक्री करते हैं। पाटन के रूप में कीमत भेदभाव एक समान अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक परम्परा बन गई है।

- ख) एसआरएफ यह प्रकटन करने में विफल रही है कि वह भी संबद्ध वस्तु की आयातक है ।
- ग) समूची पाटनरोधी कार्यवाही मै. एसआरएफ की उस परियोजना रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई है जिसमें मात्र अनुमान दिए गए हैं ।
- घ) प्राधिकारी ने व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर याचिकाकर्ता को प्रदान किए बिना और 24.09.2009 तथा 05.04.2010 के याचिकाकर्ता के अभ्यावेदनों पर विचार किए बिना अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए ।
- ङ.) याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को भरोसेमंद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए ।
- च) 24 सितम्बर, 2009 तथा 5 अप्रैल, 2010 के अभ्यावेदन पर प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणाम में विचार नहीं किया है ।
- छ) याचिकाकर्ता को न तो पाटनरोधी कार्यवाही की सूचना दी गई और न ही उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया और न ही मै. एसआरएफ की शिकायत अथवा प्राधिकारी के पास अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई ।
- ज) आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि वह स्वयं संबद्ध वस्तु का आयातक भी है ।
- झ) आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की अर्हता रखने के लिए कोई औचित्यपूर्ण मात्रा में उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता है ।
- ट) आवेदक विभिन्न सरकारी सब्सिडियों का लाभानुभोगी है ।
- ठ) विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण अत्यंत अस्पष्ट, व्यापक और स्वैच्छिक ढंग से गलत रूप में किया गया है । प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क उन उत्पादों पर भी लागू किया गया है जिनके बारे में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित होने का दावा किया गया है ।
- ड) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तु की कीमत में कृत्रिम वृद्धि होगी ।
- ढ) चीन और जापान की कंपनियाँ विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अत्यंत लागत मितव्ययी तरीकों तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं और उनकी कीमतें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हैं ।

#### जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. जाँच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. आवेदक की संस्थापित क्षमता घरेलू माँग से काफी कम है ।
- ii. संबद्ध वस्तु पर प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने से आवेदक द्वारा व्यापार पर एकाधिकार हो जाएगा ।

- iii. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु किसी उचित तीसरे पक्षकार को अधिसूचित नहीं किया गया है।
- iv. संबद्ध वस्तु का आयात अमरीका, यूके और जर्मनी से भी किया जाता है। अतः वर्तमान कार्यवाही संबद्ध वस्तु के बारे में अपूर्ण है।
- v. चूँकि आवेदक की बिक्री में वर्ष 2008-09 में 56.33% की वृद्धि हुई है इसलिए इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि आवेदक की इकाई लाभ कमाने वाली इकाई है।
- vi. आवेदक ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इससे यह पता चलता है कि बाजार से अन्य प्रतिस्पर्धियों को दूर रखने के लिए आवेदक की कम कीमत रखने की एक रणनीति है।
- vii. आयात में वृद्धि तथाकथित क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार में माँग में हुई कई गुना वृद्धि के कारण हुई है।
- viii. संबद्ध वस्तु का लागत मितव्ययी उत्पादन करने के लिए चीन जन. गण. और जापान उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।
- ix. घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क उन उत्पादों पर लागू किया गया है जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि वे संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए गए हैं। चीन का आर-134ए शुद्धता और गुणवत्ता के रूप में उच्च कोटि का है।
- x. अधिनियम और नियमों में दिए गए अधिदेश के अनुसार क्षति अवधि 4 वर्ष से कम की होनी चाहिए।
- xi. आवेदक अपनी योजना/परियोजना रिपोर्ट के आधार पर क्षति का दावा कर रहा है जो पूर्णतः अवास्तविक और किसी उचित सत्यापन के बिना अप्राप्तव्य है।
- xii. आवेदक ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के रूप में स्टैलियन तथा हनीवैल को शामिल नहीं किया है।
- xiii. संदर्भाधीन जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का समूचे भारत में व्यापक विचार किया जाना अपेक्षित था।
- xiv. निर्दिष्ट प्राधिकारी को जाँच शुरुआत संबंधी सूचना में सभी तथ्यों का खुलासा करना चाहिए था।
- xv. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि वह स्वयं संबद्ध वस्तु का आयातक भी है। इसके अलावा, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की अर्हता रखने के लिए कोई औचित्यपूर्ण मात्रा में उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता है।
- xvi. डीजीएडी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में सामान्य मूल्य, कारखाना निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन की गणना करने के विस्तृत तथ्यों/समायोजनों का प्रकटन नहीं किया है।
- xvii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातक/उत्पादक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किया गया है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(6क) के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध।
- xviii. एमईटी दावों को अस्वीकार करना अतार्किक तथा अनुचित है।
- xix. मूल सीमाशुल्क तथा सीमाशुल्क शिक्षा उपकर दोनों को पहुँच मूल्य की गणना करते समय शामिल किया जाना चाहिए।
- xx. विभिन्न क्षति मानदण्डों में सुधार से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता नहीं चलता है। क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बिक्री लागत, लाभप्रदता आदि जैसे घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदण्डों से घरेलू उद्योग की स्थापना में किसी वास्तविक क्षति का पता नहीं चलता है।
- xxi. प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी के अभिमत के विपरीत आवेदक की वास्तविक बिक्री मात्रा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित बिक्री से काफी अधिक रही है।



- xxii. किसी उद्योग की शुरूआती अवधि में असमायोजित ऊपरी खर्चों तथा अकुशल उत्पादन प्रक्रिया के कारण लागत काफी अधिक रहती है जिसकी वजह से कच्ची सामग्री की खपत अधिक होती है। इस आशय का निष्कर्ष निकालते समय प्राधिकारी को इन तथ्यों की जाँच करनी चाहिए थी कि संबद्ध क्षति आरोपित पाटित आयातों के कारण हुई है अथवा यह शुरूआती प्रचालनों के कारण हुई है।
- xxiii. वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :

क) माँग में वृद्धि के बावजूद खपत की पद्धति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग अत्यंत उच्च लागत संरचना के कारण आर-134ए की बिक्री में लाभ कमाने में असमर्थ रहा है।

ख) अनुमानित निर्यात लक्ष्यों की तुलना में किए गए कम निर्यात की एकमात्र वजह वर्ष 2008-09 के दौरान घरेलू उद्योग को हुआ घाटा रही है।

ग) एसआरएफ कम कीमत की पेशकश कर रही है; प्रयोक्ताओं द्वारा निर्यातकों पर भी एसआरएफ की कीमत के बराबर कीमत रखने पर दबाव डाला जा रहा है।

घ) घरेलू उद्योग को हुई क्षति और चीन से हुए आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

ड.) बिक्री कीमत में गिरावट, तैयार उत्पादों की माँग में कमी और उत्पादन तथा बिक्री मात्रा में गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक मंदी है।

- xxiv. घरेलू उद्योग ने कभी भी वास्तविक ह्रास का दावा नहीं किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक क्षति तथा वास्तविक ह्रास दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते।
- xxv. परियोजना रिपोर्ट घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना करने और उसका आकलन करने का कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं हो सकती।
- xxvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत काफी अधिक है।
- xxvii. घरेलू उद्योग की लागत के आंकड़ों के आधार पर परिवर्तन के अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य गलत है।
- xxviii. मैक्सिकन जापान ने यह तर्क दिया है कि औद्योगिक ग्रेड, 1-इम्पैक्ट, सीजीएमपी तथा उच्च शुद्धता जैसे संबद्ध वस्तु के विभिन्न प्रकार/ग्रेड हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अलग-अलग प्रकार/ग्रेड प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग औद्योगिक ग्रेड से इतर किसी अन्य ग्रेड का विनिर्माण नहीं कर रहा है।
- xxix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 तथा डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.10 के अनुसार यह जाँच समय बाधित है।

### जाँच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

47. जाँच के दौरान घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- याचिकाकर्ता वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत के बाद विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं कर रहा है।
- चीन के किसी भी उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया जा सकता।

- iii. चीन के उत्पादकों के लिए भारत एक उचित प्रतिनिधिक देश है। इसे अन्य जाँच प्राधिकारियों ने भी स्वीकार किया है।
- iv. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क निराधार है कि आर 134ए के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को लगाने का प्रस्ताव अतार्किक है।
- v. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क निराधार है कि आवेदक उन्नत प्रौद्योगिकी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता और उसने सीएफसी 12 की चरणबद्ध समाप्ति हेतु भारी सब्सिडी भी प्राप्त की है।
- vi. माँग में वृद्धि होना पाटन को आश्रय देने के लिए प्रमाण-पत्र नहीं हो सकता है।
- vii. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि आवेदक की स्थापित क्षमता घरेलू माँग से काफी कम है और शुल्क लगाने से आवेदक का शोषण होगा और व्यापार का एकाधिकार होगा, गलत और आधारहीन है।
- viii. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि चीन जन. गण. एवं जापान में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखानागत कीमत से काफी अधिक है आधारहीन है।
- ix. घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री मात्रा में वृद्धि करने का अर्थ यह नहीं है कि उत्पाद लाभप्रद है।
- x. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात का यह अर्थ नहीं है कि भारतीय बाजार में पाटित कीमत पर उत्पाद का आयात नहीं हो रहा है अथवा यह कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हो रहा है।
- xi. हितबद्ध पक्षकारों का यह उल्लेख कि आयातों में वृद्धि माँग में वृद्धि के कारण हुई है आधारहीन है। आयातों में वृद्धि पाटन के कारण हुई है।
- xii. आवेदक ने उसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है जिसे संबद्ध देशों में उत्पादकों ने उपयोग किया है।
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जापान ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है और चीन को एनएमई के रूप में माना गया है, इसलिए उचित जाँच के बिना शुल्क को लागू करना समीचीन और न्यायसंगत नहीं है। लेकिन जापानी उत्पादकों को चाहिए कि वे प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दें। निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी पक्ष को उत्तर देने के लिए न तो जोर दे सकता है और न ही किसी पक्षकार द्वारा असहयोग से जाँच करने या जाँच पूरी करने से रोक सकता है।
- xiv. घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट इसके निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और प्रमाणनीय सूचना पर आधारित है।
- xv. यह तर्क कि आवेदन ने अपनी स्थापित क्षमता उपयोग के उच्चतर स्तर पर प्रचालन किया है और इस प्रकार कोई पाटन नहीं हुआ है और कोई क्षति नहीं हुई है, आधारहीन है। जैसे कि याचिका एवं लिखित प्रस्ताव में बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने मार्च, 2008 के महीने में 247 मी. टन के उत्पादन स्तर को प्राप्त कर लिया है जो वार्षिक आधार पर 3000 मी. टन की क्षमता बनता है (अर्थात् 10% क्षमता उपयोग)। कंपनी ने पुनः दिसम्बर, 2008 में 239 मी. टन का उत्पादन किया। इससे आवेदक की उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री की स्थापित तकनीकी क्षमता का पता चलता है। इसके बावजूद पाटित आयातों के कारण क्षमता उपयोग पर प्रभाव पड़ा है।
- xvi. अलग पाटन मार्जिन के लिए हनीवेल फ्लोरिन प्रोडक्ट्स, यूरोप बीवी का अनुरोध स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
- xvii. यह तर्क कि प्राधिकारी ने चीन के लिए जिस आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, का प्रकटीकरण नहीं किया है, आधारहीन है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की प्रणाली का प्रकटन प्रारंभिक निष्कर्षों में किया गया है और आवश्यक तथ्यों का प्रकटन केवल प्रकटन विवरण के समय परिकल्पित किए जाने चाहिए।

- xviii. जैसे कि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है यद्यपि प्राधिकारी पहुँच मूल्य की गणना करते समय सीमाशुल्क एवं सीमाशुल्क शिक्षाकर को शामिल करता है, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा देय उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि यह भी कारखाना द्वार स्तर पर प्रभावित होते हैं।
- xix. यह आवेदन कि घरेलू उद्योग ने पीओआई के कुछ ही महीने पहले उत्पादन शुरू किया था और यह क्योंकि इसे उच्च लागत से नुकसान हो रहा है, आधारहीन है। घरेलू उद्योग की क्षति का दावा समस्या के शुरू होने से नहीं हुई है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने केवल मार्च, 2008 में 100% संयंत्र उपयोगिता प्राप्त की। तथापि बाद में संयंत्र उपयोगिता में घरेलू बाजार में उत्पाद के पाटन के कारण गिरावट आई है।
- xx. घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट एक गुप्त दस्तावेज है।
- xxi. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटन के अलावा कोई अन्य तथ्य अभिज्ञात नहीं किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- xxii. पाटन मार्जिन, एनआईपी, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत इत्यादि की गणना को गोपनीय स्वरूप का होने के कारण प्रकट नहीं किया जा सकता है।
- xxiii. चूँकि किसी निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण तभी किया जा सकता है जबकि निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का पात्र हो इसलिए यह निवेदन कि डीजीएडी को उत्पादक/निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए सही नहीं है।
- xxiv. यह तर्क कि चीन से 134क के लिए माँग चीनी सामान की उत्तम गुणवत्ता के कारण है और (उत्पादन में) घरेलू उद्योग की अकुशलता घाटे का कारण है आधारहीन है। कोई उत्तम उत्पाद कम कीमत में नहीं आ सकती है। किसी भी तरह से उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- xxv. यह आवेदन कि घरेलू उद्योग द्वारा भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, आधारहीन है। घरेलू उद्योग ने कंपनी द्वारा रखे गए दस्तावेजों के आधार पर सभी सूचना उपलब्ध कराई है और सूचना प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है।
- xxvi. यह निवेदन कि क्षति के विश्लेषण के लिए पीओआई और 3 वर्षों की कार्यवाही की अवधि होनी अपेक्षित है, सही नहीं है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार प्राधिकारी द्वारा एक कम-से-कम अवधि स्वीकार की जा सकती है।

#### प्रकटन प्रश्नात निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई टिप्पणियाँ

48. निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी गई थी।

- ❖ इस जांच को जारी रखने का अधिकार डीजीएडी के पास नहीं है। चूँकि इससे डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 5.10 का उल्लंघन होता है अतः संबद्ध जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- ❖ घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच अंतर से आयात अपरिहार्य हो जाते हैं और उससे बाजार में एकमात्र घरेलू उत्पादक के एकाधिपत्य को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोइथेन अथवा आर-1349 के विभिन्न प्रकारों/ग्रेडों को समान उत्पाद माना नहीं जा सकता है। घरेलू उद्योग केवल औद्योगिक ग्रेड के आर-134ए का विनिर्माण करता है।
- ❖ सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का प्रकट न किया जाना।
- ❖ गैर-क्षतिकारी कीमत के परिकलन के लिए अपनाई गई गलत पद्धति।

- ❖ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध कराई गई किसी परियोजना रिपोर्ट पर विश्वास किया है।
- ❖ कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है तथा घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

### प्रकटन पश्चात घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ

49. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थी:

- ❖ लगाई गई पूंजी में (क) अचल परिसंपत्तियाँ तथा (ख) आबद्ध निविष्टियों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कार्यकारी पूंजी।
- ❖ पाटनरोधी शुल्क, केवल एक निश्चित राशि आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

50. जाँच के विभिन्न चरणों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए संगत आवेदनों की जाँच की गई एवं इस निष्कर्ष के संगत पैराग्राफों में विचार किया गया।

### घ. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

51. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पादन 1,1,1,2 टेट्राफ्लोरोईथेन अथवा सभी प्रकार के आर 134ए हैं जिसे टेट्राफ्लोरोईथेन जेनेट्रान 134ए, सुवा 134ए, अथवा एचएफसी 134सी, एचएफए 134ए अथवा नॉइफ्लूरेन भी कहा जाता है। यह एक हेलोएल्केन प्रशीतक है जिसके थर्मोडायनेमिक गुणधर्म आर-12 (डाइक्लोरो डाइफ्लूरोमीथेन) के समान होते हैं परन्तु ओजोन डिप्लीशन क्षमता नहीं होती। इसका रासायनिक सूत्र  $\text{CH}_2\text{FCF}_3$  होता है और क्वथनांक -26.3 डि. से. (-15.34 डिग्री एफ) होता है। यह एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग प्राथमिक रूप से घरेलू प्रशीतन तथा ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनरों में उच्च तापमान प्रशीतन हेतु किया जाता है। सम्बद्ध वस्तु के अन्य उपयोगों में प्लास्टिक फोम क्लोईंग क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में उपयोग भेषजों (उदाहरणार्थ ब्रॉकोडायलेटर) की डिलीवरी हेतु प्रोपेलेंट के रूप में गैस डस्टर्स तथा एयर ड्रायरों में सम्पीडित वायु से नमी हटाने में इसका उपयोग किया जाता है।

52. सम्बद्ध वस्तु का आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली) उपशीर्ष 2903 तहत "हाइड्रोकार्बनों के हैलेजन युक्त व्युत्पन्न" उप शीर्ष 29033919 के तहत अन्य फ्लोरीनयुक्त व्युत्पन्न के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई निर्धारित सीमा शुल्क कोड नहीं है और इसका आयात विभिन्न सीमाशुल्क उपशीर्षों के अन्तर्गत किया जा रहा है तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

### विचाराधीन और समान वस्तु पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

53. हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा तर्क दिया गया है कि पीयूसी का काफी अस्पष्टता, व्यापक एवं बेढंगे रूप से निर्धारण किया गया है जो कि गलत है। पाटनरोधी शुल्क की प्रस्तावित लेवी का उत्पाद से परे विस्तार किया गया है जिनका कथित रूप से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्माण का दावा है। आगे यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के औद्योगिक ग्रेड, 1-इम्पैक्ट, सीजीएमपी और उच्च शुद्धता जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार/ग्रेड हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया है

कि भिन्न-भिन्न तरह के प्रकार/ग्रेड प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग औद्योगिक ग्रेड के अलावा अन्य किसी ग्रेड का विनिर्माण नहीं करता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि चीनी एवं जापानी कंपनियाँ विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए लागत प्रभाव प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं और उनकी कीमतें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और शुद्धता एवं गुणवत्ता के रूप में उच्च भी हैं।

54. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु और उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है जिसका कीमत, उपयोग, गुणवत्ता आदि पर कोई प्रभाव पड़ता हो। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि विदेशी उत्पादकों और उनके द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी और प्राथमिक उत्पादन प्रक्रिया तुलनात्मक है; तथापि प्रत्येक उत्पाद उपलब्ध सुविधाओं और जरूरतों के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया अपनाता है; आगे घरेलू उद्योग ने किसी भी तरह के आर-134ए को छोड़ने के लिए मेक्सिकम द्वारा किए गए दावे में विवाद किया है और बताया है कि भिन्न-भिन्न प्रकार कुछ नहीं है बल्कि एक उत्पाद है। यह सिर्फ उत्पादित 134ए के विभिन्न ग्रेड/समूह/प्रकार हैं।

### प्राधिकारी द्वारा जाँच

55. पाटनरोधी नियमावली के नियम घ में समान वस्तु के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख है :-

“समान वस्तु का तात्पर्य ऐसी किसी वस्तु से है जो भारत में पाटन किए जाने हेतु जाँचाधीन उत्पाद से हर प्रकार से समानरूप अथवा समान हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जो हालांकि हर प्रकार से सामान नहीं है किन्तु उसकी विशेषताएँ जाँचाधीन वस्तु की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती जुलती हों।”

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने चीनी उद्यमों की तरह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए गैस फेस प्रणाली को अपनाया है इसलिए विचाराधीन उत्पाद की प्रवृत्ति शुद्धता के स्तर में परिवर्तन नहीं आता है। उत्पाद की जाँच तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े इंगित करते हैं कि चीन से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा अपने तर्क के समर्थन में हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है।

57. संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न तरह के रूपों/ग्रेडों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्तिम उपयोग के रूप में दो प्रकार की संबद्ध वस्तुएँ अर्थात् औद्योगिक एवं चिकित्सा होती हैं। औद्योगिक वस्तुओं का उपयोग प्रशीतन एवं एयरकंडीनशनिंग आदि में होता है जबकि चिकित्सा प्रकारों का उपयोग औषध प्रणोदक मुख्यतः मानवीय खपत के रूप में होता है। दोनों प्रकारों के उत्पादन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी, कच्ची सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया समान हैं, दोनों में अन्तर केवल शुद्धता के स्तर का है, चिकित्सा प्रकारों अर्थात् मानवीय खपत के लिए न्यूनतम अपेक्षित शुद्धता 99.98% है। यद्यपि घरेलू उद्योग के पास जीएमपी प्रमाणपत्र नहीं है, उन्होंने औद्योगिक प्रकारों (प्रणोदक) एवं चिकित्सा प्रकारों दोनों का विनिर्माण एवं आपूर्ति की है तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की संबद्ध वस्तुएँ केवल शुद्धता के स्तर पर आधारित हैं और विभिन्न प्रकार की संबद्ध वस्तुएँ अर्थात् मानवीय खपत का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, शुद्धता का स्तर उच्च होने के कारण हालाँकि औद्योगिक प्रकार का मानवीय उपभोग के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

58. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विशिष्टता, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे गुणधर्मों के रूप में तुलनीय है। यह दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता उसका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर करते हैं। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी का

अभिमत है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के समान संबद्ध वस्तु है।

## ड. घरेलू उद्योग एवं स्थिति हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

59. घरेलू उद्योग की स्थिति एवं दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने जाँच के विभिन्न स्तरों पर तर्क दिया है कि आवेदक चूँकि किसी तर्कसंगत मात्रा में उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता है और संबद्ध वस्तु का आयातक भी है इसलिए वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अधीन घरेलू उद्योग नहीं है।

### घरेलू उद्योग के विचार

60. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

### ड.1 प्राधिकारी द्वारा जाँच

61. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) (अधिसूचना सं. 18/2010-सीमाशुल्क (एनटी) के द्वारा यथासंशोधित-नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी, 2010) में निम्नानुसार उल्लिखित है :

घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में और उससे जुड़े कार्यकलापों में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं- या जिनका उक्त वस्तु का संचयी उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग है बशर्ते कि ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या वे स्वयं उसका आयात कर रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में "घरेलू उद्योग" को शेष उत्पादकों के रूप में संदर्भित माना जा सकता है।

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। अतः प्राधिकारी का अभिमत है कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है और देश में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक होने के कारण नियम 5(3) के अनुसार उन्हें अधिकार प्राप्त है।

## च. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

63. हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि:-

(क) घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट सहित विश्वास किए गए दस्तावेज प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(ख) जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सभी तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए था।

(ग) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में सामान्य मूल्य की गणना से संबंधित विस्तृत तथ्य/समायोजन, कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन की गणना आदि को प्रकट नहीं किया है।

## च.1 घरेलू उद्योग के विचार

64. जहां तक गोपनीयता के मुद्दे का संबंध है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि परियोजना रिपोर्ट प्रकट नहीं की जा सकती, क्योंकि इस रिपोर्ट में संवेदनशील सूचना शामिल है, जिसे प्रकट करने से घरेलू उद्योग के व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गोपनीय आधार पर दी गई सूचना/आंकड़ों को प्राधिकारी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। पाटन मार्जिन, एनआईपी, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत आदि की गणना गोपनीय स्वरूप की होने के कारण प्रकट नहीं की जा सकती है।

## च.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

65. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराई थी। हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों की जांच के उपरांत प्राधिकारी का मत है कि सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं क्षतिरहित कीमत आदि की गणना की विधि इस जांच परिणाम में प्रकट की गई है।

66. जहां तक सूचना की गोपनीयता का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

**गोपनीय सूचना** (1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2) नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप

नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियों, अथवा जांच के दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर उनके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी कोई सूचना, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी दूसरे पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश तैयार नहीं किया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध जरूरी नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

(ख) डब्ल्यूटीओ के पाटनरोधी करार में सूचना की गोपनीयता से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

अनुच्छेद 6.5: कोई भी सूचना जिसका स्वरूप गोपनीय है (उदाहरण के लिए क्योंकि इसके प्रकटीकरण से प्रतिस्पर्धी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटीकरण से सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति जिससे यह सूचना प्राप्त की गई है, पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) अथवा जिसे जांच से संबंधित पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया है, उचित कारण प्रस्तुत किए जाने पर प्राधिकारी द्वारा इसे गोपनीय माना जाएगा। ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना इसे प्रकट नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 6.5.1: प्राधिकारी गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकार से इसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश देंगे। सारांश में पर्याप्त ब्यौरा दिया जाएगा ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु उचित रूप से स्पष्ट हो सके। अपवादात्मक परिस्थितियों में पक्षकार उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसी सूचना संक्षिप्तीकरण के योग्य नहीं है। ऐसी अपवादात्मक परिस्थितियों में उन कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए कि संक्षिप्तीकरण क्यों संभव नहीं है।

अनुच्छेद 6.5.2: यदि प्राधिकारी समझते हैं कि गोपनीयता आवश्यक नहीं है और यदि सूचना प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं, जब तक समुचित स्रोतों से उनकी संतुष्टि हेतु यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता कि वह सूचना सही है।

अनुच्छेद 6.5.2 के फुटनोट (पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार का फुटनोट 18) में निम्नानुसार उपबंधित है:-

सदस्य सहमत है कि गोपनीयता संबंधी अनुरोध मानमाने तरीके से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

67. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राधिकारियों द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से गोपनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन हैं और किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता का संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा गोपनीय सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष भी गोपनीय बन जाता है, यदि ऐसे निष्कर्ष को प्रकट किया जाना गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की परिणति सूचना के प्रकटीकरण में हो सकती है।

83. अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करने से पूर्व अनिवार्य तथ्यों के प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 में निर्धारित किए गए हैं। यहां तक कि नियम 16 के अंतर्गत गोपनीय तथ्य "संबंधित हितबद्ध पक्षकारों" के समक्ष प्रकट किए जाने अपेक्षित है जबकि अगोपनीय तथ्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित है। किसी भी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी दो गोपनीय सूचना को प्रतिस्पर्धी एवं विरोधी हितों वाले पक्षकारों के सामने प्रकट करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार यही पर्याप्त होगा कि वास्तविक आंकड़े प्रकट करने के बजाए निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत के निर्धारण और तुलना में प्रयुक्त विधि हेतु कारणों का पूरा स्पष्टीकरण दिया जाए। सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और क्षतिरहित कीमत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीय सूचना पर आधारित होते हैं और इसे प्रकट करने



से प्रतिस्पर्धी को उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा और इसे प्रकट करने का सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

69. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच में सुविधा हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी पर विश्वास करके प्रदान की गई वाणिज्यिक दृष्टि से संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना को प्रकट कर देने से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में बाजार का वातावरण पूर्णतः दूषित हो जाएगा। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, क्षति रहित कीमत आदि से जुड़ी गोपनीय सूचना प्रकट कर देने से इसका अनावश्यक लाभ घरेलू तथा विदेशी प्रतिस्पर्धियों को होगा और उपभोक्ताओं के समक्ष वे नुकसान की स्थिति में रहेंगे। इसी प्रकार सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत, पहुँच कीमत आदि जैसी निर्यातकों से जुड़ी गोपनीय सूचना का प्रकटीकरण उनके प्रतिस्पर्धियों और क्रेताओं की तुलना में उनके वाणिज्यिक हित को प्रभावित करेगा।

70. एक हितबद्ध पक्षकार अर्थात् मेसर्स रेफेक्स रेफ्रेजिरेन्ट्स प्रा.लि. ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीय सूचना देने का दावा किया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 के अनुसार घरेलू उद्योग, प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों से प्राधिकारी ने मेसर्स रेफेक्स रेफ्रेजिरेन्ट्स के दावे पर अपनी टिप्पणी देने का विशेष रूप से अनुरोध किया था। ऐसे प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग की राय है कि प्राधिकारी गोपनीय सूचना को प्रकट नहीं कर सकते हैं।

71. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धी एवं परस्पर विरोधी हितों वाले हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष गोपनीय सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है। तथापि अगोपनीय सूचना हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट कर दी गई है।

## छ. विविध मुद्दे

72. हितबद्ध पक्षकारों ने जांच के विभिन्न चरणों में निम्नलिखित विविध मुद्दे उठाए थे:-

- i. पाटन वस्तुतः निन्दनीय नहीं है क्योंकि पाटन के रूप में कीमत में भेदभाव एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पद्धति है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से सम्बद्ध वस्तुओं की कीमत में कृत्रिम वृद्धि होगी।
- ii. आवेदक की संस्थापित क्षमता घरेलू मांग से बहुत कम है। संबद्ध वस्तुओं पर प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने से व्यापार पर आवेदक का एकाधिकार हो जाएगा।
- iii. पूरी पाटनरोधी कार्यवाही मेसर्स एसआरएफ की परियोजना रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई है, जिसमें अत्यंत अनुकूल परिणाम शामिल किए गए हैं।
- iv. प्राधिकारी ने जिन दस्तावेजों पर विश्वास किया था उन्हें हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया।
- v. मेसर्स रेफेक्स ने आरोप लगाया था कि प्राधिकारी ने अनंतिम पाटनरोधी शुल्क संस्तुत करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना और याचिकाकर्ता के दिनांक 24/09/2009 और 05/04/2010 के अभ्यावेदनों पर विचार किए बिना जारी किए हैं।
- vi. आवेदक विभिन्न सरकारी सब्सिडियों का लाभानुभोगी है।

- vii. संदर्भाधीन जांच शुरुआत अधिसूचना का पूरे भारत में व्यापक प्रचार किया जाना अपेक्षित था। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सभी तथ्यों को जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रकट किया जाना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने स्टैलियन तथा हनीवेल को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों में शामिल नहीं किया था।
- viii. क्षति अवधि 4 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अधिनियम तथा नियमावली में अधिदेशित है।
- ix. पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 और डब्ल्यूटीओ संबंधी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.10 के अनुसार जांच कालबाधित है।

### छ.1 प्राधिकारी द्वारा जांच

73. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दों की जांच की है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य एवं प्रयोजन अनुचित व्यापार पद्धति को रोकना और डब्ल्यूटीओ के तत्वाधान में पाटित आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर वाले वातावरण का सृजन करना है, न कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा व्यापार के एकाधिकार का संवर्धन करना। पाटन, घरेलू विनिर्माताओं को अस्थिर करने के उद्देश्य से किसी विदेशी विनिर्माता द्वारा सामान्य मूल्य से कम पर बिक्री करने की अवधारणा पर आधारित है। प्रस्तुत मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब बाजार में उत्पाद की मांग उल्लेखनीय थी घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान उठाकर उत्पाद की बिक्री करने पर विवश होना पड़ा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 'पाटन' एक अनुचित व्यापार पद्धति है और इसकी निन्दा की जानी चाहिए यदि स्थापित घरेलू उद्योग को इससे क्षति पहुँचती है, चाहे घरेलू उत्पादक केवल एक है; क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का केवल निवारण करना है। शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में अपाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने का विदेशी उत्पादकों को अधिकार प्रतिबंधित नहीं होगा।
2. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रमाण के आधार पर जांच शुरू की थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि परियोजना रिपोर्ट पर कम्पनी के बोर्ड ने विचार किया था और अनुमोदित किया था। इसके अलावा प्राधिकारी ने जांच की कार्यवाही के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया था।
3. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अगोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक फाइल के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराए गए थे।
4. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स रेफेक्स रेफ्रेजिरेट्स लि0 द्वारा दिनांक 24.09.2007, 5.4.2010 द्वारा प्रस्तुत संगत निवेदनों और जांच की कार्यवाही के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत परवर्ती निवेदनों पर इस प्रकटीकरण में विचार किया गया है। जहां तक हितबद्ध पक्षकारों को निवेदन करने का अवसर प्रदान करने का संबंध है, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया था। मेसर्स रेफेक्स को व्यक्तिगत सुनवाई की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की दो मौखिक सुनवाईयां की थीं और प्राधिकारी द्वारा विचारित

- जांच के अनिवार्य तथ्यों के प्रकटीकरण के अतिरिक्त उन्हें संबद्ध जांच में मौखिक और लिखित निवेदन करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया था ।
5. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी का आरोप आधारहीन है । तथापि प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और वह नोट करते हैं कि एसआरएफ ने एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि एसआरएफ को आर-154ए/एचएफसी-134ए (विचाराधीन उत्पाद) के विनिर्माण हेतु अपना संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार अथवा किसी अन्य संस्थान से कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है । इसके अलावा एसआरएफ ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 1.3.2005 की अधिसूचना सं. 11/2005-सी.शु. के साथ पाठित दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं. 21/2002-सी.शु. के अंतर्गत अपने संयंत्रों में प्रयुक्त आयातित उपस्करों को कतिपय शर्तें पूरी करने पर सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की सूचना का सत्यापन किया है और नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले संयंत्र की स्थापना हेतु घरेलू उद्योग को कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है ।
  6. जांच शुरुआत अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और नियमावली के अनुसार अधिसूचना की प्रति ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भिजवाई गई थी ।
  7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी पद्धतियों से संबंधित डब्ल्यूटीओ समिति ने दिनांक 5 मई, 2000 के दस्तावेज पत्र सं. जी/एडीपी/6 में निम्नलिखित वक्तव्य दिया था:-

"पाटनरोधी जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की अवधि से संबंधित संस्तुति में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि पाटन से संबंधित जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की अवधि सामान्यतः बारह माह होगी और किसी भी स्थिति में छह माह से कम नहीं होगी जो, जहां तक व्यावहारिक हो, जांच शुरुआत की तारीख के निकट समाप्त होगी; और यह कि क्षति की जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होनी चाहिए, जब तक जिस पक्षकार से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, वह कमतर अवधि में अस्तित्व में रहा हो और पाटन की जांच हेतु आंकड़ों के संग्रहण की समस्त अवधि उसमें शामिल हानी चाहिए । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह वांछनीय है कि पाटन हेतु जांच अवधि और जिस अवधि के दौरान क्षति पाई जाती है दोनों पर्याप्ततः सुमेलित होनी चाहिए ।"

प्रस्तुत मामले में घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण हेतु अपने संयंत्र की स्थापना वर्ष 2006-07 में की थी और विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण सुविधा का स्थापना-पूर्व परीक्षण किया जा रहा था ।

8. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 और डब्ल्यूटीओ संबंधी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.10 के अनुसार संबद्ध जांच कालबाधित है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खण्डपीठ के दिनांक 6 जनवरी, 2011 के आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3 फरवरी, 2011 के आदेश के अनुसरण में संबद्ध जांच, नियमावली तथा डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम समय-सीमा अर्थात् 18 फरवरी, 2011 के बाद भी जारी रखी गई है ।

## ज. न्यूनतम से कम सीमा

74. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) तथा अन्य गौण स्रोतों से प्राधिकारी को आयात आंकड़ों तथा चीन जन गण के सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सम्बद्ध वस्तुओं का आयात न्यूनतम से अधिक स्तर पर है ।

## झ. पाटन मार्जिन का निर्धारण

### झ.1 बाजार अर्थव्यवस्था दावे की जांच

75. वर्तमान मामले में प्रारंभिक जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया था और प्राधिकारी संतुष्ट है कि उन्होंने इस तथ्य का खण्डन नहीं किया है । प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के आंकड़ों/सूचना का सत्यापन कर लिया है ।

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में पाटनरोधी जांचों में अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया था । अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबन्ध के पैरा 8(2) के अनुसार चीन जन गण को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है बशर्ते उपर्युक्त नियमावली के अनुसार निर्यातक देश अथवा अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उपर्युक्त अवधारणा का खण्डन किया जाए ।

77. यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबन्ध । के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी अवधारणा का खण्डन किया जा सकता है यदि चीन जन गण के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर सूचना तथा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करके उसके विपरीत सिद्ध कर देते हैं । चीन जनवादी गणराज्य के सम्बद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों /उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना /पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार करने में समर्थ हो सकें कि क्या :-

- (क) चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों के कीमतों, लागत और निविष्टियों, कच्ची सामग्रियों, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन बिक्रियों और निवेश से संबंधित निर्णय बाजार संकेतों के प्रतिक्रियास्वरूप लिए गए हैं जिनमें पूर्ति और मांग प्रदर्शित होती है और इस संबंध में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं ।
- (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति विशेष रूप से परिसंपत्तियों के हास, अन्य बड़े-खातों, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान की दृष्टि से पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से प्राप्त पर्याप्त विकृतियों के अधीन हैं ;
- (ग) ऐसी फर्में दिवालियापन और संपत्ति संबंधी उन कानूनों के अधीन हैं जो इन फर्मों की कानूनी निश्चितता और प्रचालन के स्थायित्व की गारंटी देते हैं, और
- (घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं ।

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत अधिसूचना जारी करने के बाद चीन जन गण से सम्बद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों एवं निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली और बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं एवं गैर-बाजार अर्थव्यवस्था अवधारणा का खण्डन किया है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली एवं बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली में दिए गए उत्तरों की जांच की गई :-

- क) साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लि.
- ख) साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं. लि.
- ग) झेजियांग जुहुआ कं. लि.
- घ) झेजलांग कुहुआफ्लोर केमेस्ट्री कं. लि.
- ङ) झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं. लि.
- च) ड्यू पांट ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि.

79. चीन जन.गण. से निम्नलिखित सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यातक प्रश्नावली तथा बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली से संबंधित उत्तर स्वीकार किए गए और प्राधिकारी द्वारा उनकी सूचनाओं/आंकड़ों का सत्यापन किया गया:

- (क) मै0 साइनोकेम मॉडर्न एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं.लि.
- (ख) मै0 साइनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं.लि.
- (ग) मै0 डू पांट ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि.

### प्राधिकारी द्वारा जांच

मै0 साइनोकेम मॉडर्न एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन (जियान) कं.लि. (उत्पादक/निर्यातक)

80. मै0 साइनोकेम मॉडर्न एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं.लि. ने अपने उत्तर में गैर बाजार अर्थव्यवस्था होने का दावा किया है। एमईटी उत्तर में यह कहा गया है कि चाइना न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ट्रेड कं.लि., जिसका हिस्सा संबद्ध कम्पनी में \*\*\*% है, राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी है। कहा गया है कि इसमें \*\*\*% हिस्सा जियान मॉडर्न केमिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का है।

जियान मॉडर्न केमिकल्स कं.लि. जो संबद्ध कम्पनी की पूर्ववर्ती कम्पनी है के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार यह टिबेट जिगझू कं0लि0 और जियान मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च का एक संयुक्त उद्यम था। जबकि टिबेट जिगझू कं.लि. का हिस्सा \*\*\*% था। जियानल जिगझू मॉडर्न केमिकल्स कं0लि0 में जियांग मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल्स रिसर्च, द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना ऑर्डनेन्स इंडस्ट्री के हिस्से \*\*\*% थे। जियान जिगझू मॉडर्न केमिकल कं.लि. के संयुक्त उद्यम की स्थापना टिबेट प्लान समिति तथा सांग्जी प्रॉबिन्स प्लान समिति, जो राज्य स्वामित्व वाली एजेंसी है के अनुमोदन से की गई थी।

"वेब आधारित जानकारी के अनुसार साइनोकेम ग्रुप/साइनोकेम कॉर्पोरेशन राज्य के स्वामित्व वाली एक कम्पनी है जिसकी स्थापना रसायनों एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री का संवर्धन करने के लिए मूलरूप से 1950 के दशक में की गई थी।

सत्यापन के दौरान कम्पनी द्वारा यह देखा और माना गया कि साइनोकेम ग्रुप कं.लि. अथवा साइनोकेम कॉर्पोरेशन \*\*\*% राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी है जिसकी स्थापना मूल रूप से 1950 के दशक में की गई थी ।

झेजियांग प्रॉविन्स स्टेट एसेट कमीशन राज्य के स्वामित्व वाली एक कम्पनी थी । उसने \*\*\*% तथा \*\*\*% हिस्से के साथ जेजियांग प्रॉविन्स पेट्रोकेम कंस्ट्रक्शन मटीरियल ग्रुप का संवर्धन किया था । जेजियांग प्रॉविन्स पेट्रोकेम कंस्ट्रक्शन मटीरियल ग्रुप के स्वामित्व में \*\*\*% के साथ चाइना न्यू ट्रेड डेवलपमेंट कं.लि. नामक एक कम्पनी थी जिसमें साइनोकेम ग्रुप का हिस्सा \*\*\*% था । राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी, चाइना न्यू ट्रेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं.लि., जिसके राज्य स्वामित्व का प्रतिशत \*\*\*% है राज्य के स्वामित्व वाली एक अन्य कम्पनी जियान मॉडर्न केमिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ संबद्ध कम्पनी पर मालिकाना हक रखती है । इस प्रकारसंबद्ध कम्पनी मै0 साइनोकेम मॉडर्न एनवायर्नमेंटल केमिकल्स (जियान) कं.लि., राज्य के स्वामित्व वाले साइनोकेम ग्रुप साझा नियंत्रण के अधीन \*\*\*% राज्य स्वामित्व वाली कम्पनी है । इसकी सहायक कम्पनी, मै0 साइनोकेम एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं.लि., जो संबद्ध जांच में प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली दो अन्य कम्पनियों अर्थात् \*\*\*% हिस्से के साथ साइनोकेम यूरोप और \*\*\*% हिस्से के साथ चाइना न्यू ट्रेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं.लि. के साथ उसका \*\*\*% का सबसे बड़ा हिस्सा है, मी. \*\*\*% राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी है । आगे यह भी देखा गया है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल से राज्य के स्वामित्व वाली शेयर धारक कम्पनियों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व \*\*\*% है ।

कम्पनी इस तथ्य को दस्तावेजों द्वारा समुचित रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकी कि वर्षों के दौरान कम्पनी का विकास/ परिवर्तन राज्य के हस्तक्षेप से पूर्णतः रहित, बाजार शक्तियों द्वारा शासित था । इसके अलावा प्रतिवादी कंपनी दस्तावेजों की सहायता से यह प्रदर्शित नहीं कर सकी कि कम्पनी द्वारा परिसंपत्तियों/कच्ची सामग्रियों/उपयोग की वस्तुओं की खरीद बाजार स्थिति के अधीन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय कीमतों पर की गई हैं । कम्पनी दस्तावेजों की सहायता से समुचित रूप से यह भी प्रदर्शित नहीं कर सकी किह कम्पनी में निर्णय लेने की प्रक्रिया राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त है ।

कम्पनी एमईपी के दावे के समर्थन में सत्यापन दल को निम्नलिखित संगत सूचना/दस्तावेज/रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असमर्थ रही:

i. राज्य के स्वामित्व वाली ग्रुप कम्पनी, साइनोकेम ग्रुप/साइनोकेम कॉर्पोरेशन, मूल कम्पनिया चाइना न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ट्रेड कं. और जियान मॉडर्न केमिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा संबद्ध एवं सहायक कम्पनियों से संबंधित विवरण/दस्तावेज ।

ii. टिबेट जिगसू कं0लि0 तथा जियान मॉडर्न केमिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टिबेट जिगडू मॉडर्न केमिकल्स कं.लि. में निवेदक है से संबंधित विवरण/दस्तावेज

iii. सब्सिडियों की सूची और सरकारी स्रोत से कम्पनीर को प्राप्त सब्सिडियां

iv. स्थापना के वर्ष से जांच अवधि तक खरीद की तारीख, खरीद की पद्धति, खरीद के स्रोत के विवरण सहित सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान के साक्ष्य में दस्तावेजों के साथ कम्पनी की परिसंपत्तियों की विस्तृत सूची ।

v. टिबेट प्लान समिति तथा सांगजी प्लान समिति की रिपोर्टों की प्रति-जिसके अनुमोदन से वर्ष 1997 में जियान जिगझू मॉडर्न केमिकल्स कं. की स्थापना की गई थी।

vi. संबद्ध कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी में किए गए निवेश/निधि की राशि और स्रोत तथा साइनोकेम जियान की पंजीकृत पूंजी और साइनोकेम ताइकांग में उसके निवेशों के बीच अंतर का औचित्य दर्शाते हुए दस्तावेज।

vii. खरीद के साक्ष्य, खरीद की पद्धति, सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान के साक्ष्य के साथ भूमि और बिलडिंग के रिकॉर्ड।

सत्यापन रिपोर्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध उत्पादक/निर्यातक के पास उनके अभिमतों/टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। तथापि, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। उपर उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर प्राधिकारी ने मै0 साइनोकेम मॉडर्न एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं.लि. को एमईटी दर्जा प्रदान नहीं किया है।

#### मै0 साइनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं.लि. (उत्पादक/निर्यातक)

81. मै0 साइनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं.लि. द्वारा एमईटी से संबंधित उनके उत्तर में यह निवेदन किया गया है कि वे चीन की विदेशी इक्विटी संयुक्त उद्यम कम्पनी हैं। प्रतिवादी कम्पनी ने अपने उत्तर में एमईटी दर्जे का दावा किया है। एमईटी उत्तर में यह कहा गया है कि संबद्ध कम्पनी सीमित देयता वाली कम्पनी और विदेशी इक्विटी संयुक्त उद्यम वाली कम्पनी है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा मै0 साइनोकेम जियान, जो मूल कम्पनी है, के पास है।

तथापि सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उच्चतम नियंत्रक कम्पनी अर्थात् साइनोकेम ग्रुप कं.लि. अथवा साइनोकेम कॉर्पोरेशन, जो वेब आधारित सूचना के अनुसार मूल रूप से 1950 के दशक में स्थापित की गई थी। \*\*\*% राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी है। झेजियांग प्रॉविन्स स्टेट एसेट कमीशन नामक राज्य के स्वामित्व वाली एक अन्य कम्पनी के साथ उसके क्रमशः \*\*\*% तथा \*\*\*% हिस्से के साथ झेजियांग प्रॉविन्स पेट्रोकेम कंस्ट्रक्शन मटीरियल ग्रुप का संवर्धन किया। झेजियांग प्रॉविन्स पेट्रोकेम कंस्ट्रक्शन मटीरियल ग्रुप \*\*\*% हिस्से के साथ साइनोकेम ग्रुप जिसका हिस्सा \*\*\*% है के साथ चाइना न्यू ट्रेड डेवलपमेंट कम्पनी पर मालिकाना हक रखती है। चाइना न्यू ट्रेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं.लि. जो \*\*\*% राज्य स्वामित्व वाली कम्पनी है, एक अन्य राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी अर्थात् जियान मॉडर्न केमिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साइनोकेम मॉडर्न एनवायरनमेंटल केमिकल्स (जियान) कं.लि. पर मालिकाना हक रखती है। साइनोकेम मॉडर्न एनवायरनमेंटल केमिकल्स (जियान) कं.लि. संबद्ध कम्पनी की प्रतिवादी नियंत्रक मूल कम्पनी है जिसका दो अन्य राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियों अर्थात् \*\*\*% हिस्से के साथ साइनोकेम यूरोप तथा \*\*\*% हिस्से के साथ चाइना न्यू ट्रेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कं.लि. के साथ \*\*\*% का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार संबद्ध कम्पनी \*\*\*% राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी है। निदेशक मण्डल के अध्यक्ष सहित सभी 7 निदेशक राज्य के स्वामित्व वाली शेयर धारक कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

सत्यापन के दौरान प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने यह माना कि वह \*\*\*% हिस्से के साथ राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी है तथा निदेशक मण्डल में राज्य के स्वामित्व वाली शेयर धारक कम्पनियों के प्रतिनिधित्व का

प्रतिशत \*\*\*% है। वे इस बात का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि निर्णय लेने की प्रक्रिया राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त है।

प्रतिवादी कम्पनी दस्तावेजी साक्ष्यों की सहायता से यह प्रदर्शित नहीं कर सकी कि कम्पनी द्वारा परिसंपत्तियों/कच्ची सामग्री/उपयोगी वस्तुओं की खरीद बाजार स्थिति के अधीन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों पर की गई है। कम्पनी दस्तावेजों की सहायता से समुचित रूप से यह भी प्रदर्शित नहीं कर सकी कि कम्पनी में निर्णय लेने की प्रक्रिया राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त है। कम्पनी अपने एमईटी दावे के समर्थन में सत्यापन दल को निम्नलिखित संगत सूचना/दस्तावेज/रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असमर्थ रही:

- (i) साइनोकेम ग्रुप जो \*\*\*% राज्य के स्वामित्व वाली तथा उच्चतम नियंत्रक कम्पनी है, से संबंधित विवरण/दस्तावेज।
- (ii) मूल कम्पनी (साइनोकेम जियान) की पंजीकृत पूंजी तथा मूल कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी (साइनोकेम ताईकांग) में किए गए निवेश के बीच अंतर का औचित्य जो संबद्ध कम्पनी के लेखाबद्ध वार्षिक लेखों में दर्शाया गया है तथा निधि का स्रोत।
- (iii) सरकार से प्राप्त सब्सिडियों की सूची।
- (iv) आर 134ए के उत्पादन हेतु इकाई द्वारा विद्युत की खपत।
- (v) सामान्य बैंकिंग प्रणाली के जरिए प्रमुख परिसंपत्तियों के भुगतान वाउचर।
- (vi) संब तथा असंबद्ध पार्टियों से टीसीई तथा एएचएफ की खरीद की नमूना प्रतियाँ।
- (vii) संबद्ध कम्पनी द्वारा संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री हेतु बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ।
- (viii) संबद्ध कम्पनी द्वारा मै ड्यूपोंट शंघाई को की गई संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की मात्रा और उनके रिकॉर्ड में दर्शाई गई खरीद मात्रा के बीच विसंगति के लिए स्पष्टीकरण।  
सत्यापन रिपोर्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध उत्पादक/निर्यातक के पास उनके अभिमतों/टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। तथापि, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। उपर उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर प्राधिकारी ने मै0 साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताईकांगो) कं.लि. को एमईटी दर्जा प्रदान नहीं किया है।

#### मै0 ड्यू पोंट ट्रेडिंग (शंघाई) कं.लि. (निर्यातक)

82. अपने एमईटी उत्तर में मै0 ड्यू-पोंट ट्रेडिंग शंघाई कं.लि. (डीपीटीएस) ने यह निवेदन किया है कि वह मै0 ड्यू पोंट चाइना होल्डिंग कं.लि. की 100% सहायक कम्पनी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि मै0 साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताईवान) कं.लि. जो चीन के कानून के अंतर्गत स्थापित एक निगम है, आर-134ए का एकमात्र (असंबद्ध) आपूर्तिकर्ता है और सितम्बर, 2008 से उनके पास बहुवर्षीय संविदा मौजूद है। सत्यापन के दौरान यह सूचित किया गया कि ड्यू-पोंट चाइना होल्डिंग कं.लि. ('डीसीएच') चीन में प्रमुख ड्यू-पोंट सत्ता है और मै0 ड्यू पोंट ट्रेडिंग शंघाई कं.लि. (डीपीटीएस) की नियंत्रक कम्पनी है। डीपीटीएस, डीएसएच के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में से एक है।



केवल डीपीटीएस ही संबद्ध उत्पाद के व्यापार में संलग्न है। यह सूचित किया गया था कि न तो डीसीएच और न ही डीसीएच की अन्य संबद्ध कम्पनियां संबद्ध उत्पादन करती हैं।

एक व्यापारिक संस्था के रूप में डीपीटीएस ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जे का दावा किया है। डीपीटीएस ने कहा है कि चूंकि डीसीएच संबद्ध उत्पाद है उत्पादन अथवा बिक्री में बिल्कुल शामिल नहीं था इसलिए उन्होंने अलग से एमईटी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। आगे यह स्पष्ट किया गया था कि ड्यू-पॉंट चाइना लि. जो अमेरिका में पंजीकृत एक कम्पनी है, में डीसीएच का \*\*\*% हिस्सा रखती है और डीपीटीएस में डीसीएच का \*\*\*% हिस्सा है।

एक व्यापारिक कम्पनी होने के नाते डीपीटीएस का एमईटी संबंधी दावा संगत नहीं है जब तक की संबद्ध उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था का अपना दर्जा स्थापित न करे।

इसके अलावा डीपीटीएस, जो संबद्ध व्यापारिक कम्पनी है, ने साइनोकेम ताइकांग, जो \*\*\*% राज्य के स्वामित्व वाली चनी उत्पादक/निर्यातक है तथा संबद्ध जांच में सहयोगी प्रतिवादी है, के साथ सहमत कीमत पर भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की खरीद हेतु दीर्घकालिक करार किया है। डीपीटीएस ने मै0 साइनोकेम ताइकांग जो \*\*\*% राज्य स्वामित्व वाली कम्पनी है से उसकी खरीद हेतु भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। डीपीटीएस ने दोनों कम्पनियों के बीच उत्पाद की खरीद और बिक्री करार के अंतर्गत संबद्ध वस्तुओं की खरीद की है।

प्राधिकारी ने पाया है कि मै0 ड्यू पॉंट ट्रेडिंग शंघाई कं.लि. चीन (निर्यातक), मै0 ड्यू-पॉंट चाइना होल्डिंग कं.लि. के \*\*\*% स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है जिसने संबद्ध जांच में एमईटी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। मै0 साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन कमिकल्स (ताइकांग) कं.लि. जो चीन जन.गण. में \*\*\*% राज्य स्वामित्व वाली कम्पनी है जिसे बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। वह आर-134ए की एकमात्र आपूर्तिकर्ता है और उसके पास सितम्बर, 2008 से बहुवर्षीय संविदा मौजूद है।

सत्यापन रिपोर्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध उत्पादक/निर्यातक के पास उनके अभिमतों/टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। तथापि, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। उपर उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर प्राधिकारी ने मै0 ड्यू-पॉंट ट्रेडिंग शंघाई कं.लि. चीन को एमईटी दर्जा प्रदान नहीं किया है।

## झ.॥ जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी मुद्दे

83. जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार से जुड़े निम्नलिखित मुद्दे उठाए थे:-

- उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार किए बिना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(6क)-में स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधानों के विरुद्ध है।

- सम्बद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किसी समुचित तीसरे पक्षकार को अधिसूचित नहीं किया गया है ।
- बाजार अर्थव्यवस्था दावे को अस्वीकार करना अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है ।
- घरेलू उद्योग के लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर परिवर्तन लागत आधारित सामान्य मूल्य का निर्धारण गलत है ।
- गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान संशोधित नियमावली की धारा 9क(6क) के अंतर्गत अधिकारातीत हो चुके हैं ।

### झ. III बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार तथा सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त विचार

84. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार तथा सामान्य मूल्य के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं :-

- i. चीन के किसी भी उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं किया जा सकता है ।
- ii. भारत चीन के उत्पादकों हेतु एक समुचित सहोदर देश है । इसे अन्य जांच प्राधिकारियों ने भी स्वीकार किया है ।
- iii. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क आधारहीन है कि चीन जन.गण. और जापान में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से पर्याप्ततः अधिक है ।
- iv. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जापान ने अभी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है और चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है, अतः समुचित जांच के बिना शुल्क लगाया जाना उचित नहीं है और अन्यायपूर्ण है । परंतु अब जापान के उत्पादकों द्वारा प्राधिकारी को उत्तर प्रस्तुत किए जाने चाहिए । निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी पक्षकार को उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं और न ही किसी पक्षकार का असहयोग प्राधिकारी को जांच कार्यवाही करने और उसे पूरा करने से रोक सकता है ।
- v. यह तर्क आधारहीन है कि प्राधिकारी ने जिस आधार पर चीन हेतु सामान्य मूल्य संरचित किया है, उसे प्रकट नहीं किया है । प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की संरचना की विधि को प्रकट किया है ।
- vi. यह निवेदन कि डीजीएडी के उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना चाहिए, सही नहीं है, क्योंकि किसी निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण तभी किया जा सकता है, जब निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार हेतु पात्र हो ।

### झ. IV प्राधिकारी द्वारा जांच

85. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान संशोधित नियमावली की धारा 9क(6क) के अंतर्गत अधिकारातीत हो चुके हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारण कानूनी उपबंधों के पूर्णतः अनुरूप है ।

86. प्राधिकारी ने इस बात का संज्ञान लिया है कि चीन जन गण के निर्यातकों ने सुसंगत तथ्यों के साथ अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर वे नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में उल्लिखित अवधारणाओं और अपनी कंपनियों हेतु गैर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने के संबंध में उन्हें प्रेषित गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का खण्डन करना चाहते हैं। जहां तक कच्चे माल और अन्य संबंधित निविष्टियों, जिनमें मुख्यतः एएचएफ तथा टीसीई शामिल हैं, की खरीद का संबंध है, उत्पादकों/निर्यातकों ने निवेदन किया है कि उन्होंने इसकी खरीद चीन के बाजार मूल्य पर आंशिक रूप से सम्बद्ध/संबंधित कंपनियों से और आंशिक रूप से निजी पार्टियों से की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार तथा उत्पादन लागत के सही आकलन, दोनों दृष्टियों से कंपनियों द्वारा भुगतान की गई कच्चे माल के कीमतों का मुक्त जांच हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

87. प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी ने किसी भी उत्पादक/निर्यात को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं किया था, क्योंकि किसी ने भी सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ यह सिद्ध नहीं किया था कि 'प्रमुख निविष्टियों की कीमतें बाजार मूल्यों को पर्याप्ततः परिलक्षित करती है।' इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ऐसी स्थिति में जब कच्चे माल की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित बाजार दरों से पर्याप्ततः कम हैं तब न केवल बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार हेतु एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी नहीं होती, बल्कि लागत का निर्धारण भी अनुमान से कम किया जाता है। अतः प्राधिकारी का अभिमत है कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की निर्णायक शर्तों में से एक शर्त भी यदि पूरी नहीं की जाती है तो प्रतिवादी कम्पनियों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करना व्यावहारिक नहीं होगा।

88. सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भी हितबद्ध पक्षकार ने तीसरे बाजार की समुचित अर्थव्यवस्था के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

89. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि 'प्रमुख निविष्टियों की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में बाजार मूल्यों को पर्याप्ततः प्रदर्शित करती है।' ऐसी स्थिति में जब कच्चे माल की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित बाजार दरों से पर्याप्ततः कम हैं तब न केवल बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार हेतु एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी नहीं होती, बल्कि लागत का निर्धारण भी अनुमान से कम किया जाता है। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक स्वीकृत रूप से प्रत्यक्षतः अथवा सहायक कम्पनियों और आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से राज्य द्वारा नियंत्रित हैं।

90. स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मुद्दों, लागत और कीमतों पर उनके प्रभाव और कम्पनियों के व्यावसायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के किसी भी संबद्ध उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है।

## ज. सामान्य मूल्य का निर्धारण

### ज.1 चीन जन.गण. हेतु सामान्य मूल्य का निर्धारण

91. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया था कि प्राधिकारी जांच की कार्यवाही के दौरान उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में चीन जन.गण. हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किसी समुचित तीसरे देश के बारे में सूचित कर सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उपर्युक्त प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी समुचित तीसरे देश के चयन हेतु

प्राधिकारी के समक्ष कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उसने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमत संबंधी सूचना और लागत संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु प्रयास किए हैं परंतु इस बोर में कोई भी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तीसरे देश की लागत और कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकारी को घरेलू बिक्री के बारे में पूर्ण एवं विस्तृत आंकड़े, उत्पादन लागत तथा तीसरे देश के उत्पादकों का सहयोग अपेक्षित होगा, जिसे प्राप्त करने में आवेदक असमर्थ है। चीन की प्रतिवादी कम्पनियों ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले समुचित तीसरे देश के बारे में कोई दावा नहीं किया है। अतः घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि इस मामले में भारत को चीन का समुचित सहोदर देश मान लिया जाए और सामान्य मूल्य का निर्धारण तदनुसार किया जाए।

92. चीन जन.गण. के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को ध्यान में रखते हुए और चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी समुचित तीसरे देश से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः प्राधिकारी नियमावली में उपलब्ध तीसरे विकल्प को अपनाने का निर्णय करते हैं, जिसमें किसी अन्य समुचित आधार को अपनाने का प्रावधान है, जिसमें समान उत्पाद हेतु भारत में वास्तविक रूप से सद्यः अथवा भुगतान योग्य कीमत शामिल हैं, जिसमें यदि आवश्यक हो तों लाभ की समुचित गुंजाइश का समायोजन किय जाएगा और चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य की संरचना की जाएगी। तदनुसार, चीन जन.गण. के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों हेतु विचाराधीन उत्पाद के कारखाना-द्वारा सामान्य मूल्य की संरचना उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। सामान्य मूल्य की संरचना उत्पादकों/निर्यातकों के खपत मानदण्डों और एएचएफ, टीसीई और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे प्रमुख कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की अनुपलब्धता के मामले में नाइट्रोजन की घरेलू कीमत को ध्यान में रखकर की गई है। इसके अलावा सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू उद्योग की विधिवत समायोजित परिवर्तन लागत और एसजी व्ययों को अपनाया गया है। इसके अलावा जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निराशाजनक क्षमता उपयोग के कारण घरेलू उद्योग के स्थायी व्ययों का भी विनियमन किया गया है। 5% की समुचित लाभ मार्जिन को जोड़ने पर चीन जन.गण. हेतु संरचित सामान्य मूल्य \*\*\*\* अम.डॉलर प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

## अ.2 जापान हेतु सामान्य मूल्य

93. जापान के किसी भी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है और प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसे देखते हुए प्राधिकारी ने जापान में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया था। परंतु सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया है और जापान हेतु सामान्य मूल्य की संरचना उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की है। सामान्य मूल्य की संरचना हेतु विधिवत समायोजित समुद्री मालभाड़े सहित एएचएफ, टीसीई और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की अनुपलब्धता के मामले में मालभाड़े के विधिवत समायोजन सहित नाइट्रोजन की घरेलू कीमत पर विश्वास किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार कच्चे माल के खपत संबंधी मानदण्डों, विधिवत समायोजित लागत एवं विविध आय पर विचार किया गया है। इसके अलावा जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निराशाजनक क्षमता उपयोग के कारण घरेलू उद्योग

के स्थायी व्ययों पर विचार किया गया है। इसके अलावा 5% की समुचित लाभ मार्जिन को जोड़कर जापान के उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में संरचित सामान्य मूल्य \*\*\*\* अम.डॉलर प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

## ट. निर्यात कीमत का निर्धारण

### ट.1 चीन जन गण के सहयोगी निर्यातकों हेतु निर्यात कीमत

मेसर्स साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लि.

94. निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों का सौदेवार ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इस जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु सभी निर्यात सौदों पर विचार किया गया है। पैकिंग, अन्तर्देशीय माल भाड़े एवं पत्तन प्रभार विदेशी माल भाड़े, विदेशी बीमे निकासी तथा प्रहस्तन प्रभारों एवं अन्य विविध प्रभारों से संबंधित दावों की अनुमति सत्यापन के अध्यधीन प्रदान की गई है। इस विधि से कारखाना-द्वारा भारित औसत निर्यात कीमत \*\*\*\*\* अम. डॉलर/किग्रा निर्धारित की गई है।

सेजियांग जुहुआ कं.लि. मेसर्स साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं. लि.

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लि. एवं मेसर्स साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं. लि. एवं दूसरे से संबंधित है और मेसर्स साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं. लि. में प्रमुख शेरधारक मेसर्स साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लि. में भी शेरधारक हैं। इसके अलावा मेसर्स साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लि. की पितृ कंपनी स्वीकृत रूप से मेसर्स साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं. लि. है, जो सम्बद्ध पण्य वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री करती है। मेसर्स साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लि. की उत्पादन क्षमता मेसर्स साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं. लि. की उत्पादन क्षमता की तुलना में काफी अधिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इन दोनों कंपनियों की उत्पादन लागत की रेंज लगभग समान होने के बावजूद इन कंपनियों द्वारा प्रभारित सकल कीमत में पर्याप्त अंतर है। प्रस्तुत की गई सूचना से यह नोट किया गया कि यह अंतर मूलतः बल्क छूट के कारण है। निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों का सौदेवार ब्यौरा प्रस्तुत किया है। प्रारम्भिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु सभी निर्यात सौदों पर विचार किया गया है। पैकिंग, अन्तर्देशीय मालभाड़े, तथा पत्तन प्रभार, समुद्री मालभाड़े, समुद्री बीमे के संबंध में किए गए दावों की अनुमति सत्यापन के अध्यधीन प्रदान की गई है। उपर्युक्त को देखते हुए कारखाना - द्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु प्राधिकारी ने समान उत्पादन लागत के कारण 0.54 अम.डॉ. प्रति किग्रा की छूट के समायोजन पर भी विचार किया है। इस विधि से मेसर्स साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं. लि. हेतु कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत \*\*\* अम. डॉलर/किग्रा निर्धारित की गई है।

मेसर्स ड्यू पांट ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि.

96. निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों का सौदेवार ब्यौरा प्रस्तुत किया है। प्रारम्भिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु सभी निर्यात सौदों पर विचार किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करते समय निर्यातक ने पैकिंग प्रभारों, अन्तर्देशीय मालभाड़े, समुद्री मालभाड़े

तथा बीमा प्रीमियम हेतु समायोजन किया है । इसके अलावा कारखाना-द्वारा भारित औसत निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए घरेलू तौर पर खरीदी गई वस्तुओं और ड्यू पांट ट्रेडिंग की लाभ मार्जिन का भी समायोजन किया गया है । इस विधि से मेसर्स ड्यू पांट ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि. हेतु कारखाना -द्वारा निर्यात कीमत \*\*\* अम. डॉलर/किग्रा निर्धारित की गई है ।

**मेसर्स झेजलांग कुहुआफ्लोर - केमिस्ट्री कं. लि. तथा झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेडिंग कं. लि.**

झेजिंग जुहुआ कं.लि., (संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक), मै0 झेजलांग कुहुआफ्लोर-केमिस्ट्री कं.लि. तथा झेजियांग कं.लि तथा झेजियांग गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं.लि. (निर्यातक) संबद्ध पक्षकार है ।

97. झेजलांग कुहुआफ्लोर - केमिस्ट्री कं. लि. ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों का सौदेवार ब्यौरा प्रस्तुत किया है और निवेदन किया है कि मेसर्स झेजियांग जुहुआ कं. लि. (संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक) से संबद्ध वस्तुओं की खरीद के बाद मेसर्स झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं. को अपना निर्यात एजेंट नियुक्त किया और एल/सी विमर्शित भुगतान प्राप्त करने के बाद यानांतरण और सीमाशुल्क घोषणा की गई और भुगतान प्राप्त किया गया । तथापि उनके उत्तर का अवलोकन करते हुए प्राधिकारी ने नोट किया कि नमूना बीजकों तथा अन्य निर्यात दस्तावेजों की प्रतियां मेसर्स झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं. लि. के नाम धारित हैं; इस प्रकार वही भारत के लिए वास्तविक निर्यातक हैं । इसके अलावा मेसर्स झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं. लि. जिन्होंने निर्यातक प्रश्नावली तथा एमईटी प्रश्नावली के उत्तर भी प्रस्तुत किए हैं ने निवेदन किया है कि वह जांचाधीन उत्पाद के वास्तविक निर्यातक नहीं हैं और मात्र एक निर्यात एजेंट है । तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी निर्यात दस्तावेज मेसर्स झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं. लि. के नाम पर हैं । निर्यातक नहीं बल्कि केवल एक निर्यातक एजेंट हैं । उत्पादक से निर्यातक तक तथा उसके पश्चात भारतीय क्रेता तक वस्तुओं के सुचारु प्रवाह के अभाव में प्रारंभिक जांच परिणाम में प्रतिवादी निर्यातक हेतु स्वतंत्र पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया गया है ।/।

प्रारंभिक जांच परिणाम के पश्चात यह स्पष्ट किया गया कि मै0 झेजलांग कुहुआफ्लोर-केमिस्ट्री कं0लि0 के अनुरोध पर मै0 झेजियांग जुहुआ कं0लि0 (उत्पादक) ने संबद्ध वस्तुओं को सीधे मै0 झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं0लि0 तक पहुँचाया था तत्पश्चात उन्होंने भारत को वस्तुओं का निर्यात किया तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन किया । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक मै0 झेजियांग जुहुआ कं0लि0 की घरेलू बिक्री के संबंध में दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि मै0 झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं0लि0 को ऐसी आपूर्ति की गई थी । इसके अलावा मै0 झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं0 लि0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उत्पादक मै0 झेजियांग जुहुआ कं0लि0 से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की खरीद की गई थी, यद्यपि निर्यात दस्तावेज उन्हीं के नाम पर हैं । इसके अतिरिक्त यद्यपि निर्यात दस्तावेजों में मै0 झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं0 का नाम, संबद्ध वस्तुओं के वास्तविक निर्यातक के रूप दर्शाया गया है, जिन्होंने विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया था, तथापि परिशिष्ट-2 (निर्यात बिक्री का) में मै0 झेजलांग कुहुआफ्लोर-केमिस्ट्री कं0लि0 ने भारत को किए गए निर्यात बिक्री सौदों को दर्शाया है । परंतु भारत को संबद्ध वस्तुओं का वास्तविक निर्यातक होने के बावजूद मै0 झेजलांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं0 द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में संगत परिशिष्ट संलग्न नहीं है । चूंकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन तथा भारत को उसके निर्यात के बीच संबंध के विषय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद भी प्राधिकारी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए अतः झेजलांग कुहुआफ्लोर केमिस्ट्री कं0लि0 अथवा झेजियांग जुहुआ गोंगलियान फॉरेन ट्रेड कं0लि0 दोनों के लिए ही अलग-अलग

निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं किया गया है। उपर्युक्त के मदेनजर प्राधिकारी ने मै0 झेजियांग जुहुआ कं0लि0, मै0 झेजलांग क्वाहुआफ्लोस्-केमेस्ट्री कं0लि0 तथा मै0 झेजियांग जुहुआ गोंगलियन फॉरेन ट्रेड कं0लि0 को असहयोगी मानने का प्रस्ताव किया है।

## ट.2 चीन के असहयोगी निर्यातकों हेतु निर्यात कीमत

98. चूंकि चीन जन गण से सम्बद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उनकी निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के अनुसार करने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा आईबीआईएस स्रोत के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आंकड़ों का संकलन किया गया और चीन जन गण के असहयोगी निर्यातकों के संबंध में कारखाना-द्वार कीमत ज्ञात करने हेतु सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर पैकिंग, अन्तर्देशीय मालभाड़े तथा पत्तन प्रभार, समुद्री मालभाड़े समुद्री बीमे, निकासी तथा प्रहस्तन प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों से संबंधित समायोजन किए गए। उपर्युक्त विधि को अपनाते हुए कारखाना-द्वार निर्यात कीमत \*\*\*\* अम. डॉलर/किग्रा निर्धारित की गई है।

## ट. 3 जापान के निर्यातकों हेतु निर्यात कीमत

99. जापान के किसी भी निर्यातक ने जांच शुरुआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है। अतः कारखाना-द्वार निर्यात कीमत की गणना हेतु जापान से हुए निर्यातों के संबंध में आईबीआईएस, मुम्बई द्वारा सूचित आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। चूंकि ये सौदे सीआईएफ आधार पर किए गए हैं, अतः कारखाना-द्वार निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु समुद्री मालभाड़े, समुद्री बीमे, प्रहस्तन प्रभारों पत्तन व्ययों हेतु समायोजन किए गए हैं। उपर्युक्त विधि को अपनाते हुए जापान के निर्यातकों हेतु कारखाना-द्वार निर्यात कीमत \*\*\* अम. डॉलर/किग्रा निर्धारित की गई है।

## ठ. पाटन मार्जिन

100. पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य तथा अनन्तिम रूप से निर्धारित उपर्युक्त निर्यात कीमतों की तुलना व्यापार के समान स्तर पर की गई है और सम्बद्ध देशों के निर्यातकों हेतु पाटन मार्जिन का अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया है। उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्यों तथा निर्यात कीमतों के आधार पर निर्यातकों हेतु पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित तालिका में किया गया है :-

निम्नलिखित देश के निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (अम. डॉलर)	निर्यात कीमत (अम. डॉलर)	पाटन मार्जिन (अम. डॉलर)	पाटन मार्जिन %
जापान	***	***	***	25-35
चीन जन गण	***	***	***	
सिनोचैम एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग)	***	***	***	35-45
सिनोचैम एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जिआन)	***	***	***	30-40
ड्यू पांट	***	***	***	40-50
अन्य	***	***	***	45-55

101. इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन अत्यधिक हैं और न्यूनतम स्तर से अधिक हैं।

## ड. क्षति निर्धारण की विधि तथा कारणात्मक संबंध की जांच

### ड.1 जांच के दौरान निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

102. जांच के दौरान निर्यातक, आयातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार विचार प्रकट किए गए:

- i. संबद्ध वस्तुओं का आयात अमरीका, यूके तथा जर्मनी द्वारा भी किया जाता है। अतः संबद्ध वस्तुओं के संबंध में वर्तमान कार्रवाई अपूर्ण है।
- ii. चूंकि वर्ष 2008-09 में आवेदक की बिक्री में 56.33% की वृद्धि हुई है अतः यह स्पष्ट है कि आवेदक की इकाई एक लाभकारी इकाई है।
- iii. आवेदक ने वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कम कीमत, बाजार से अन्य निर्यातकों को बेदखल करने की आवेदक की कार्यनीति है।
- iv. आयात में वृद्धि, कथित रूप से क्षति की अवधि के दौरान भारतीय बाजार में मांग में कई गुणा वृद्धि होने के कारण हुई है।
- v. पहुँच मूल्य का परिकलन करते समय आधारभूत सीमाशुल्क तथा सीमाशुल्क शैक्षिक उपकरण दोनों को शामिल किया जाना चाहिए।
- vi. विभिन्न क्षति मानदण्डों में सुधार से यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बिक्री लागत, लाभप्रदता आदि जैसे घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदण्डों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का कोई संकेत नहीं मिलता है।
- vii. प्रारंभिक जांच में प्राधिकारी के मतों के विपरीत, आवेदक की वास्तविक बिक्री मात्रा; परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित बिक्री मात्रा से कहीं अधिक है।
- viii. किसी भी उद्योग की शुरुआती अवधि के दौरान, असमाविष्ट उपरी खर्चों तथा अकुशल उत्पादन प्रक्रिया के कारण लागत अत्यधिक उच्च रहती है, जिसके परिणामस्वरूप कच्ची सामग्री की खपत अत्यधिक उच्च बनी रहती है। इस निष्कर्ष का निर्धारण करते समय कि यह क्षति कथित रूप से पाटित आयातों के कारण अथवा शुरुआती प्रचालनों के कारण हुई है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन तथ्यों की भी जांच की जानी चाहिए थी।
- ix. निम्नलिखित बातों के मद्देनजर इस मामले में कारणात्मक संबंध का निर्धारण अनुचित है:

- मांग में वृद्धि के बावजूद खपत की पद्धति में परिवर्तन, घरेलू उद्योग आर134ए की बिक्री में, उसकी अत्यधिक उच्च लागत संरचना के कारण लाभ अर्जित करने में असमर्थ रहा है।
- अनुमानित निर्यात लक्ष्य की तुलना में अल्प वास्तविक निर्यात वर्ष 2008-09 के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रमुख कारण रहा था।
- एसआरएफ अत्यधिक कम कीमतों की पेशकश कर रहा है। उपयोक्ता, निर्यातकों पर भी अपनी कीमतें एसआरएफ के अनुसार निर्धारित करने का दबाव डाल रहे हैं।
- घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा चीन से आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।



- वैश्विक मंदी, बिक्री कीमत में गिरावट, तैयार उत्पादों की मांग में गिरावट तथा उत्पादन एवं बिक्री मात्राओं में गिरावट की प्रमुख वजह है।

- x. घरेलू उद्योग ने कभी भी वास्तविक क्षति का दावा नहीं किया है। इसके अलावा, वास्तविक क्षति तथा घरेलू उद्योग में वास्तविक मंदी एक साथ मौजूद नहीं हो सकती हैं। घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना एवं मूल्यांकन हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है।

## ड.2 घरेलू उद्योग का विचार

103. जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नानुसार मत व्यक्त किया गया है:-

- घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि का अभिप्राय यह नहीं है कि उत्पाद लाभकारी है।
- घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात का अर्थ यह नहीं है कि उत्पादन का आयात भारतीय बाजार में पटित कीमतों पर नहीं किया जा रहा है अथवा पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।
- हितबद्ध पक्षकारों का यह मत कि आयात में वृद्धि, मांग में वृद्धि के कारण हो रही है, आधारहीन है। आयात में वृद्धि पाटन के कारण हो रही है।
- आवेदक उसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है जो संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा उपयोग में लाई जाता है।
- घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट उसके निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की जाती है और वह सत्यापन योग्य सूचना पर आधारित होती है।
- यह तर्क कि आवेदक ने संस्थापित क्षमता उपयोग के उच्चतम स्तर पर प्रचालन किया है और इसलिए कोई पाटन अथवा क्षति मौजूद नहीं है आधारहीन है। याचिका तथा लिखित निवेदनों में इस तथ्य के अनुसार कि याचिकाकर्ता ने मार्च, 2008 में 247 मी. टन का उत्पादन स्तर प्राप्त किया है, का तात्पर्य यह है कि वार्षिकीकृत आधार पर 3000 मी. टन क्षमता का उपयोग (अर्थात् 100% उपयोग) किया गया है। कम्पनी ने दिसम्बर, 2008 में पुनः 239 मी. टन का उत्पादन किया था। इससे यह स्पष्ट है कि उत्पादक के पास उत्पाद का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने की तकनीकी क्षमता मौजूद है। वास्तव में पाटित आयातों के कारण क्षमता उपयोग पर प्रभाव पड़ा है।
- यह मत कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के कुछ ही माह पूर्व उत्पादन शुरू किया है और इसलिए उसकी लागतें उच्च हैं, आधारहीन है। घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति शुरुआती समस्याओं के कारण नहीं है। वास्तव में याचिकाकर्ता ने मार्च, 2008 में ही 100% संयंत्र उपयोग प्राप्त कर लिया था। तथापि, घरेलू उद्योग में उत्पादन के पाटन के कारण संयंत्र उपयोग में तदनुसार गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है।
- किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटन को छोड़कर किसी अन्य कारक को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के रूप में अभिज्ञात नहीं किया है।
- यह मत कि घरेलू उद्योग द्वारा भ्रामक आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, आधारहीन है। घरेलू उद्योग ने कम्पनी द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं और प्राधिकारी द्वारा सूचना का सत्यापन किया गया है।

## ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

104. जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है:-

1. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क सही नहीं है कि अमरीका, यूके तथा जर्मनी द्वारा भी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जाता है और इसलिए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में वर्तमान कार्रवाई अपूर्ण है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन/याचिका, चीन जन.गण. और जापान से आयातों के विरुद्ध है। अमरीका, यूके और जर्मनी से आयातों के संबंध में प्राधिकारी ने तथ्यों की जांच की है और यह पाया है कि यद्यपि अमरीका, यूके तथा जर्मनी से भी आयात किए गए हैं परंतु वे संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में अधिक उच्च कीमतों पर किये गए हैं।
2. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क सही नहीं है कि वर्ष 2008-09 में आवेदक की बिक्री का स्तर बढ़कर 56.33% हो गया था। अतः आवेदक की इकाई एक लाभकारी इकाई है। केवल बिक्री मात्रा में वृद्धि का तात्पर्य यह नहीं है कि उत्पाद लाभदायक है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच सभी क्षति मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए।
3. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क की आवेदक ने वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में आवेदक ने वस्तुओं का निर्यात किया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह बाजार से अन्य भागीदारों को बेदखल करने की एक कार्यनीति थी, के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में क्षति की जांच घरेलू बाजार के परिप्रेक्ष्य में की गई है।
4. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क कि आयात में वृद्धि कथित रूप से क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार में मांग में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई है, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में वृद्धि होने से निर्यातकों/उत्पादकों को पाटित कीमतों पर वस्तु का निर्यात करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तथापि इस अवधि के दौरान संबद्ध देशों एवं अन्य देशों का बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2007-08 से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है और इसलिए देश में नई उत्पादन सुविधा के शुरू होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप आयातों में थोड़ी गिरावट होना सामान्य है। आयातों में वृद्धि, पाटन के कारण हुई है। पाटन के अभाव में याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से मांग में वृद्धि होने के समय पर अधिक उत्पादन एवं बाजार में अधिक बिक्री कर सकते थे।
5. हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि पहुँच मूल्य का परिकलन करते समय आधारभूत सीमाशुल्क तथा सीमाशुल्क शैक्षिक उपकरण, दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने पहुँच मूल्य का परिकलन करते समय दोनों पर विचार किया है।
6. हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि विभिन्न क्षति मानदण्डों में सुधार से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कारकों के संचयी प्रभाव से यह संकेत मिलता है कि समग्र अर्थों में उत्पादन एवं बिक्री में सुधार, क्षमता उपयोग में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, प्रति इकाई घाटे में कमी, बाजार हिस्से में वृद्धि के बावजूद बिक्री की उच्च लागत की तुलना में बिक्री कीमत में कमी तथा संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अत्यधिक घाटा हुआ था। संबद्ध देशों से आयात मजबूत बने हुए हैं तथा इनसे कीमतों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण ह्रास, कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं।
7. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि किसी उद्योग की शुरुआती अवधि के दौरान असमाविष्ट उपरी खर्चों तथा अकुशल उत्पादन प्रक्रिया के कारण लागत अत्यधिक उच्च बनी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप कच्ची सामग्री की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है तथा इस निष्कर्ष का निर्धारण करते समय कि यह क्षति कथित रूप से पाटित आयातों के कारण अथवा शुरुआती प्रचालनों के कारण हुई है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन तथ्यों की भी जांच की जानी चाहिए थी। यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता ने मार्च, 2008 में ही 100% संयंत्र उपयोगिता प्राप्त कर ली थी। तथापि घरेलू बाजार में उत्पाद के पाटन के कारण तदनन्तर संयंत्र की उपयोगिता में गिरावट आई थी।

8. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने कभी भी वास्तविक मंदी का दावा नहीं किया है। इसके अलावा, वास्तविक क्षति तथा घरेलू उद्योग में वास्तविक मंदी एक साथ मौजूद नहीं हो सकती हैं। घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना एवं मूल्यांकन हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है। नियमों के अंतर्गत, प्राधिकारी, पाटित आयातों की मात्रा सहित, सभी संगत तथ्यों तथा समान वस्तुओं के घरेलू बाजार पर उनके प्रभाव तथा समान वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर आयात के परिणामी प्रभाव तथा नियम के अनुबंध-11 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग के संगठन में वास्तविक कमी तथा पाटित आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि इन मानदण्डों में सुधार, नई उत्पादन सुविधाओं की शुरुआत का प्राकृतिक परिणाम है, तथापि इस तथ्य से कि याचिकाकर्ता देश में अत्यधिक मांग के बावजूद सृजित क्षमता के अनुरूप इनमें विस्तार नहीं कर पाया है, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के संगठनों में वास्तविक कमी है। इसके अलावा घरेलू उद्योग को हुए नकारात्मक लाभ से यह स्पष्ट है कि यह पाटित आयातों के परिणामस्वरूप हुआ है।

105. चीन और जापान से किए गए पाटन की सीमा और अस्तित्व की जांच के बाद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, तथा पाटित आयातों एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की है। प्राधिकारी का अभिमत है कि आवेदक कंपनी अर्थात् मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड का पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अन्तर्गत जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। अतः नियमावली के अर्थ के भीतर क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवेदक कंपनी को घरेलू उद्योग माना गया है।

106. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..... " ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

107. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच हेतु उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध 11 के अनुसार घरेलू उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों यथा उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की सीमा एवं मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।

108. चीन तथा जापान से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध अनिवार्य तथ्य निम्नानुसार है, जो प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रारंभिक निर्धारण का आधार हैं। डीजीएडी द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार क्षति अवधि में जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों को शामिल किया जाता है। सम्बद्ध मामले में जांच की अवधि 1 अप्रैल 2008 से शुरू होकर 31 मार्च 2009 (12 माह) तक की है। तथापि क्षति की जांच अवधि में वर्ष 2007-08 और जांच अवधि को शामिल किया जाएगा, क्योंकि आवेदक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2007-08 से ही शुरू किया गया था। अतः घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक कारकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा आदि की जांच उक्त क्षति अवधि के सन्दर्भ में की गई है। तथापि आयातों (मात्रा तथा मूल्य) से संबंधित सूचना पूर्ववर्ती

तीन वर्षों के संबंध में भी उपलब्ध होने के कारण क्षति विश्लेषण में चार वर्षों की अवधि अर्थात् जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों को शामिल किया गया है ।

#### ढ. क्षति का संचयी आकलन

109. नियमावली के अनुबंध II (iii) के अनुसार यदि एक से अधिक देश से हुए किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी के लिए केवल उस स्थिति में ऐसे आयातों के संचयी प्रभाव का निर्धारण अपेक्षित होता है जब वह यह निर्धारित करे कि :-

(क) अलग-अलग देशों से हुए आयात के संबंध में पाटन मार्जिन, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीमा से अधिक हैं अर्थात् आयातों के 3% से अधिक हैं प्रत्येक देश से किए गए आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों के 3% से अधिक बनती है, और,

(ख) आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है ।

110. प्राधिकारी ने पाया है कि प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन का मार्जिन 2% से अधिक रहा है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा भी 3% से अधिक रही है ।

111. आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों का आकलन करने की दृष्टि से प्राधिकारी नोट करते हैं कि -

क. विदेशी उत्पादक द्वारा आपूर्ति की गई और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु परस्पर समान वस्तुएं हैं ।

ख. प्राधिकारी ने पाया है कि आयातित संबद्ध वस्तु घरेलू रूप से उत्पादित आर-134 ए को वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापित करती है ।

ग. प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई सूचना से यह तर्कसंगत संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से किए गए निर्यात समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि ये समान उत्पाद हैं ।

112. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयातों के घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तु पर पड़ने वाले प्रभाव का आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में संचयी आकलन करना उचित है ।

113. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है (अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई उत्तर नहीं मिला था)

114. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में निम्नलिखित दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी :

(क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और

(ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव

115. प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करें कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभावों के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्थिति तक बढ़ गई होगी।

116. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर संचयी प्रभाव और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों पर इसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, का मूल्यांकन किया जा सके। चूंकि संबद्ध देशों से निर्यातों के लिए भारी पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, इसलिए क्षति विश्लेषण और कारणात्मक संबंध की जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से हुए समस्त आयातों को पाटित आयात माना गया है।

#### ण. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

117. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। जहां तक आयात की मात्रा का संबंध है, डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़े तथा द्वितीयक स्रोतों अर्थात् आई बी आई एस द्वारा बताए गए आयात आंकड़ों की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में भिन्न-भिन्न नामों और भिन्न-भिन्न सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भारत में किए जा रहे संबद्ध वस्तु के आयातों को शामिल नहीं किया गया है और इसलिए आई बी आई एस स्रोत से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया गया है अतः आई बी आई एस स्रोत के आधार पर सौदा स्तर के आंकड़ों पर भरोसा किया गया है और आयातों की मात्रा और मूल्य का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :

#### त.1 आयात मात्राएं और संबद्ध देशों का हिस्सा

118. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

120. प्राधिकारी ने आई बी आई एस स्रोत से आयातों के सौदावार आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा की जांच की है:

मात्रा : मी.ट. में

अवधि	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
देश				
चीन जन.गण.	551	687	1123	1313
प्रवृत्ति	100	125	204	238

जापान	1057	564	992	957
प्रवृत्ति	100	53	94	91
अन्य	812	1059	1318	1281
प्रवृत्ति	100	130	162	158
कुल	2420	2310	3433	3551
प्रवृत्ति	100	95	142	147
संबद्ध देशों का हिस्सा (%)	66	54	62	64
प्रवृत्ति	100	82	94	97

120. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि चीन जन.गण. से हुए आयातों की मात्रा में समग्र रूप से लगातार वृद्धि हुई है जो 2005-06 के दौरान 551 मी.ट. से बढ़कर 2008-09 (जांच अवधि) के दौरान 1313 मी.ट. हो गए हैं। जापान के मामले में आयात मात्रा में 2005-06 के दौरान 1057 मी.ट. से 2006-07 के दौरान 564 मी.ट. तक की भारी गिरावट आई है और तत्पश्चात 2007-08 के दौरान इनमें 992 मी.ट. तक की भारी वृद्धि हुई है और 2008-09 के दौरान ये मामूली रूप से घटकर 957 मी.ट. हो गए थे। कुल आयातों में संबद्ध देशों का हिस्सा वर्ष 2005-06 तथा 2007-08 की तुलना में जांच अवधि के दौरान लगभग समान स्तर पर रहा है।

## त.2. मांग, उत्पादन तथा बाजार हिस्सा

### त.2.1. मांग में वृद्धि

	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
मांग का निर्धारण					
➤ चीन से आयात	मी.ट.	551	687	1123	1313
➤ जापान से आयात	मी.ट.	1057	564	992	957
➤ संबद्ध देश	मी.ट.	1608	1251	2115	2270
➤ अन्य देशों से आयात	मी.ट.	812	1059	1318	1281
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	-	-	909	1421
मांग निर्धारण	मी.ट.	2420	2310	4342	4972

121. यद्यपि, घरेलू उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू हुआ है, तथापि मांग का विश्लेषण वर्ष 2005-06 और 06-07 में हुए आयातों के आधार पर भी किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में संबद्ध वस्तु की मांग में वर्ष 2005-06 की तुलना में जांच अवधि के दौरान 100% से अधिक की वृद्धि हुई है और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें 15% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि समग्र रूप से मांग में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 630 मी.ट. तक की वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग का हिस्सा इसी अवधि के दौरान बढ़कर 512 मी.ट. हो गया है।

**त.2.2 मांग में बाजार हिस्सा**

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2007-08	2008-09
चीन से आयात	%	25.86	26.41
जापान से आयात	%	22.85	19.25
संबद्ध देशों से आयात	%	48.71	45.66
अन्य देशों से आयात	%	30.35	25.76
घरेलू उद्योग	%	20.94	28.58
अन्य उत्पादक	%	0	0

122. प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में चीन से हुए आयातों में मामूली वृद्धि हुई है और जापान से हुए आयातों में मामूली कमी आई है। तथापि, इस अवधि के दौरान संबद्ध देशों और अन्य देशों के आयातों का समग्र हिस्सा कम हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2007-08 में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है और इसलिए देश में नई उत्पादन सुविधा के आरंभ होने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप आयातों में थोड़ी गिरावट आना सुस्पष्ट है। तथापि, आवेदक ने बढ़ती हुई मांग में काफी अधिक बिक्रियों/बाजार हिस्से की प्रत्याशा/अनुमान (उनकी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार) लगाया था परंतु इसके विपरीत जांच अवधि के दौरान काफी कम स्तर प्राप्त हो पाया था।

**त. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग**

	इकाई	2007-08	2008-09
क्षमता	मी.ट.	3,000	3,000
उत्पादन	मी.ट.	1,061	1,343
क्षमता उपयोग	%	35.37%	44.77%
घरेलू बिक्री	मी.ट.	909	1,421
मांग	मी.ट.	4,342	4,972

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में समग्र और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में भारी मांग के बावजूद योजनागत/अनुमानित क्षमता उपयोग के स्तर से काफी कम स्तर पर प्रचालन किया है। इस प्रकार पाटन के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं कर पाया है।

**थ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

124. नियम 18 के उप नियम (2) में यथाउल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की

तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी मात्रा में कमी करना रहा है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना रहा है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती।

125. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देशों से हुए आयातों की पहुंच लागत के साथ की गई है।

#### थ.1. विचाराधीन अवधि के दौरान कीमत का मूल्यांकन

	इकाई	2007-08	2008-09
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94
बिक्री कीमत (एनएसआर)	रु./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागतों में \*\*\* तक की गिरावट आई है। इसी प्रकार संगत अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत में भी \*\*\* तक की कमी आई है।

#### थ.2. कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव

	इकाई	2007-08	2008-09
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	***	***
पहुंच कीमत			
जापान	रु./किग्रा.	***	***
चीन जन.गण.	रु./किग्रा.	***	***
कुल संबद्ध देश	रु./किग्रा.	***	***
कीमत कटौती			
जापान	रु./किग्रा.	-	***
चीन जन.गण.	रु./किग्रा.	-	***
कुल संबद्ध देश	रु./किग्रा.	-	***
कीमत कटौती (%)			
जापान	%	-	10-20
चीन जन.गण.	%	-	1 - 10
कुल संबद्ध देश	%	-	5 - 15
क्षति रहित कीमत	रु./किग्रा.	-	***
कम कीमत पर बिक्री			
जापान	रु./किग्रा.	-	***



चीन जन.गण.	रु./किग्रा.	-	***
कुल संबद्ध देश	रु./किग्रा.	-	***
कम कीमत पर बिक्री (%)			
जापान	%	-	50 - 60
चीन जन.गण.	%	-	40 - 50
कुल संबद्ध देश	%	-	45 - 55

127. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति ज्ञात करते समय घरेलू उद्योग द्वारा दी गई रिबेटों, छूटों और कमीशनों तथा प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को घटाया गया है। कीमत कटौती का निर्धारण संपूर्ण जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ करके किया गया है। चीन जन.गण. और जापान के लिए कीमत कटौती का निर्धारण अलग-अलग किया गया है और संबद्ध देशों के लिए समग्र रूप से इस प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य का परिकलन संबद्ध देशों से आयात कीमतों के आई बी आई एस आंकड़ों में बताए गए मूल्य में 1% पहुंच प्रभार और लागू मूल सीमा शुल्क को जोड़कर किया गया है। चीन जन.गण. और जापान से कीमत कटौती क्रमशः \*\*\* % और \*\*\* % के रूप में निर्धारित की गई है और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संचयी कीमत कटौती \*\*\* % के रूप में निर्धारित की गई है।

128. कम कीमत पर बिक्री के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है। चीन जन.गण. और जापान से कम कीमत पर बिक्री \*\*\* % और \*\*\* % के रूप में निर्धारित की गई है और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कम कीमत पर की गई संचयी बिक्री \*\*\* % के रूप में निर्धारित की गई है।

129. संबद्ध देशों की मात्रा और आयात कीमत के उतार चढ़ाव का विश्लेषण वर्ष 2005-06 और उसके बाद के वर्षों के लिए निम्नांकित तालिका में किया गया है:

आयात की मात्रा	इकाई	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
चीन	मी.ट.	551	687	1123	1313
जापान	मी.ट.	1056	564	991	957
औसत आयात कीमत					
चीन	रु./किग्रा.	***	***	***	***
जापान	रु./किग्रा.	***	***	***	***
घरेलू निवल बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	---	---	***	***

130. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से निर्यात कीमत वर्ष 2005-06 के दौरान \*\*\* रूपए प्रति किग्रा. रही थी और वर्ष 2006-07 के दौरान यह घटकर \*\*\* रूपए प्रति किग्रा. रह गई थी और वर्ष 2007-08 के दौरान यह और घटकर \*\*\* रूपए प्रति किग्रा. रह गई थी। इसी प्रकार जापान से निर्यात कीमतें वर्ष 2005-06 के दौरान \*\*\* रूपए प्रति किग्रा. रह गई थी और वर्ष 2006-07 के दौरान इनमें \*\*\* रूपए प्रति किग्रा. तक की मामूली वृद्धि हुई थी, वर्ष 2006-07 के दौरान ये तेजी से घटकर \*\*\* रूपए रह गई थी और

जांच अवधि के दौरान ये पुनः मामूली रूप से बढ़कर \*\*\* रूपए प्रति किग्रा. हो गई थी। यह स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 के दौरान दोनों संबद्ध देशों ने अपनी कीमतें तेजी से घटाई हैं जब घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। संबद्ध देशों के ऐसे हतोत्साहजनक बाजारी व्यवहार के बावजूद चूंकि घरेलू उद्योग आयात कीमतों से अधिक कीमतें प्राप्त करने में सक्षम रहा था, इसलिए जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी थीं। फिर भी घरेलू उद्योग को इनसे क्षति हुई थी।

### थ.3. पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत हासकारी प्रभाव:

131. पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत हास संबंधी प्रभाव की जांच उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य के संदर्भ में भी की गई थी। कीमत न्यूनीकरण तब मौजूद होता है जब उद्योग की कीमतें पूर्ववर्ती अवधि के स्तर से कम रही हों। कीमत हास तब पाया जाता है, जब पाटन के कारण ऐसी कीमत वृद्धि नहीं हो पाती है जो अन्यथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हो गई होती।

विवरण	इकाई	2007-08	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96
पहुंच कीमत	रु./किग्रा.		
जापान	रु./किग्रा.	***	***
चीन जन.गण.	रु./किग्रा.	***	***
संबद्ध देश	रु./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117

132. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कीमत हास मौजूद है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत जांच अवधि के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की कीमत से कम रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री लागतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी अधिक रही हैं। अपने प्रचालन का दूसरा वर्ष होने के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतें पाटित आयातों के कारण उसकी उत्पादन लागत से भी काफी कम स्तर पर रही हैं। यद्यपि, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट आई है परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से इसका काफी अधिक रहना जारी है और अपेक्षाकृत सस्ते आयात के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत के स्तर को भी प्राप्त नहीं कर सका था। उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक ओर अपनी बिक्री लागतों को प्राप्त नहीं कर सका है और दूसरी ओर पाटित आयातों के कारण संबद्ध देश के निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम नहीं रहा है।

### द. क्षति संबंधी अन्य मापदंडों की जांच

133. घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमतों तथा आयातों की मात्रा और मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा विभिन्न खंडों के बाजार हिस्से के साथ मांग की प्रवृत्ति जैसे प्रमुख क्षति संबंधी संकेतकों की पूर्ववर्ती खंड में जांच करने के बाद अन्य आर्थिक मापदंडों जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी का संकेत मिल सकता है, का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :

**द.1. लाभ और नकद प्रवाह पर कीमत के वास्तविक और संभावित प्रभाव**

	इकाई	2007-08	2008-09
बिक्री की लागत	रू./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94
बिक्री कीमत (एनएसआर)	रू./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96
लाभ/हानि	रू./किग्रा.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-91
लाभ/कर पूर्व हानि	लाख रुपए	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-142
पी बी आई टी	लाख रुपए	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-150
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-183

134. उक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान \*\*\* % की गिरावट आई है। जबकि जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में \*\*\* % की गिरावट आई है। यद्यपि, जांच अवधि के दौरान प्रति इकाई घाटे में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कमी आई है, परंतु जांच अवधि में घरेलू उद्योग को भारी घाटा होना जारी रहा है।

**द.2. निवेश पर आय तथा पूंजी जुटाने की क्षमता**

	इकाई	2007-08	2008-09
पी बी आई टी	लाख रुपए	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-150
निवल स्थायी परिसंपत्ति	लाख रुपए	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96
कार्यशील पूंजी	लाख रुपए	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62
लगाई गई पूंजी	लाख रुपए	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92
लगाई गई पूंजी पर आय (एन एफ ए आधार)	%	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-162

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों के लिए नियोजित पूंजी पर आय में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारी कमी हुई है और जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं से ऋणात्मक आय प्राप्त हुई थी।

**द.3 उत्पादकता**

	इकाई	2007-08	2008-09
उत्पादन	मी.ट.	1,061	1,343
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./सं.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113

136. प्रति कर्मचारी उत्पादन संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 13% की वृद्धि हुई है ।

**द.4 रोजगार तथा मजदूरी**

	इकाई	2007-08	2008-09
रोजगार (जन शक्ति)	सं.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113
मजदूरी	लाख रुपए	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111

137. रोजगार के स्तर और मजदूरी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । ऐसा इस तथ्य के कारण भी हो सकता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2007-08 के दौरान ही संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है। भारी घाटा उठाने के बावजूद घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान मजदूरी में \*\*\*% की वृद्धि करने में सक्षम रहा है ।

**द.5 मालसूची**

मालसूची	इकाई	2007-08	2008-09
औसत	मी.ट.	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची वर्ष 2007-08 के दौरान 255 मी.ट. से घटकर जांच अवधि के दौरान 166 मी.ट. रह गई है । सूचीबद्ध रूप में औसत मालसूची वर्ष 2007-08 के दौरान 100 से घटकर जांच अवधि के दौरान 64 रह गई है ।

**द.6. वृद्धि**

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन और घरेलू बिक्रीयों में वृद्धि, क्षमता उपयोग में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, प्रति इकाई घाटे में कमी और अंतिम माल सूची में कमी की दृष्टि से

सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। तथापि, ऐसे सकारात्मक वृद्धि संबंधी संकेतकों के बावजूद घरेलू उद्योग को कम बिक्री कीमत के कारण भारी घाटा होना जारी है।

#### द.7. नया निवेश जुटाने की क्षमता

140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं किया है और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोई नया निवेश नहीं किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने हाल ही में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

#### द.8 पाटन की मात्रा

141. उस सीमा के एक संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा जहां तक पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, दर्शाती है कि जांच अवधि के लिए संबद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक रहा है।

#### द.9. कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

142. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में संबद्ध आयात की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती। घरेलू बाजार पर आयातों के प्रभाव का आकलन करने की दृष्टि से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों का विश्लेषण किया है। यह पाया गया था कि जांच अवधि में प्रति कि.ग्रा. पहुंच मूल्य दोनों संबद्ध देशों के संबंध में आर-134 ए की निवल बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत, दोनों से कम रहा था। घरेलू उद्योग और प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण लागत संरचना में परिवर्तन यदि कोई हो, की जांच उन कारकों के विश्लेषण हेतु की गई है, जिनसे घरेलू बाजार में कीमतें प्रभावित होने की संभावना थी। उत्पादन लागत में जांच अवधि के दौरान \*\*\*% की गिरावट आई है जबकि इसी अवधि के दौरान निवल बिक्री कीमत में \*\*\*% तक की गिरावट आई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपने प्रचालनों का दूसरा वर्ष होने के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतें उसकी उत्पादन लागत के स्तर से काफी कम स्तर पर रही हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत कटौती हुई है। जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती 2-12% के बीच रही थी और जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री 40-50% के बीच रही थी।

#### घ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

143. संबंधित कारकों के उपर्युक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि समग्र रूप से उत्पादन और बिक्रियों में सुधार होने, क्षमता उपयोग में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, प्रति इकाई घाटे में कमी, बाजार हिस्से में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत में कमी के कारण भारी घाटा उठाना पड़ा है क्योंकि उस दौरान बिक्री लागत काफी अधिक रही थी और संबद्ध देशों से पाटन हुआ था।

144. संबद्ध देशों से हुए आयात अपनी पर्याप्त मौजूदगी बनाए हुए हैं और इनसे कीमत पर काफी प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप कम कीमत पर बिक्री, कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण हुआ है।

145. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

### न. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

146. हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित के मद्देनजर कारणात्मक संबंध के अभाव के पक्ष में ये तर्क दिए हैं:-

- (क) माँग में वृद्धि के बावजूद खपत की पद्धति में परिवर्तन होने से घरेलू उद्योग अति उच्च लागत संरचना के कारण आर 134ए की बिक्री में लाभ नहीं कमा सका ।
- (ख) अनुमानित निर्यात लक्ष्य की तुलना में किए गए कम निर्यात की एकमात्र वजह से घरेलू उद्योग को वर्ष 2008-09 के दौरान घाटा हुआ है ।
- (ग) एसआरएफ अत्यंत कम कीमतों की पेशकश कर रही है, प्रयोक्ता भी निर्यातकों पर एसआरएफ की कीमत के बराबर कीमतें रखने के लिए दबाव डाल रहे हैं ।
- (घ) घरेलू उद्योग को हुई क्षति और चीन से हुए आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।
- (ङ.) वैश्विक मंदी बिक्री कीमत में गिरावट, तैयार उत्पादों की मांग में कमी और उत्पादन तथा बिक्री मात्रा में गिरावट का प्रमुख कारण है ।

### घरेलू उद्योग के विचार

147. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उल्लिखित याचिका, प्रारंभिक जांच परिणाम और लिखित अनुरोधों पर भरोसा किया गया है जिससे पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की स्पष्ट पुष्टि होती है ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

148. वास्तविक क्षति की मौजूदगी और घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रासकारी प्रभावों की दृष्टि से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच करने के बाद, भारतीय नियम और पाटनरोधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मापदंडों की भी जांच की गई है ताकि यह देखा जा सके कि क्या पाटित आयातों के अलावा ऐसा कोई अन्य कारक है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो । इस संबंध में निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है ।

### न.1 अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमत

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, अन्य देशों से भी आयात हुए हैं, परंतु ये आयात संबद्ध देशों से हुए आयातों की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर हुए हैं ।

रू./किग्रा.	2007-08	2008-09
आयात कीमत		
चीन	***	***
जापान	***	***
तीसरा देश	***	***
अंतर	83.38%	57.88%

## न.2 मांग में कमी और/या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

150. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। वस्तुतः मांग में भारी सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इस प्रकार मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पादों के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत की प्रवृत्ति में हुए परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क क्षति मापदंडों में प्रदर्शित प्रवृत्ति के अनुसार स्वीकार्य नहीं है कि बिक्री कीमत में गिरावट, तैयार उत्पाद की बिक्री में कमी और उत्पादन तथा बिक्री मात्रा में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक मंदी है।

## न.3 व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के लिए ऐसा एक ही बाजार है जहां संबद्ध देशों के पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातित उत्पाद की बिक्री घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के समान वाणिज्यिक ग्रेडों और विनिर्देशनों की मांग को पूरा करने के लिए की जाती है और यह कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं और इनका उपयोग समान अनुप्रयोगों/अंतिम उपयोग में किया जाता है।

152. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग में ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया प्रचलित नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

## न.4 प्रौद्योगिकी का विकास

153. याचिकाकर्ता के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर प्राधिकारी का मानना है कि प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक संगत कारक नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग तथा चीन जन.गण. के निर्यातक उत्पादन की समान प्रक्रिया अपनाते हैं और जापान से कोई उत्तर नहीं मिला है।

## न.5 निर्यात निष्पादन

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता अपने उत्पादन के एक हिस्से का निर्यात भी करता है और वर्ष 2007-08 के दौरान निर्यातों में 4 मी.ट. से जांच अवधि के दौरान 87 मी.ट. तक की वृद्धि हुई है परंतु निर्यातित सामग्री की मात्रा जांच अवधि में घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का काफी कम

हिस्सा अर्थात् केवल 6.4% रही है। इस प्रकार प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती है।

#### न.6. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

155. प्रति कर्मचारी उत्पादन की दृष्टि से घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार प्रदर्शित हुआ है।
156. ऐसा कोई अन्य कारक, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना हो सकती हो, प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया है।

#### प. क्षति मार्जिन की मात्रा

157. क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। संबद्ध देशों से निर्यातों की पहुंच कीमत और क्षति मार्जिन निम्नानुसार ज्ञात किए गए हैं:

#### प.1. क्षति मार्जिन संबंधी गणनाएं

उत्पादक	निर्यातक	क्षति मार्जिन (अम.डॉ.)	क्षति मार्जिन (%)
<b>चीन जन.गण.</b>			
सिनोचैम इन्वार्नमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (ताईकांग) कं. लि.	सिनोचैम इन्वार्नमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (ताईकांग) कं. लि.	***	40-50
सिनोचैम इन्वार्नमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (ताईकांग) कं. लि.	दू प्वाइंट ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि.	***	45-55
सिनोचैम मॉर्डन इन्वार्नमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (जियान) कं.लि.	सिनोचैम मॉर्डन इन्वार्नमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (जियान) कं.लि.	***	30-40
कोई	कोई	***	45-55
<b>जापान</b>		***	
कोई	कोई	***	50-60

#### फ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

158. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता अब भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।
159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं



उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

## ब. निष्कर्ष

160. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

- क. भारत को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;
- ख. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से हुए आयात के कारण वास्तविक क्षति हुई है;
- ग. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन काफी अधिक एवं न्यूनतम सीमा से ज्यादा है।

## भ. सिफारिशें

161. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उसकी सूचना दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। निर्धारित पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटन और क्षति एवं पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच शुरू और पूर्ण करने के बाद तथा संबद्ध देशों के विरुद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति निर्धारित करने के बाद यह आवश्यक समझते हैं और आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तारीख से निम्नानुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

162. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है :

**शुल्क तालिका**

क्र.सं.	टैरिफ मद का उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	माप की इकाई	युग्म
1	2.	3.	4.	5	6.	7.	8	9	10.
1	29033919	1.1.1.2-टेट्राफ्लोरोईथेन या आर-134ए	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	सिनोचैम इन्वायर्नमेंटल प्रोटेक्शन (ताईकांग) कं. लि.	सिनोचैम इन्वायर्नमेंटल प्रोटेक्शन (ताईकांग) कं. लि.	1.15	किग्रा.	अम.डॉ.

2	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	सिनोचैम इन्वायर्नमेंटल प्रोटेक्शन (ताईकांग) कं. लि.	दू प्वाइट ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि.	1.36	किग्रा.	अम.डॉ.
3	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	सिनोचैम इन्वायर्नमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (जियान) कं.लि.	सिनोचैम इन्वायर्नमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (जियान) कं.लि.	1.15	किग्रा.	अम.डॉ.
4	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कं.सं. 1 से 3 के उत्पादक तथा निर्यातक से इतर अन्य कोई संयोजन		1.41	किग्रा.	अम.डॉ.
5	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1.41	किग्रा.	अम.डॉ.
6	- वही -	- वही -	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	1.41	किग्रा.	अम.डॉ.
7	- वही -	1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन या आर-134ए	जापान	जापान	कोई	कोई	0.69	किग्रा.	अम.डॉ.
8	- वही -	- वही -	जापान	कोई	कोई	कोई	0.69	किग्रा.	अम.डॉ.
9	- वही -	- वही -	जापान को छोड़कर कोई अन्य देश	Japan	कोई	कोई	0.69	किग्रा.	अम.डॉ.

163. केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इस जांच परिणाम के खिलाफ कोई अपील वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ नियम, 1995 के अनुसार (सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) में दायर की जा सकेगी।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th May, 2011

**Final Findings**

**Subject : Anti-Dumping Investigations concerning imports of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a of all types originating in or exported from China PR and Japan.**

**F. No. 14/24/2009-DGAD.—**Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof;

**A. Background Of The Case:**

The background of the case is as follows:

1. Whereas M/s SRF Ltd, Gurgaon (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Act and the Rules alleging dumping of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a of all types (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR and Japan (hereinafter referred to as the subject countries) and requested for initiation of anti-dumping investigation for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries,
2. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence, submitted by the applicant issued a Public Notice dated 19th August, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in accordance with the sub Rule 5(5) of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

3. The anti-dumping investigation concerning imports of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a of all types, originating in or exported from China PR and Japan, was initiated by the Authority vide Notification No. 14/24/2009-DGAD dated 19th August, 2009 on the basis of an application made by M/s SRF Ltd, having its office at Block C-8, Sector 45, Gurgaon, Haryana and factory at Bhiwadi, Tehsil Tijara, Alwar, Rajasthan, the sole producer of the subject goods in India.
4. After verifying the domestic industry's data and after examining the responses submitted by the cooperating producers/exporters from the subject countries and the cooperating importers of the subject goods in India, preliminary finding was issued by the Designated Authority vide Notification No. 14/24/2009-DGAD dated 19th February, 2010, recommending provisional duties against imports of the subject goods from the subject countries.
5. The recommendation of the Designated Authority vide the Preliminary Finding for imposition of provisional duty was accepted by the Central Government and the Revenue Department notified the imposition of the provisional anti-dumping duty vide Notification No. 52/2010-Customs dated 19th April, 2010.
6. The public hearing (oral hearing) as per Rules was convened by the Designated Authority on 10th May, 2010 by inviting the known interested parties for oral hearing.
7. M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai filed a writ petition vide WPC No.6952 of 2010 before the Hon'ble High Court of Madras and challenged the initiation of the investigation and the preliminary finding of the Authority. The Hon'ble High Court of Madras directed the Petitioner to attend the oral hearing scheduled by the Authority and directed the Authority to give an opportunity of personal hearing to the Petitioner.
8. Pursuant to the orders of the Hon'ble High Court of Madras, the Designated Authority heard the petitioner personally on 10th May, 2010 immediately after the oral hearing of the interested parties and passed a speaking order vide No.18/8/2019-DGAD dated 21st May, 2010.
9. M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai filed another writ petition vide WPC No. 8901 of 2010 before the Hon'ble High Court of Madras and obtained interim stay on the Customs Notification No. 52/2010 dated 19th April, 2010.
10. M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai filed another writ petition vide WPC No. 10709 of 2010 before the Hon'ble High Court of Madras and obtained interim stay on the proceedings of the subject investigation including the concerned Customs Notification that notified the provisional duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

11. M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai filed another writ petition vide WPC No. 10710 of 2010 before the Hon'ble High Court of Madras. The said writ petition was dismissed as withdrawn by the Hon'ble High Court vide order dated 12th May, 2010.
12. Another Mumbai based importer, M/s Stallion Enterprises, filed a writ petition before the Hon'ble High Court of Bombay against the initiation of the subject investigation and the preliminary findings of the Authority. The writ petition was dismissed by the Hon'ble High Court of Bombay vide order dated 15<sup>th</sup> June, 2010 .
13. Another Chennai based importer, M/s Hawwa Exims, filed a writ petition before the Hon'ble High Court of Madras vide WPC No. 13438 of 2010. The Hon'ble High Court of Madras granted interim stay vide order dated 25th June, 2010.
14. Another Chennai based importer, M/s Value Refrigerants Pvt Ltd, filed a writ petition vide WPC No. 15826 of 2010. The Hon'ble High Court of Madras granted interim stay vide order dated 21st July, 2010 in this case as well.
15. The Domestic Industry filed Writ Appeals No. 1237 and 1238 before the Hon'ble High Court of Madras. The counter affidavits and the stay vacation petitions filed by the Designated Authority before the Hon'ble High Court of Madras were tagged up with the Writ Appeals of the Domestic Industry before the Hon'ble Division Bench of Madras High Court. The Hon'ble Division Bench heard the matters in its final hearing on 16th August, 2010 and reserved the order.
16. SLP was filed by the Domestic Industry, before the Hon'ble Supreme Court, against the interim stay orders granted by the Hon'ble Madras High Court. The Hon'ble Supreme Court vide order dated 13<sup>th</sup> December, 2010 directed Hon'ble High Court of Madras to expeditiously issue the reserved judgment within 4 weeks:

*Heard learned counsel on both sides. We request the High Court to expeditiously deliver the judgment in the pending Writ Appeal Nos.1237 of 2010 and 1238 of 2010 and Writ Petition Nos.8901 of 2010 and 10709 of 2010. This order has become necessary in view of the fact that the cut-off date is 18th February, 2011, in respect of final findings on Anti Dumping Duty. We request the High Court to deliver this judgment, preferably within a period of four weeks from today. The special leave petitions are, accordingly, disposed of.*

17. On 6th January, 2011, Hon'ble Division Bench of Madras High Court passed the following Judgment:

*"17. Therefore, without going into various aspects urged and argued on either side in view of the further fact that serious disputed questions of fact regarding the stature of the complainant, which will have the impact of cutting the root, are involved in the matter, we set aside the orders dated 19.4.2010 and 21.5.2010 passed by the third respondent and direct the first respondent/Government of India to appoint/nominate another officer in the place of the third respondent, to*

*act as a Designated Authority for this case, within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this order. The officer so appointed/nominated is directed to conduct enquiry by scrupulously following the law governing the subject, viz. the Customs (Tariff) Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on dumped articles and for determination of Injury) Rules, 1995 and pass orders within six weeks thereafter. Till that time, the preliminary report dated 19.2.2010 shall not be given effect to. With this direction, all these matters are disposed of. No costs. Connected Miscellaneous Petitions are closed."*

18. SLP filed by the Authority against the interim stay orders granted by the Hon'ble Madras High Court vide No.18447-18449 of 2010 came up for hearing on 14.01.2011 and the same was disposed of as infructuous.

19. The Designated Authority again filed SLP against the final judgment dated 06.01.2011 of the Hon'ble Division Bench of Madras High Court vide No.1913-1916. The same was finally heard by the Hon'ble Supreme Court on 03.02.2011 and disposed of as follows:

*" We have heard the learned Additional Solicitor General and the learned senior counsel for the parties at length.*

*In our considered view, no interference is called for. The special leave petitions are dismissed."*

20. In compliance with the Orders dated 6<sup>th</sup> January, 2011 of the Hon'ble Division Bench of Madras High Court and pursuant to the orders dated 3<sup>rd</sup> February, 2011 of the Hon'ble Supreme Court, the new Designated Authority was appointed by the Central Government in term of Rule 3 of the Rules with effect from 14<sup>th</sup> February, 2011. The Designated Authority so appointed, filed a writ application before the Hon'ble High Court of Madras, praying for extension of time granted by them vide their judgment dated 06.01.2011, for completing the subject investigation.

21. Another oral hearing was given by the new Designated Authority to the known interested parties on 1<sup>st</sup> March, 2011 and the interested parties were given opportunity of being heard and file their submissions.

22. The Hon'ble High Court of Madras, vide orders dated 25<sup>th</sup> March, 2011, disposed of the WP No. 15826 of 2010 and MP No. 1 and 2 of 2010 in M/s Value Refrigerants Pvt Ltd vs Union of India with a similar judgment as passed by the Hon'ble Division Bench in the WA No. 1237 of 2010 and batch cases 06.01.2011 in the SRF Ltd vs Refex Refrigerants Ltd.

23. The Hon'ble Madras High Court vide its order dated 30<sup>th</sup> March, 2011 in the Misc. Petition Nos. 1 and 1 of 2011 in Writ appeals No. 1237 of 2010 made the following order:

*" In view of the dismissal of SLP. Nos. 1913 to 1916 of 2011 by the Hon'ble Apex Court by order dated 3.2.2011, it is submitted that the New designated authority has been appointed on 14.2.2011.*

Accordingly, though it is not feasible to grant a period of six months time as requested by the petitioners herein.

We consider it appropriate to grant a period of six weeks from today to complete the investigation.

M.P.Nos. 1&1 of 2011 are disposed of accordingly."

Further, M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai had challenged the aforesaid orders dated 30<sup>th</sup> March, 2011 of the Hon'ble High Court of Madras, before the Hon'ble Supreme Court of India, vide their SLP(c) CC No. 7520-7523/2011. The Hon'ble Supreme Court heard the SLP on 9<sup>th</sup> May, 2011 and dismissed the SLP as withdrawn.

24. As per Rule 17 of the Anti-dumping Rules, the Designated Authority shall, within one year from the date of initiation of an investigation, submit to the Central Government its final finding, although the Central Government may, in its discretion in special circumstances, extend further the aforesaid period of one year by six months. Therefore the maximum time period available under the Rules for completing an investigation is 18 months from the date of initiation of investigation. The above provisions of the Anti-dumping Rules are clearly in line with Article 5.10 of the WTO Agreement which reads as follows:

"Investigations shall, except in special circumstances, be concluded within one year and in no case more than 18 months, after their initiation".

25. Due to the stay orders granted by the Hon'ble Madras High Court, the Authority could not complete the subject investigation within the time frame stipulated under the Anti-dumping Rules and WTO Agreement. However, pursuant to and in compliance with the orders dated 6th January, 2011 of the Hon'ble Division Bench of the Madras High Court, orders dated 3rd February, 2011 of the Hon'ble Supreme Court and orders dated 30<sup>th</sup> March, 2011 of the Hon'ble Division Bench of the Madras High Court, the subject investigation has been continued by the Authority beyond the maximum time limit prescribed under the WTO Agreement and the Anti-dumping Rules.

## **B. PROCEDURE**

26. The procedure described below has been followed with regard to this investigation after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:
- i. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the anti-dumping investigation in accordance with the sub-rule (5) of Rule 5 supra;
  - ii. The Designated Authority sent copies of the initiation notifications dated 19<sup>th</sup> August, 2009 to the embassies of the subject countries in India, known exporters

from the subject countries, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it. The known interested parties to this investigation were requested to file questionnaire response and make their views known in writing within prescribed time limit. Copies of the letter, petition and questionnaire sent to the exporter were also sent to the Embassies of the subject countries along with a list of known exporters/ producers with the request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.

- iii. Copy of the non-confidential version of the application filed by the domestic industry was made available to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra.
- iv. Questionnaires were sent to the known exporters from subject countries in accordance with Rule 6(4) to elicit relevant information. Whereas no response has been received from Japan, responses to exporter's questionnaire and MET questionnaire have been received from the following exporters of the subject goods from China PR :
  - a) Zhejiang Juhua Co. Ltd., Kecheng District, Quzhou City, Zhejiang Province, China PR – 324004
  - b) Zhejiang Quhuaflour – Chemistry Co., Ltd., Juhua Group, Kecheng District, Quzhou City, Zhejiang Province
  - c) Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd., 18, South of Binjiang Road, Shihua Industrial Park, Taicang Port, , Jiangsu Province, China PR – 215433.
  - d) Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co. Ltd., Jinghe Industrial Area, Xian Economic-Technological Development Zone, Xian, China PR.
  - e) DuPont Trading (Shanghai) Co. Ltd., 10/F Building # 11, 399 Keyuan Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong New District, Shanghai – 201203, China PR.
  - f) M/s Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co Ltd., 2<sup>nd</sup> Floor, No. 243, Juhua Centre Road, Quzhou China.
- v. Post initiation views/comments were also received from the China Association of Flourine & Silicon Industry.



- vi. Questionnaires were sent to the known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) and response to the importers questionnaire has been received from the following importers of the subject goods in India;
- a) Navine Fluorine International Ltd., 35-C, Shivaji Marg, New Delhi - 110015
- b) E.I. DuPont India Private Limited, DLF Cyber Greens, 7th Floor, - 'C' Tower 25A – DLF City, Phase III Gurgaon 122002, Haryana.
- vii. Post initiation, views/comments were also received from the importers/users of the subject goods viz; M/s Refex Refrigerants Ltd , M/s Chennai Marine Trading Pvt Ltd and M/s Honeywell International Pvt Ltd . The submissions made by them has been considered in this finding.
- viii. Post Preliminary Findings M/s Amarchand & Mangaldas and Suresh A. Shroff & Co has submitted request for condonation of delay for submission of exporters questionnaire response on behalf of M/s Mexichem Fluor Japan Ltd, Japan vide their letter dated 2<sup>nd</sup> June, 2010. In support of their request for condonation of delay they have stated that M/s Mexichem Fluor Japan SA de CV is a Mexican company that has taken over M/s INEOS Fluor Japan Ltd, Japan, (a subsidiary of M/s INEOS U K, a UK based company, which produced the Refrigerant HFC-R-134a), on March 31, 2010, after the preliminary finding was issued. They have argued that the PF was given on 19<sup>th</sup> February, 2010 and they have taken over the Japanese company on 31<sup>st</sup> March, 2010 and in view of that they could not have responded to the initiation of the investigation by the Authority on 19<sup>th</sup> August, 2009. They have informed that they could know about the subject investigation only after taking over the said company, world-wide, including their Japan based company. However, the investigation initiation notification was sent to M/s Mitsui Dupont Fluorochemicals Co Ltd, known producer/exporter in Japan as declared by the domestic industry in their application, and also to the Japanese embassy in India. But, no response was received from any producer/exporter from Japan. In view of the above and undue delay in filing the request for condonation of delay by M/s Amarchand & Mangaldas and Suresh A. Shroff & Co on behalf of M/s Mexichem Fluor Japan Ltd, Japan, the Authority did not accept the request for condonation of delay for filing the exporter's questionnaire response by M/s Mexichem Fluor Japan Ltd, Japan. However, the submissions made by the interested party have been considered in this finding.
- ix. Similarly, post preliminary findings, M/s Lakshmi Kumaran & Sridharan has requested for condonation of delay for filling the exporters questionnaire response on behalf of M/s Honeywell Fluorine Products Europe BV, Larderhoogtweg, Amsterdam, Netherland vide their letter dated 30<sup>th</sup> April, 2010. They have argued that Honeywell Europe was not aware of the subject investigation earlier and no sooner they came to know about the subject investigation, they have approached the Authority. However, the plea of M/s Honeywell Fluorine Products Europe BV that they were not aware of the subject investigation earlier does not sound convincing since M/s Zhejiang Quhua Fluor Co Ltd, China PR and M/s Sinochem

Environmental Protection Chemicals (Taikang) Co Ltd, China PR, from whom they have procured the subject goods and exported to India, have submitted questionnaire responses in the subject investigation. In view of the above and due to undue delay in filing the request, the Authority did not accept the request for condonation of delay for filing the exporter's questionnaire response by M/s Honeywell Fluorine Products Europe BV, Larderhoogtweg, Amsterdam, Netherland. However, the submissions made by the interested party have been considered in this finding.

- x. Post Preliminary Findings M/s Stallion Enterprises, Mumbai submitted importer's questionnaire response, the same being belated was not accepted by the Authority. However the relevant information and submissions made by M/s Stallion Enterprises, Mumbai have been considered in this finding.
- xi. Submission was also furnished by the China Association of Flourine & Silicone Industry and the same have been considered in this finding.
- xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xiii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the injury period including the period of investigation.
- xiv. The Non-Injurious Price based on the cost of production on the basis of the accounting information furnished by the petitioner on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lesser than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- xv. The Authority initiated the investigation with Non-Market Economy (NME) presumption in respect of People's Republic of China in terms of Para 8 of Annexure I to the Rules and provided an opportunity to the country concerned and the exporters from People's Republic of China to rebut the said presumption under the said Rule. It was also mentioned in the said notification that the Authority may however, notify an appropriate third country, in the due course, for the purpose of determination of normal value in China PR in terms of para 7 of Annexure I to the Rules. However, none of the interested parties, including the applicants, have placed any material fact before the Authority to select an appropriate market economy third country for the above purpose.
- xvi. As per the practice adopted by the DGAD, the injury period covers POI and preceding three years. The period of investigation in the subject case is starting from 1st April 2008 to 31st March 2009 (12 months). However, in the subject case the injury investigation period covers the period 2007-08 and the POI, as the applicant has started commercial production in the year 2007-08 only.

- xvii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all the known interested parties to present their views orally in oral hearing held on 10th May, 2010 and 1<sup>st</sup> March, 2011. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally.
- xviii. The submissions made by the interested parties post prior to notification of the preliminary findings and the submissions made in response to the preliminary findings and arguments made in the written submissions/ rejoinders received from the known interested parties after the both the oral hearings and issues raised by interested parties in response to the disclosure statement and also before various courts have been considered, wherever found relevant, in this finding.
- xix. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry and the cooperative respondent producers/exporters in China PR. Since no response was received from Japan, no verification was conducted.
- xx. The disclosure statement was issued by the Authority disclosing the essential facts of the investigation to the interested parties. Comments were received from the following interested parties:
- a) M/s A.K.Gupta, TPM Consultants, on behalf of M/s SRF Ltd, the Domestic Industry,
  - b) M/s Lakshmi Kumaran & Sridharan on behalf of M/s Du Pont Trading(Shanghai) Co Ltd, China PR, El Dupont India Pvt Ltd, India and M/s Honeywell Florine Products Europe BV,
  - c) M/s Amarchand Mangaldas & Suresh A. Shroff & Co on behalf of M/s Mexichem Fluor, Japan Ltd, Japan,
  - d) M/s Seth Associates Advocates & Legal Consultants on behalf of M/s Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xian) Co Ltd and M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taikang) Co Ltd .

No other interested parties including those who had filed cases before various courts namely M/s Stallion Enterprises, Mumbai, Refex Refrigerants Ltd, Chennai, M/s Hawwa Exims, Chennai and M/s Value Refrigerants Pvt Ltd, Chennai have filed comments on the disclosure statement issued by the Authority. M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai vide their letter dated 9<sup>th</sup> May, 2011 requested the Authority for grant of twenty-four hours time from the date of their letter to submit comments on the disclosure statement and opportunity for making oral submissions. However, in view of the fact that adequate opportunity was granted to the interested parties by the Authority to make oral as well as written submissions and the time granted for submission of comments on the disclosure statement was 6<sup>th</sup> May, 2011, the Authority did not consider it necessary to grant any further time/opportunity to M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai for making submission.

The relevant comments/submissions received from the interested parties have been examined and addressed in this finding.

- xxi. The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated as confidential.
- xxii. The exporters, producers, importers, consumers and other interested parties who have not supplied information in this investigation have been treated as non co-operating interested parties and the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.
- xxiii. \*\*\* in this finding represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Anti-dumping Rules.
- xxiv. The exchange rate adopted for the POI is Rs. 45.72=1 US \$.

### **C. Litigation Before Various Courts**

#### **C.1 WPC No. 6952 of 2010 filed by M/S Refex Refrigerants Limited, Chennai**

27. After issuance of the preliminary findings, a Chennai based importer namely M/S Refex Refrigerants Limited, had filed a writ petition vide No. 6952 of 2010 before the Hon'ble High Court of Madras challenging initiation of the investigation and the preliminary findings issued by the Authority. The Hon'ble High Court vide their orders dated 19.04.2010 at para 6 to 9 of the order have directed as follows:

*"6. Going by the said regulation governing the investigation, the only grievance of the petitioner herein is that without adverting to the various contentions raised therein, the provisional order has been passed. It is further stated that the complainant itself is an importer of the goods. Having regard to the serious prejudice faced and in the light of the absence of any remedial provisions as against the provisional order of the respondent, it is absolutely essential that the petitioner's interest be properly considered before any demand is made on the petitioner.*

*7. I agree with the submission of the learned Advocate General that having regard to the guidelines given in the Rules and the specific request made by the petitioner in their representation seeking a personal hearing in this matter without disturbing the order, the second respondent is hereby directed to consider the objection of the petitioner in terms of the representations dated 24/09/2009 as well as 05/04/2010 by affording opportunity to the petitioner for personal hearing and pass order thereon within a period of six weeks from today. It is also made clear that the respondent shall furnish the materials which are relied on as provided for under sub clause 6 of Rule 6 of the Customs Tariff (Identification,*

***Assessment and collection of Anti-Dumping Duty on dumped Article and for determination of Injury) Rules, 1995.***

***8. Considering the above directions issued, in the meantime, the respondents are directed not to implement the order. Depending on the outcomes of the order passed, it is open to the respective parties to work out their remedies.***

***9. With the above observation, the writ petition is disposed off. No costs. Consequently, connected MPs are closed."***

28. Pursuant to the orders of the Hon'ble High Court of Madras the petitioner was granted a personal hearing by the Designated Authority at 12.30 PM in Room No. 141, Udyog Bhavan, New Delhi, immediately after the Public Hearing(oral hearing) held at 11.00 AM on 10<sup>th</sup> May, 2010 in the same venue. The representatives of the petitioner had attended the Public Hearing(oral hearing) and preferred not to make any submissions. The representatives of the petitioner also attended the personal hearing granted by the Designated Authority in terms of the orders of the Hon'ble High Court of Judicature at Madras under protest and made submissions vide their letter dated 10<sup>th</sup> May, 2010.

29. A speaking Order vide No.18/8/2019-DGAD dated 21<sup>st</sup> May, 2010 was issued by the Designated Authority in compliance with the orders dated 19.04.2010 of the Hon'ble Madras High Court in the matters of WP No. 6952 of 2010 filed by M/s. Refex Refrigerants Limited, Chennai. The speaking order dated 21.05.2010 was set aside by the Hon'ble High Court of Madras vide order dated 06.01.2011. However the submissions made by the petitioner during the personal hearing granted on 10.05.2010 have been considered in this finding.

**C.2 WPC No. 8901 of 2010 filed by M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai before Hon'ble High Court of Madras**

30. M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai had filed another WPC No. 8901 of 2010 before the Hon'ble High Court of Madras challenging the initiation of the subject investigation, the preliminary finding issued by the Authority and the Customs Notification that notified the provisional duty. The Hon'ble Bench of the Madras High Court vide order dated 5<sup>th</sup> May, 2010 in respect of WP No. 8901 of 2010 filed by M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai had directed the petitioner to participate in the public hearing scheduled by the Designated Authority on 10th May, 2010 and also directed that pending final decision by the Designated Authority in the matters the Customs Notification No 52/2010 dated 19<sup>th</sup> April 2010 shall not be given effect to in so far as the petitioner is concerned. The order of the Hon'ble Court is quoted below:

***"6. Considering the facts and circumstances of the case and submissions made by the learned senior counsel for the petitioner as well as learned standing counsel appearing for the respondents, the petitioner is directed to participate in the oral hearing scheduled on 10.05.2010 and raise all its contentions which are open to it under law and thereafter, the Designated Authority shall take a final decision in the matter. Pending such decisions, the impugned notification in No. 52/2010 – Customs, dated 19.04.2010 shall not be given effect to in so far as the petitioner is concerned. Notice."***

**C.3 WPC No. 10709 of 2010 filed by M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai before Hon'ble Bench of the High Court of Madras,**

31. The Hon'ble Bench of the Madras High Court vide order dated 12th May 2010 in respect of WP No. 10709 of 2010 filed by M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai has granted interim stay on the proceedings of the subject investigation being conducted by the DGAD, the preliminary findings issued by the Designated Authority and the provisional duties imposed by the Department of Revenue vide Customs Notification No.52/2010-Customs dated 19<sup>th</sup> April, 2010. The order of the Hon'ble Bench is quoted below:

*"Order : This petition coming on for orders upon perusing the petition and the affidavit filed in support thereof and upon hearing the arguments of M/S. SATISH PARASARAN, Advocate for the petitioner the court made the following order :-*

*Interim stay as prayed for. Notice. Private notice is also permitted.*

*Post alongwith W.P.No. 8901/2010."*

**C.4 WPC No. 10710 of 2010 filed by M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai before Hon'ble High Court of Madras,**

32. The writ petition No 10710 of 2010 filed by M/s Refex Refrigerants Ltd, Chennai was dismissed as withdrawn vide order dated 12th May, 2010 of the Hon'ble Bench of the Madras High Court.

**C.5 WPC No. 13438 filed by M/s Hawwa Exims, Chennai before Hon'ble High Court of Madras**

33. In the Writ Petition No. 13438 of 2010 filed by M/s Hawwa Exims, another Chennai based importer, vs Union of India the Hon'ble High Court of Madras vide order dated 25<sup>th</sup> June 2010 granted interim stay and passed the order as follows:

*"Order : This petition coming on for orders upon perusing the petition and the affidavit filed in support thereof and upon hearing the arguments of M/S. MOHAMED SALEEM, Advocate for the petitioner, the court made the following order :-*

*Interim stay. Notice. "*

**C.6 WPC No. 15826 of 2010 filed by M/s Value Refrigerants Pvt Ltd Chennai before Hon'ble High Court of Madras,**

34. In the Writ Petition No. 15826 of 2010 filed by M/s Value Refrigerants Pvt. Ltd., Chennai vs Union of India the Hon'ble High Court of Madras vide order dated 21<sup>st</sup> July 2010 passed the order as follows:

*"Order : These petitions coming on for orders upon perusing the petitions and the respective affidavits filed in support thereof and upon hearing the arguments of M/S. T.RAMESH, Advocate for the petitioner in both the petitions and of Mr. M. RAVIEEDRAN, Addl. Solicitor General for Mr. K. RAVICHANDRAN, Advocate taking notice for the Respondents in both the petitions the court made the following order :-*

*Mr. M.Raveendran, Addl. Solicitor General took notice for respondents.*

*In view of the fact that in similar matters, this court granted interim order in M.B. Nos. 2 & 3 of 2010 in W.P. No. 8901 of 2010, dated 5.5.2010. Though writ appeal was filed, no stay having been granted, there may be a stay of this order till the disposal of the writ appeal.*

*In view of the same, their will be an order of interim stay, till the disposal of the writ appeal nos. 1237 and 1238 of 2010, till 2.8.2010.*

*Post on 2.8.2010."*

**C.7 WPC No. 971 of 2010 filed by M/s Stallion Enterprises, Mumbai before the Hon'ble Bombay High Court**

35. M/s Stallion Enterprises, Mumbai filed the WPC No. 971 of 2010 before the Hon'ble Bombay High Court in the subject anti-dumping investigations. The petition was dismissed by the Hon'ble Divisional Bench of Mumbai High Court vide order dated 15<sup>th</sup> June 2010.

**C.8 WPC No. 13438 of 2010 filed by M/s Hawwa Exims, Chennai before the Hon'ble Madras High Court**

36. Another Chennai based importer, M/s Hawwa Exims, filed a writ petition before the Hon'ble High Court of Madras vide WPC No. 13438 of 2010. The Hon'ble High Court of Madras granted interim stay vide order dated 25th June, 2010.

**C.9 WPC No. 15826 of 2010 filed by M/s Value Refrigerants Pvt Ltd, Chennai before the Hon'ble Madras High Court**

37. Another Chennai based importer, M/s Value Refrigerants Pvt Ltd, filed a writ petition vide WPC No. 15826 of 2010. The Hon'ble High Court of Madras granted interim stay vide order dated 21st July, 2010 in this case as well.

38. The Domestic Industry filed Writ Appeals No. 1237 and 1238 before the Hon'ble High Court of Madras. The counter affidavits and the stay vacation petitions filed by the Designated Authority before the Hon'ble High Court of Madras were tagged up with the

Writ Appeals of the Domestic Industry before the Hon'ble Division Bench of Madras High Court. The Hon'ble Division Bench heard the matters in its final hearing on 16th August, 2010 and reserved the order.

39. SLP was filed by the Domestic Industry, before the Hon'ble Supreme Court, against the interim stay orders granted by the Hon'ble Madras High Court. The Hon'ble Supreme Court vide order dated 13<sup>th</sup> December, 2010 directed Hon'ble High Court of Madras to expeditiously issue the reserved judgment within 4 weeks:

*Heard learned counsel on both sides. We request the High Court to expeditiously deliver the judgment in the pending Writ Appeal Nos.1237 of 2010 and 1238 of 2010 and Writ Petition Nos.8901 of 2010 and 10709 of 2010. This order has become necessary in view of the fact that the cut-off date is 18th February, 2011, in respect of final findings on Anti Dumping Duty. We request the High Court to deliver this judgment, preferably within a period of four weeks from today. The special leave petitions are, accordingly, disposed of.*

40. The Hon'ble High Court of Madras, vide orders dated 25<sup>th</sup> March, 2011, disposed of the WP No. 15826 of 2010 and MP No. 1 and 2 of 2010 in M/s Value Refrigerants Pvt Ltd vs Union of India with a similar judgment as passed by the Hon'ble Division Bench in the WA No. 1237 of 2010 and batch cases 06.01.2011 in the SRF Ltd vs Refex Refrigerants Ltd.

41. The Hon'ble Madras High Court vide its order dated 30<sup>th</sup> March, 2011 in the Misc. Petition Nos. 1 and 1 of 2011 in Writ appeals No. 1237 of 2010 made the following order:

" In view of the dismissal of SLP. Nos. 1913 to 1916 of 2011 by the Hon'ble Apex Court by order dated 3.2.2011, it is submitted that the New designated authority has been appointed on 14.2.2011.

Accordingly, though it is not feasible to grant a period of six months time as requested by the petitioners herein.

We consider it appropriate to grant a period of six weeks from today to complete the investigation.

M.P.Nos. 1&1 of 2011 are disposed of accordingly."

42. On 6th January, 2011, Hon'ble Division Bench of Madras High Court passed the following Judgment:

*"17. Therefore, without going into various aspects urged and argued on either side in view of the further fact that serious disputed questions of fact regarding the stature of the complainant, which will have the impact of cutting the root, are involved in the matter, we set aside the orders dated 19.4.2010 and 21.5.2010 passed by the third respondent and direct the first respondent/Government of India to appoint/nominate another officer in the place of the third respondent, to act as a Designated Authority for this case, within a period of four weeks from*



*the date of receipt of a copy of this order. The officer so appointed/nominated is directed to conduct enquiry by scrupulously following the law governing the subject, viz. the Customs (Tariff) Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti Dumping Duty on dumped articles and for determination of Injury) Rules, 1995 and pass orders within six weeks thereafter. Till that time, the preliminary report dated 19.2.2010 shall not be given effect to. With this direction, all these matters are disposed of. No costs. Connected Miscellaneous Petitions are closed."*

43. SLP filed by the Authority against the interim stay orders granted by the Hon'ble Madras High Court vide No.18447-18449 of 2010 came up for hearing on 14.01.2011 and the same was disposed of as infructuous.

44. The Designated Authority again filed SLP against the final judgment dated 06.01.2011 of the Hon'ble Division Bench of Madras High Court vide No.1913-1916. The same was finally heard by the Hon'ble Supreme Court on 03.02.2011 and disposed of as follows:

*" We have heard the learned Additional Solicitor General and the learned senior counsel for the parties at length.  
In our considered view, no interference is called for. The special leave petitions are dismissed."*

45. Relevant averments made by the interested parties before various Courts in their respective writ petitions, which have also been considered by the Authority in this finding, are as follows:

- a) Dumping per se not condemnable as it is recognized that producers sell their goods at different prices to different countries. Price discrimination in the form of dumping is a common international commercial practice.
- b) SRF has failed to disclose that they are also an importer of the subject goods.
- c) The entire anti-dumping proceeding has been initiated on the basis of a project report of M/s SRF which contains extremely rosy projections.
- d) Preliminary findings issued by the Authority recommending provisional anti-dumping duty without affording the petitioner an opportunity of personal hearing and without considering the representations of the petitioner dated 24/09/2009 and 05/04/2010.
- e) The petitioner was not supplied relied upon documents by Authority.
- f) The representation dated 24th September, 2009 and 05th April, 2010 has not been considered by the Authority in preliminary findings.
- g) The petitioner was not given notice of the anti-dumping proceedings nor was it called for a personal hearing or given copies of the complaint by the M/s SRF or the other documents before the Authority.

- h) The applicant is not a domestic industry under Rule 2(b) of AD Rules since they are also importer of the subject goods.
- i) The applicant does not manufacture the product in any justifiable quantity in order to qualify as domestic industry under Rule 2(b) of AD Rules.
- j) The applicant is beneficiary of various Government subsidies.
- k) The PUC has been incorrectly determined in extremely vague, wide and amorphous manner. Proposed levy of anti-dumping duty extends beyond the products that are claimed to be allegedly manufactured by the domestic industry.
- l) Imposition of anti-dumping duty will result in artificial increase in the price of the subject goods.
- m) The Chinese and Japanese companies use extremely cost effective methods and technology to produce the product under consideration and their prices are globally competitive.

**Submissions made by the interested parties during the course of the investigation**

46. Following submissions have been made by the various interested parties during the course of the investigation:

- i. Installed capacity of applicant is much less than the domestic demand.
- ii. Imposition of proposed duty on the subject goods will lead to monopolization of the trade by the applicant.
- iii. No appropriate third party has been notified for the purpose of determination of normal value of the subject goods.
- iv. Subject goods are also imported from USA, UK and Germany. Hence the present proceeding is incomplete in respect of the subject goods.
- v. Since the Sale of applicant increased by 56.33% in 2008-09, it clearly establishes that the applicant's unit is a profit making unit.
- vi. Applicant has exported subject goods during 2007-08 and 2008-09. It indicates that low price is the applicant's strategy to oust the other players from the market.
- vii. The increase in import is due to manifold increase in demand in the Indian market during the so called injury period.

- viii. China PR and Japan use advance technology to produce the subject goods cost effectively.
- ix. There is known difference between domestically produced subject goods and goods imported from the subject countries. The proposed levy of anti-dumping duty is extended beyond the products claimed to be purportedly manufactured by the purported domestic industry. R-134A from China is superior in terms of purity and quality.
- x. Injury period should not be less than 4 years as mandated under the Act and Rules.
- xi. The applicant is claiming injury based on its plan/project report which is totally unrealistic and unachievable without any proper verification.
- xii. The Applicant did not include Stallion and Honeywell as known interested parties.
- xiii. Wide publicity of the initiation notification under reference was necessarily required to be given throughout India.
- xiv. The Designated Authority should have disclosed all the facts in the initiation notification.
- xv. The applicant is not domestic industry under Rule 2(b) of AD Rules since they are also importer of the subject goods. Further, the applicant does not manufacture the product in any justifiable quantity in order to qualify as domestic industry under Rule 2(b) of AD Rules.
- xvi. DGAD has not disclosed the detailed facts/adjustments of computing the Normal Value the ex-factory export price, dumping margin calculation etc in the Preliminary Finding.
- xvii. Determination of Normal Value in terms of Rule 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules without considering the data furnished by the producer/exporter is against the express provisions of Section 9A(6A) of the Customs Tariff Act.
- xviii. Rejection of the MET claims is unreasonable and unjust.
- xix. Both basic customs duty and customs education cess should be included while calculating the landed value.
- xx. Improvement in various injury parameters does not show injury to the domestic industry. The various economic parameters of domestic industry such as Capacity, Production, Capacity Utilization, Domestic Sales, Cost of sales.

profitability, etc, do not indicate material retardation to establishment of domestic industry.

- xxi. Contrary to the observations of the Authority in the PF, the actual sales volumes of the Applicant have far exceeded the projected sales in the project report.
- xxii. During the start up period of an Industry the cost remains very high due to unabsorbed overheads and inefficient production process, which results in high raw material consumption. These facts should have been examined by the Designated Authority while coming to a conclusion that purported injury has been caused by alleged dumped imports or the same is due to start up operations.
- xxiii. Regarding causal link in the instant case the following submissions were made:
- a) Change in the pattern of consumption despite increase in demand, domestic industry is unable to make profits in the sale of R134a because of its very high cost structure.
  - b) Poor exports achieved compared to projected export targets were the sole reason for the losses suffered by the domestic industry during 2008-09.
  - c) SRF is offering significantly low prices; users are forcing exporters also to match the prices set by SRF.
  - d) There is no causal link between the injury to the domestic industry and the imports from china.
  - e) Global recession is the main cause of decline in sales prices, decline in demand of finished products and decline in production and sales quantities.
- xxiv. The Domestic Industry has never claimed Material Retardation. Moreover, both Material Injury and Material Retardation to the establishment of the Domestic Industry cannot co-exist.
- xxv. Project report cannot be an authentic document to compare and assess the performance of the Domestic Industry.
- xxvi. The Non-injurious Price determined by the Designated Authority is highly superfluous.
- xxvii. Normal Value determined on the basis of conversion cost based on Domestic Industry cost data is incorrect.

xxviii. Mexichem Japan contended that there are various types/grades of the subject goods such as Industrial grade, 1-impact, CGMP and high purity. They further contended that different types/ grades are not substitutable and alleged that domestic industry is not manufacturing any grade other than industrial grade.

xxix. Investigation is time bared in term of Rule 17 of AD Rules and Article 5.10 of the WTO Agreement on anti-dumping.

**Submissions made by the domestic industry during the course of the investigation**

47. During the course of the investigation the following submissions have been made by the Domestic Industry:

- i. The petitioner is not importing the product under consideration after commencement of commercial production.
- ii. None of the Chinese producers can be given market economy treatment.
- iii. India is an appropriate surrogate country for Chinese producers. This has been accepted by other investigating authorities also.
- iv. The argument of the interested parties that the proposed imposition of ADD on import of R 134a is without rationale is baseless.
- v. The argument of the interested parties that the applicant does not want to compete with advance technology and had also received a huge subsidy for phasing out CFC 12 are baseless.
- vi. Increase in demand cannot be the certificate for resorting to dumping.
- vii. The argument of the interested parties that the installed capacity of the applicant is much less than the domestic demand and imposition of duty will make the applicant exploit and monopolize the trade is not correct and baseless.
- viii. The argument of the interested parties that the normal value of subject good in China PR and Japan is significantly higher than the ex factory export price is without any basis.
- ix. Increase in sale volume by the domestic industry does not mean that the product is profitable.
- x. Export made by the domestic industry does not mean that the product is not being imported at dumping prices in the Indian market or that the domestic industry is not suffering injury due to dumping.

- xi. The submission of the interested parties that increase in import is due to increase in demand is baseless. Increase in imports is due to dumping.
- xii. The Applicant uses the same technology as the producers in the subject countries.
- xiii. The interested parties have argued that Japan has not yet responded and China PR has been treated as NME, hence, without proper investigation, imposition of duty is not appropriate and justified. But, it is for the Japanese producers to respond to the Authority. The Designated Authority cannot force a party to respond nor can the non-cooperation by a party prevent to conduct and completion of the investigations.
- xiv. The project report of the domestic industry is approved by its Board of Directors and is based on verifiable information.
- xv. The argument that the Applicant has operated at its highest level of installed capacity utilization and thus, there is no dumping and no injury is without basis. As stated in the petition and written submissions, that the petitioner has achieved production level of 247 MT in the month of March, 2008, which implies 3000 MT capability on annualized basis [i.e., 100% utilization]. The company again achieved production of 239 MT in Dec., 2008. This clearly establishes technical capability of the petitioner to produce and sell the product. Capacity utilization in fact got impacted due to dumped imports.
- xvi. The request of Honeywell Flourine Products, Europe BV for a separate dumping margin should not be accepted since they have not filed questionnaire response.
- xvii. The argument that the Authority has not disclosed on what basis normal value for China has been construed is baseless. The methodology of construction of the Normal Value has been disclosed in the Preliminary Findings and disclosure of the essential facts should be envisaged only at the stage of disclosure statement.
- xviii. If the Authority includes customs duty and customs education cess while calculating the landed value, as argued by the interested parties, the Authority should also include excise duty and sales tax payable by the domestic industry since these are also charged at the ex-factory level .
- xix. The submission that Domestic Industry had started the production just a few months before POI and that is why, it is suffering from high costs, is without basis. The claim of injury to the domestic industry is not due to start up problems. In fact, the petitioner had achieved 100% plant utilization in March, 2008 itself. However, the plant utilization subsequently declined because of the dumping of the product in the domestic market.

- xx. The project report of the domestic industry is a confidential document.
- xxi. None of the interested parties have identified any factor, other than dumping, which could have caused injury to the domestic industry.
- xxii. Calculations of dumping margin, NIP, Normal Value, Export Price etc cannot be disclosed being confidential in nature.
- xxiii. The submission that DGAD should determine normal value based on the information provided by the producer/ exporter is not correct since Dumping margin on the basis of information provided by an exporter can be determined only if the exporter is entitled to market economy treatment.
- xxiv. The argument that the demand for R 134a from China is because of the superior quality of the Chinese goods and loss is caused due to the domestic Industry's inefficiency in production is without basis. A superior product cannot come-in at a lower price. In any case, there is no significant difference in the product.
- xxv. The submission that misleading statistics has been provided by the domestic industry is baseless. The domestic industry has provided all the information based on records maintained by the company and the information has been verified by the Authority.
- xxvi. The submission that a time period of preceding 3 years and POI for injury analysis is required, is not correct. As per WTO, a shorter period can be accepted by the Authority.

**Post disclosure comments by the exporters/importers/other interested parties**

48. Following comments were made by the exporters/importers/other interested parties

- DGAD has no jurisdiction to continue this investigation. The subject investigation should be terminated since violated Article 5.10 of the WTO Agreement,
- Gap between the domestic demand and the domestic supply makes imports inevitable and may promote monopoly of the sole domestic producer.
- The different types/grades of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a cannot be treated as like products. The Domestic Industry manufactures only Industrial Grade R-134a.
- Non-disclosure of normal value, export price and dumping margin
- Wrong Methodology adopted to calculate Non-injurious Price.

- Authority has placed heavy reliance on some project report submitted by the Domestic Industry in support of its claim.
- No causal link and no injury to the domestic industry.

### **Post disclosure comments by domestic industry**

49. Following comments were made by the domestic industry on the disclosure statement:

- Capital employed should include (a) fixed assets and (b) working capital required for production of the captive input.
- anti dumping duty may be imposed only on fixed amount basis.

### **Examination by the Authority**

50. The relevant submissions raised by the interested parties at various stages of the investigation including comments on the disclosure statement, have been examined and addressed in the respective paras of this finding.

### **D. Product under Consideration and Like Article**

51. The product under consideration in the present investigation is 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a of all types. R-134a, is also called as Tetrafluoroethane, Genetron 134a, Suva 134a or HFC-134a, HFA-134a, and Norflurane. It is a haloalkane refrigerant with thermodynamic properties similar to R-12 (dichlorodifluoromethane), but without its ozone depletion potential. It has the chemical formula  $\text{CH}_2\text{FCF}_3$ , and a boiling point of  $-26.3^\circ\text{C}$  ( $-15.34^\circ\text{F}$ ). It is an inert gas used primarily as a high temperature refrigerant for domestic refrigeration and automobile air-conditioners. Other uses of the subject goods include plastic foam blowing, as a cleaning solvent and as a propellant for the delivery of pharmaceuticals (e.g. bronchodilators), gas dusters, and in air driers, for removing the moisture from compressed air.
52. The subject goods are being imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2903 under "Halogenated Derivatives of Hydrocarbons"; under subheading 29033919 as "Other Fluorinated Derivatives", under the Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System). The petitioner has, however claimed that the product under consideration does not have any dedicated customs classification code and are being imported under various other Customs sub-headings. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.



### **Issues Raised by Interested Parties on PUC and Like Article**

53. It has been argued by the interested parties that the PUC has been incorrectly determined in extremely vague, wide and amorphous manner. Proposed levy of anti-dumping duty extends beyond the products that are claimed to be allegedly manufactured by the domestic industry. It has been further contended that there are various types/grades of the subject goods such as industrial grade, 1-impact, CGMP and high purity. They further contended that different types/ grades are not substitutable and alleged that domestic industry is not manufacturing any grade other than industrial grade. It was further argued that the Chinese and Japanese companies use extremely cost effective methods and technology to produce the product under consideration and their prices are globally competitive and also superior in terms of purity and quality.
54. The domestic industry has claimed that there is no known difference between the products manufactured by them and the subject goods imported from the subject countries, which can have any impact on price, usage, quality etc. The domestic industry also claims that the technology and primary production process employed by them and the foreign producers are comparable; however, every producer fine-tunes its production process based on available facilities and necessities. Further, domestic industry disputes the claim made by Mexichem for exclusion of any type of R-134a and submits that different types are nothing but one product. These are merely different grades/forms/types of 134a produced.

### **Examination by Authority**

55. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

*"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

56. The Authority notes that the Domestic Industry follows the Gas Phase Method for the production of PUC as the Chinese enterprises and the nature of the PUC does not change with the level of purity. Examination of the product and import data submitted by the applicant indicates that there is no difference between subject goods produced by the Domestic Industry and imported from China. Moreover no substantial material has been provided by the interested parties in support of their arguments.
57. With regard to different types/grades of the subject goods, the Authority notes that in terms of end use, broadly there are two types of the subject goods i.e industrial and medical. The industrial type is used in refrigeration and air-conditioning etc, whereas the medical type is used as a drug propellant mainly for human consumption. The plant and machinery, raw material and the process of production of both the types are same. The differences between the two is only the level of purity, the purity required for the medical type meant for human consumption is minimum 99.98%. Although the domestic industry does not have GMP certificate, they have manufactured and supplied both industrial type and medical type (propellant) and adequately demonstrated with

documentary evidence. Moreover the different types of the subject goods are based on level of purity only and the various types of the subject goods meant for human consumption can be used for industrial purpose, the purity level being higher, although the industrial type cannot be used for human consumption.

58. Product under consideration produced by the Domestic Industry and those imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the above, the Authority holds that subject goods produced by the Domestic Industry is therefore being treated as like article to the subject goods imported from subject countries, in accordance with the Anti-Dumping Rules.

## **E. Domestic Industry and Standing**

### **Issues Raised by Interested Parties**

59. With regard to standing and scope of the domestic industry the interested parties have argued at various stages of the investigation that the applicant is not Domestic Industry under Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules since they do not manufacture the product in any justifiable quantity and are also importer of the subject goods.

### **Views of the Domestic Industry**

60. The domestic industry has claimed that they have not imported the product under consideration after commencement of commercial production.

## **E.1. Examination by Authority**

61. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules (as amended by Notification No. 18/2010-Customs (N.T.) – New Delhi dated 27<sup>th</sup> February, 2010) provides as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term “domestic industry” may be construed as referring to the rest of the producers only.”

62. The Authority notes that evidence on record does not show that Domestic Industry has imported the subject goods from the subject countries after commencement of commercial production and during the period of investigation. Therefore, the Authority holds that the applicant constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) and being the sole producer of the subject goods in the country commands the standing in terms of Rule 5(3).

**F. Issues relating to Confidentiality**

63. The interested parties have argued that:

- a) The relied upon documents , including project report of the domestic industry, was not supplied by Authority.
- b) The Designated Authority should have disclosed all the facts in the initiation notification.
- c) Authority has not disclosed the detailed facts/adjustments of computing the Normal Value, the ex-factory export price, dumping margin calculation etc in the Preliminary Finding.

**F.1 Views of the Domestic Industry**

64. In respect of confidentiality issue, domestic industry claimed that the project report can not be disclosed since the report contains sensitive information, disclosure of which will seriously jeopardize business interests of the domestic industry. Any information/data given on confidential basis cannot be disclosed by the Authority. Calculations of dumping margin, NIP, Normal Value, Export Price etc cannot be disclosed being confidential in nature.

**F.2 Examination by the Authority**

65. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7). The Authority after examining the submissions of the interested parties observed that the methodology of computation of Normal Value, export price and non-injurious price have been disclosed in this finding.

66. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

**Confidential information.** (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the

information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

b) The WTO Agreement on Anti Dumping provides as follows with regard to confidentiality of information :-

**Article-6.5** Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.

**Article-6.5.1** The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

**Article-6.5.2** If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.

Footnote to Article 6.5.2 (footnote 18 of the WTO Agreement on Anti Dumping) provides as follows :-

*Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected.*

67. It is thus evident that the public notices issued by the authorities are directly subjected to confidentiality provisions and should protect confidentiality of information provided by an interested party. Further, a conclusion drawn by the Authority based on confidential information also becomes confidential, if disclosure of such conclusion can in any way effectively lead to disclosure of information provided on confidential basis.

68. The provision for disclosure of essential facts before giving final findings has been laid down at Rule 16 of the Anti-dumping Rules. Even under Rule 16, the confidential facts are required to be disclosed to "respective interested parties", while non-confidential facts are required to be disclosed to all interested parties. At no stage the Designated Authority is empowered to disclose the confidential information to the parties with competing and conflicting interests. Thus it would be sufficient if full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment and comparison of the export price, normal value and Non-injurious price are disclosed by the Designated Authority instead of disclosing the actual figures. Normal Value, export price and non-injurious price are based on the confidential information submitted by the parties and disclosure of the same would be of significant competitive advantage to a competitor and its

disclosure could have a significantly adverse effect upon the person supplying the information.

69. Disclosure of the commercially sensitive and confidential information, provided by the interested parties to the Designated Authority, by reposing trust and confidence, to facilitate the investigation, will completely vitiate the market atmosphere both in the domestic as well as international fronts. The disclosure of confidential information relating to the cost of production, non-injurious price etc. of the domestic industry will provide undue advantage to its domestic as well as overseas competitors and place them in a disadvantageous position before the consumers. Likewise disclosure of the confidential information relating to the exporters such as normal value, net export price, landed price etc. will jeopardize their commercial interest vis-à-vis their competitors as well as buyers.
70. One of the interested parties namely M/S Refex Refrigerants Pvt. Ltd. has claimed that confidential information of the other interested parties. In terms of the provision of Rules 7 of the AD Rules, the domestic industry and the respondents exporters and importers were specifically requested by Authority to offer their comments on the claim of the M/S Refex Refrigerants. Such respondent interested parties and the domestic industry have opined that the Authority can not disclose the confidential information.
71. In view of the above Authority notes that confidential information can not be disclosed to the interested parties with competing and conflicting interests. However the non – confidential information has been disclosed to the interested parties.

#### **G. Miscellaneous issues**

72. The following miscellaneous issues have been raised by the interested parties at various stages of the investigation:
- i) Dumping per se not condemnable as price discrimination in the form of dumping is a common international commercial practice. Imposition of anti-dumping duty will result in artificial increase in the price of the subject goods.
  - ii) Installed capacity of applicant is much less than the domestic demand. Imposition of proposed duty on the subject goods will lead to monopolization of the trade by the applicant.
  - iii) The entire anti-dumping proceeding has been initiated on the basis of a project report of M/s SRF which contains extremely rosy projections.
  - iv) The Authority did not supply relied upon documents to interested parties.
  - v) M/s Refex alleged that preliminary finding has been issued by the Authority recommending provisional anti-dumping duty without affording the petitioner an opportunity of personal hearing and without considering the representations of the petitioner dated 24/09/2009 and 05/04/2010.

- vi) The applicant is beneficiary of various Government subsidies.
- vii) Wide publicity of the initiation notification under reference was necessarily required to be given throughout India. The Designated Authority should have disclosed all the facts in the initiation notification. The Domestic industry did not include Stallion and Honeywell as known interested parties.
- viii) Injury period should not be less than 4 years as mandated under the Act and Rules.
- ix) Investigation is time bared in term of Rule 17 of AD Rules and Article 5.10 of the WTO Agreement on anti-dumping.

#### **G.1. Examination by the Authority**

73. The Authority has examined the miscellaneous issues raised by the interested parties as follows:

1. Authority notes that the objective and purpose of imposing anti-dumping duty is to prevent unfair trade practice and to create a level playing field for the domestic industry vis a vis dumped imports under the aegis of WTO and not to promote monopolization of trade by any interested party. Dumping is founded on the basis that a foreign manufacturer sells below the normal value in order to destabilize domestic manufacturers. In the present case, the Authority notes that even when the market for the product had significant demand, the domestic industry was forced to sell the product at a financial loss. The Authority notes that 'dumping' is an unfair trade practice and must be condemned if it causes injury to an established domestic industry, even though there is only one domestic producer; as the intent of anti-dumping duty is only to redress the injury caused to the domestic industry on account of the unfair trade practice of dumping. Imposition of the duties shall not restrict the rights of foreign producers to sell the subject goods at un-dumped prices in the Indian market.
2. The Authority on the basis of sufficient evidence, submitted by the domestic industry, initiated the investigation. The Authority notes that the project report has been considered and approved by the Board of the Company. Moreover, the Authority has verified the information submitted by domestic industry during the course of investigation.
3. The Authority notes that as per Rules 6(7), the non-confidential documents submitted by various interested parties are made available through public file for inspection by the interested parties.
4. The Authority notes that the relevant submissions made by M/s Refex Refrigerants Ltd. vide their letter dated 24.09.2009, 5.4.2010 and all their subsequent submissions, including the submissions made by various interested parties during the course of the investigation have been considered in this disclosure. With regard to opportunity to interested parties for making submission,

the Authority has provided ample opportunity to the interested parties as per Rules. Apart from granting personal hearing to M/s Refex, the Authority had granted two oral hearings to the interested parties and provided opportunity for making oral and written submissions in the subject investigation, apart from disclosing essential facts of the investigation considered by the Authority.

5. Authority notes that the allegation of subsidy is without any basis. However the Authority has examined the issue and notes that SRF has given a certificate containing that SRF has not received any subsidy from the Government of India or any other institution for setting up its Plant to manufacture R-134a/ HFC-134a (PUC). Further SRF had cleared the imported equipments used in its Plant under Notification No. 21/2002- Customs dated 1.3.2002 as read with Notification No.11/2005 Customs dated 1.3.2005, which exempts payment of Customs Duty on fulfillment of certain conditions. The authority has verified the information of the Domestic Industry and notes that no subsidy has been received by the Domestic Industry for setting up the plant manufacturing the subject goods.
6. The initiation notification was published in the Gazette of India and Copy of the notification was sent to known interested parties as per Rules.
7. The Authority notes that WTO Committee on Anti-Dumping Practices vide paper G/ADP/6, adopted on 5 May 2000 states as follows:

*"The Recommendation Concerning the Periods of Data Collection for Anti-Dumping Investigations states, inter alia, that the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable; and that the period of data collection for injury investigations normally should be at least three years, unless a party from whom data is being gathered has existed for a lesser period, and should include the entirety of the period of data collection for the dumping investigation. From this, we take it that it is desirable that there be a substantial coincidence in the period of investigation for dumping and the period during which injury was found".*

In the present case the domestic industry has set up their Plant for manufacturing the product under consideration in the year of 2006-07 and the manufacturing facility for product under consideration was undergoing pre-commissioning trial runs.

8. It has been contended by the interested parties that the subject investigation is time bared in term of Rule 17 of AD Rules and Article 5.10 of the WTO Agreement on anti-dumping. The Authority notes that pursuant to the orders dated 6<sup>th</sup> January, 2011 of the Hon'ble Division Bench of the Madras High Court and orders dated 3<sup>rd</sup> February, 2011 of the Hon'ble Supreme Court, the subject investigation has been continued beyond the maximum time limit prescribed under the Rules and WTO Agreement i.e. 18<sup>th</sup> February, 2011.

#### H. De Minimis Limits

74. As per the import data received by the Authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and other secondary sources, as well

as the data furnished by the cooperating exporters from China PR, the import of the subject goods from the subject countries are above the de minimis level.

**I. Determination of Dumping Margin**

**I.1 Examination of Market Economy Claims**

75. In the present case the cooperating producers/exporters were accorded Non Market Economy status in the Preliminary Findings and they have not rebutted to the satisfaction of the Authority. The Authority had verified the data/information of the cooperating producers/exporters from China PR.

76. The Authority, notes that in the past China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of Para 8 (2) of the annexure of Anti-dumping Rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules.

77. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

- a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and,
- d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

78. The Authority notes that following producers and exporters of the subject goods from China PR have submitted their Exporters Questionnaire responses and Market Economy Questionnaire response, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption:

- a) Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd.
- b) Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd.
- c) Zhejiang Juhua Co. Ltd.
- d) Zhejiang Quhuaflour Chemistry Co., Ltd.
- e) Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co Ltd
- f) Du-Pont Trading (Shanghai) Co. Ltd.



79. The Exporters Questionnaire responses and the Market Economy Questionnaire responses of the following cooperating producers/exporters from China PR were accepted and their information/data got verified by the Authority:

- a) M/s Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd.
- b) M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd.
- c) M/s Du-Pont Trading (Shanghai) Co. Ltd.

### Examination by the Authority

#### M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd (Producer/Exporter)

80. M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd has claimed MET status in its response. It is stated in the MET response that China New Technology Development Trade Co Ltd holding \*\*\*% share in the subject company is a State owned company. The other \*\*\*% share is stated to be held by Xian Modern Chemistry Research Institute.

As per the Article of Association of Xian Jinzhu Modern Chemical Co Ltd, the predecessor company of the subject company, it was a joint venture between Tibet Jinzhu Co Ltd and Xian Modern Institute of Chemical Research. While Tibet Jinzhu Co Ltd held \*\*\*% share, Xian Modern Institute of Chemical Research, the Research Institute of China Ordnance Industry, held \*\*\*% of the shares in Xian Jinzhu Modern Chemical Co Ltd. The joint venture Xian Jinzhu Modern Chemical Co Ltd was formed with the approval of Tibet Plan Committee and Sanxi Province Plan Committee, the State owned agencies.

As per the web based information, Sinochem Group/Sinochem Corporation is a State owned company and the company was set up originally during 1950 as a State owned agency for promoting production and sale of chemicals and other products.

During verification it was observed and acknowledged by the company that Sinochem Group Co Ltd or Sinochem Corporation is a \*\*\*% State owned company originally set up during 1950. Along with another State owned agency namely Zhejiang Province State Asset Commission, it promoted Zhejiang Province Petrochem Construction Material Group with \*\*\*% and \*\*\*% shares respectively, which in turn owns China New Trade Development Co Ltd holding \*\*\*% share along with Sinochem Group holding \*\*\*% share. China New Trade Technology Development Co Ltd, a \*\*\*% State owned company along with another State owned agency namely Xian Modern Chemistry Research Institute owns the subject company. In this way the subject company M/s Sinochem Modern Environmental Chemicals (Xian) Co Ltd is a \*\*\*% State owned company, under the common control of the State owned Sinochem Group. It's subsidiary company M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taikang) Co Ltd, a respondent producer/exporter in the subject investigation, in which it has the majority share of \*\*\*%

along with two other State owned companies namely Sinochem Europe holding \*\*\*% share and China New Trade Technology Development Co Ltd holding \*\*\*% share, is also a \*\*\*% State owned company. It is further observed that the Board of Directors of the company is \*\*\*% represented by the representatives of the State owned share holding companies

The company could not adequately demonstrate with documentary support that the growth/transformation of the company over the years was determined by market forces completely free of state interference. Further, the respondent company could not demonstrate with documentary support that the assets/raw materials/ utilities have been purchased by the company under market conditions and at prices comparable to the prices prevailing in the international market. The company could not also adequately demonstrate with documentary support to prove that the decisional process of the company is free of State influence.

The company failed to furnish some of the following relevant information/documents/records to the verification team, in support of their MET claim:

- i. Details/documents relating to the State owned Group company Sinochem Group/Sinochem Corporation, parent companies China New Technology Development Trade Co and Xian Modern Chemistry Research Institute and the affiliated and subsidiary companies.
- ii. Details/documents relating to Tibet Jinzhu Co Ltd and Xian Modern Chemistry Research Institute, the investors in Tibet Jinzhu Modern chemicals Co Ltd.
- iii. List of subsidies and details of the subsidies received by the company from the Government source.
- iv. Detailed list of the assets of the company from the year of establishment till POI with details regarding date of procurement, mode of procurement, source of procurement, along with documents in proof of payment through normal banking channel.
- v. Copy of the reports of Tibet Plan Committee and Sanxi Plan Committee with whose approval Xian Jinzhu Modern Chemicals Co was set up in 1997.
- vi. Amount and source of investments/funds made by the subject company in its subsidiary company and documents justifying the difference between the registered capital of Sinochem Xian and it's investments in Sinochem Taikang.
- vii. Land and building records along with proof of procurement, mode of procurement, payment proof through normal banking channel, etc.

The verification report was sent to the concerned producer/exporter by the Authority for views/comments. However, they failed to offer any comment. In view of the above stated position the Authority has not granted MET status to M/s Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd.

**M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co . Ltd**  
**(Producer/Exporter).**

81. it has been submitted by M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd. in their MET Response that they are a Chinese foreign equity joint venture company. The respondent company has claimed MET status in its response. It is stated in the MET Response that the subject company is a limited liability company and a foreign equity joint venture, with majority share held by M/s Sinochem Xian, the parent company.

However, during verification it was observed that the ultimate controlling company i.e. Sinochem Group Co Ltd or Sinochem Corporation, originally set up during 1950 as per web based information, is a \*\*\*% State owned company. Along with another State owned agency Zhejiang Province State Asset Commission, it promoted Zhejiang Province Petrochem Construction Material Group with \*\*\*% and \*\*\*% shares respectively, which in turn owns China New Trade Development Co Ltd holding \*\*\*% share along with Sinochem Group holding \*\*\*% share. China New Trade Technology Development Co Ltd, a \*\*\*% State owned company along with another State owned agency namely Xian Modern Chemistry Research Institute owns Sinochem Modern Environmental Chemicals (Xian) Co Ltd, the respondent controlling parent company of the subject company, which holds the majority share of \*\*\*% along with two other State owned companies namely Sinochem Europe holding \*\*\*% share and China New Trade Technology Development Co Ltd holding \*\*\*% share. In that way the subject company is a \*\*\*% State owned company. All the 7 Directors including the Chairman of the Board of Directors of the company, represent the State owned share holding companies.

During verification the respondent producer/exporter acknowledged that they are a \*\*\*% State owned company with the Board of Directors \*\*\*% represented by representatives of the State owned share holding companies and could not adequately demonstrate that the decisional process of the company is free of State influence.

The respondent company could not demonstrate with documentary support that the assets/raw materials/ utilities have been purchased by the company under market conditions and at prices comparable to the prices prevailing in the international market. The company could not also adequately demonstrate with documentary support to prove that the decisional process of the company is free of State Influence. The Company failed to furnish some of the following relevant information/documents/records to the verification team, in support of their MET claim:

- (i) Details/documents concerning Sinochem Group, the \*\*\*% State owned and ultimate controlling company.
- (ii) Justification for the difference between the registered capital of the parent company (Sinochem Xian) and investment made by the parent company in it's subsidiary company(Sinochem Taicang), as reflected in the audited annual accounts of the subject company, and the source of fund.
- (iii) List of subsidies received from the Government.

- (iv) Power consumption by unit for production of R134a.
- (v) Payment vouchers of major assets through normal banking channel.
- (vi) Sample copies of TCE and AHF purchase from related and unrelated parties.
- (vii) Copies of sales documents for domestic sales of the subject goods by the subject company.
- (viii) Clarification to the discrepancy between quantity of sale of the subject goods made by the subject company to M/s Du pont Shanghai and the purchase quantity shown by them in their records.

The verification report was sent to the concerned producer/exporter by the Authority for views/comments. However, they failed to offer any comment. In view of the above stated position the Authority has not granted MET status to M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd.

#### **M/S Du-Pont Trading (Shanghai) Co. Ltd. (Exporter)**

82. In their MET Response it has been submitted by M/S Du-Pont Trading Shanghai Co. Ltd. (DPTS), China that they are a 100% subsidiary of M/s Du-Pont China Holding Co. Ltd. It has further been submitted that M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd., a corporation organized under the laws of China, is the only supplier (un-related) of R-134a and has multi year contract with them starting from Sep., 2008. During verification it was informed that Du Pont China Holding Co Ltd ("DCH") is the principal Du Pont entity in China and the controlling company of M/s Du Pont Trading Shanghai Co Ltd (DPTS), Shanghai. DPTS is one of the wholly owned subsidiaries of DCH. DPTS only is involved in the trading of the product concerned. It was informed that neither DCH nor any other related companies of DCH are involved in the product concerned.

DPTS in its capacity as a trader has claimed Market Economy Status. DPTS stated that since DCH was not at all involved in the production or sale of the product concerned, they have not filed a separate MET questionnaire response. Further, it was explained that Du Pont China Ltd, a company registered in USA holds \*\*\*\*% of the shares of DCH and DCH holds \*\*\*\*% shares in DPTS.

Being a trading company, MET claim of DPTS is not relevant unless the producer concerned establishes its market economy status. Moreover, DPTS, the subject trading company, has long term agreement with Sinochem Taikang, a \*\*\*\*% State owned Chinese producer/exporter and a cooperative respondent in the subject investigation, for procurement of the subject goods, exported to India, at agreed upon price. DPTS has exported the subject goods to India by procuring the same only from M/s Sinochem Taikang, a \*\*\*\*% State owned company. DPTS purchased the subject goods from Sinochem Taicang under a Product Purchase and Sale Agreement between the two companies.

The authority observes that M/S Du-Pont Trading Shanghai Co. Ltd. China, (exporter) is a \*\*\*\*% subsidiary of M/s Du-Pont China Holding Co. Ltd, who has not filed MET Response in the subject investigation. M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd., a \*\*\*\*% state owned company in China PR, which has not been granted market economy status, is the only supplier of R-134a and has multiyear contract with them starting from Sep., 2008.

The verification report was sent to the party by the Authority for views/comments. However, they failed to offer any comment. In view of the above stated position the Authority has not granted MET status to M/s Du-Pont Trading Shanghai Co. Ltd. China.

**I.II. MET related issues raised by the interested parties during the course of the investigation.**

83. During the course of the investigation following MET related issues have been raised by the interested parties.

- Determination of Normal Value in terms of Rule 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules without considering the data furnished by the producer/exporter is against the express provisions of Section 9A(6A) of the Customs Tariff Act.
- No appropriate third party has been notified for the purpose of determination of normal value of the subject goods.
- Rejection of the MET claims is unreasonable and unjust.
- Normal Value determined on the basis of conversion cost based on Domestic Industry cost data is incorrect.
- Non – market economy provisions have become ultra vires under section 9A (6A) of the amended Rules.

**I.III. Views offered by the domestic industry with regard to MET and Normal Value.**

84. The following views have been offered by the domestic industry with regard to MET and Normal Value.

- i) None of the Chinese producers can be given market economy treatment.
- ii) India is an appropriate surrogate country for Chinese producers. This has been accepted by other investigating authorities also.
- iii) The argument of the interested parties that the normal value of subject good in China PR and Japan is significantly higher than the ex factory export price is without any basis.
- iv) The interested parties have argued that Japan has not yet responded and China PR has been treated as NME, hence, without proper investigation, imposition of duty is not appropriate and justified. But, it is for the Japanese producers to respond to the Authority. The Designated Authority cannot force a party to respond nor can the non-cooperation by a party prevent the Authority to conduct and complete an investigation.

- v) The argument that the Authority has not disclosed on what basis normal value for China has been constructed is baseless. The methodology of construction of the Normal Value has been disclosed by the Authority.
- vi) The submission that DGAD should determine normal value based on the information provided by the producer/ exporter is not correct since Dumping margin on the basis of information provided by an exporter can be determined only if the exporter is entitled to market economy treatment

#### **I.IV. Examination by the Authority**

85. As regards the argument that non-market economy provisions has become *ultra vires* under section 9A (6A) of the amended Rules, the Authority notes that the determination is fully consistent with the legal provisions.
86. The Authority has taken cognizance that the exporters from China PR have submitted responses rebutting the presumptions as mentioned in Para 8 of Annexure 1 of the Rules and Non Market Economy Questionnaire sent to them regarding grant of market economy status to their companies. The authority observes that both the verified cooperative respondent Chinese producers/exporters, which are related, are \*\*\*% State owned companies and failed to demonstrate with documentary support that their growth and commercial and administrative transactions are free of State influence. Moreover, they failed to furnish most of the relevant documents during verification to prove that they are free of State influence in their growth and administrative and commercial transactions and procurement of assets, raw materials and other relevant inputs are at prevailing market prices comparable to international standard. Further, the MET claim of the verified cooperative respondent trading company is irrelevant in the sense that the producer from whom they procured the subject goods through a long term pricing contract and exported to India is itself a \*\*\*% State owned and non market entity.
87. The Authority had not granted market economy treatment in the Preliminary Findings. During verification the cooperative respondent Chinese producers/exporters/traders could not demonstrate and justify with documentary evidence their MET claim as already mentioned in this finding. Since, even if one of the critical parameters of market economy treatment is not satisfied it would not be feasible to grant market economy status to the responding companies, the Authority has not granted MET status to any of the cooperative respondent Chinese producers/exporters/traders.
88. None of the interested parties have made available information regarding an appropriate market economy third country for the purpose of determination of normal value.
89. Moreover the Authority notes that the evidence on record does not establish that "prices of major inputs substantially reflect market values" comparable to prices prevailing in the international market. In a situation where the raw material prices are significantly lower than the prevailing market rates in the international market, not only a vital condition for market economy treatment is not satisfied but also costs may be underestimated. Further, the Authority notes that the producers/exporters from China

PR are admittedly either directly or through their subsidiaries and suppliers State controlled.

90. In view of the issues concerning ownership and control, their impact on the cost and prices and business decisions of the companies, the Authority has not granted market economy status to any of the subject producers/exporters from China PR.

## **J. Determination of Normal Value**

### **J.1 Determination of Normal Value for China PR**

91. The Authority indicated, in the Initiation Notification, that the Authority may notify an appropriate third country, in the due course, for the purpose of determination of normal value in China PR in terms of the above provisions. The Authority notes that none of the interested parties, including the applicants, have placed any material fact before the Authority to select an appropriate market economy third country for the above purpose. The domestic industry has submitted that they have made efforts to collect information on price and cost data of the subject goods in market economy third countries but no publicly available information could be collected in this regard. It has also been argued that for determination of normal value based on third country cost and prices, the Authority would require complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country, which the applicant is unable to obtain. The responding Chinese companies have made no claim with regard to an appropriate market economy third country. Therefore, the domestic industry has submitted that India should be treated as an appropriate surrogate country for China in this matter and the normal value should be determined accordingly.

92. The Authority, in view of the non-market economy status of the responding producers/exporters from China PR and since no interested party has provided the data of any appropriate third country, the Authority adopted the third option available in the Rules, which provides for adoption of any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin and construct the normal value in respect of China PR. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration for cooperating producers/exporters from China PR has been constructed based on facts available. The Normal Value has been constructed taking into account consumption norms of verified producers/exporters and international prices of major raw materials as per the data from DGCI&S source. Further, duly adjusted conversion cost and SGA expenses of the domestic industry have been adopted for determination of the normal value. After adding a reasonable profit margin of 5% constructed normal value has been determined as US\$ \*\*\* per Kg. in respect of the China PR.

### **J.2 Normal Value for Japan**

93. No exporter from Japan has cooperated and responded to the initiation notification issued by the Authority and submitted any information within the stipulated time. In view of that the Authority has seen the exports of subject goods by Japan to world over from the data available as per World Trade Atlas. On this basis normal value has been determined as US\$ \*\*\* Per Kg in respect of the producers/exporters from Japan.

**K. Determination of Export Price****K.1 Export Price for co-operating exporters from China PR****M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd.**

94. M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd has provided transaction wise details of exports to India during the period of investigation. For the purpose of this finding all export transactions have been taken into consideration for determination of export price. Company exported \*\*\* MT of subject goods to India during POI at total value of USD \*\*\*. The expenses claimed on account of packing, inland freight & port charges, overseas freight, overseas insurance, clearance and handling charges, other misc. charges and VAT adjustments have been allowed. By this methodology the ex factory weighted average export price has been determined as US\$ \*\*\* Kg.

**M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd.**

95. The Authority notes that M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd and M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd are related companies, being subsidiary companies of the Sinochem Group. M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd is also a shareholder in M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. Further, M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang)'s parent company is admittedly M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd, which produces and sales the subject merchandise. M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd has much larger production capacity than that of M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd. The Authority also notes that the Gross price charged by both these companies is substantially different despite having almost similar range of cost of production. It is noted from the information submitted that the difference is primarily on account of Bulk Discount. The exporter has provided transaction wise details of exports to India during the period of investigation. Company exported \*\*\* MT of subject goods to India during POI at total value of USD \*\*\*. All export transactions have been taken into consideration for determination of export price. The expenses claimed on account of packing, inland freight & port charges, overseas freight, overseas insurance and VAT adjustments have been allowed. By this methodology the ex-factory export price for M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co. Ltd. has been determined as US\$ \*\*\*/Kg.

**M/S Dupont Trading (Shanghai) Co., Ltd.**

96. The exporter has provided transaction wise details of exports to India during the period of investigation. All export transactions have been taken into consideration for determination of export price. Company exported \*\*\* MT of subject goods to India during POI at total gross value of USD \*\*\*. While arriving at net export price the



exporter has made adjustments towards packing charges, inland freight, sea freight and insurance premium. Further, adjustments of domestically procured goods, profit margin of Du-Pont Trading and VAT adjustments has also been made to arrive at the ex-factory weighted average export price. By adopting this methodology the ex-factory export price in respect of M/S Du-pont (Shanghai) Co. Ltd. has been determined as US\$ \*\*\*/Kg.

**Zhejiang Juhua Co. Ltd, M/S Zhejiang Quhuafluor – Chemistry Co., Ltd. & Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd.**

97. Zhejiang Juhua Co. Ltd (producer of the subject goods) M/S Zhejiang Quhuafluor – Chemistry Co., Ltd. & Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd (exporter) are related parties. M/S Zhejiang Quhuafluor – Chemistry Co., Ltd. has provided the transaction wise details of exports to India during the period of investigation and submitted that after procurement of subject goods from M/S Zhejiang Juhua Co. Ltd., (producer of the subject goods) appointed M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd. as their export agent and shipped and declared at the customs after they received L/C, negotiated payment and received payment. However, while going through their responses it is observed by the Authority that the copies of the sample invoices and other relevant export documents are held in the name of M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd., thereby making them the actual exporter to India. However, M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd., who also have submitted the Exporters and MET questionnaire responses, has submitted that they are not the actual exporter of the product under investigation and just an exporting agent. Due to absence of clear channel of flow of goods from the producer to the exporter and thereafter to the Indian buyer, independent dumping margin was not given to the respondent exporter in the preliminary finding.

Post preliminary findings, it was clarified that on the request of M/S Zhejiang Quhuafluor – Chemistry Co., Ltd, M/s Zhejiang Juhua Co. Ltd., (the producer ) delivered the subject goods directly to M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd., who then exported the goods to India and realized the foreign exchange. The Authority notes that the documents with regard to the domestic sale of the producer M/S Zhejiang Juhua Co. Ltd., do not evident such supply to M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd. Further, the documents submitted by M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd do not evident procurement of the exported subject goods from the producer M/S Zhejiang Juhua Co. Ltd, although they hold the export documents in their name. Moreover, though the export documents show the name of M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co. as the actual exporter of the subject goods, who also realized the foreign exchange, M/s Zhejiang Quhuafluor – Chemistry Co., Ltd in Appendix 2 ( of export sales) reflects the export sales transactions to India. But the exporters questionnaire response submitted by M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., despite being the actual exporter of the subject goods to India, does not contain the relevant appendices. As the linkage between production and export of the subject goods to India has not been clarified to the complete satisfaction of the Authority with documentary evidence, no separate export price has been determined in respect of either Zhejiang Quhuafluor Chemistry Co. Ltd. or Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd. In view of the above the Authority considers M/S Zhejiang Juhua Co. Ltd, M/S Zhejiang Quhuafluor – Chemistry Co., Ltd. & M/S Zhejiang Juhua Gonglian Foreign Trade Co., Ltd as non-cooperative.

**K.2. Export price for Non-cooperating Exporters from China**

98. Since, no response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from China PR; the Authority has decided to determine their Export Price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The data has been collated as per the information provided by the Applicant based on IBIS source and the expenses on account of packing, inland freight & port charges, overseas freight, overseas insurance, clearance and handling charges and other misc. charges have been adjusted on the basis of data furnished by co-operative exporters to arrive at the ex-factory price in respect of non-cooperative exporters from China PR. By adopting the above method the ex-factory export price for non-cooperative exporters from China PR has been determined as US\$ \*\*\* per /Kg.

**K.3. Export price for Exporters from Japan**

99. No exporter from Japan has responded to the investigation initiation notification. Therefore, the data reported by the IBIS, Mumbai for exports from Japan has been relied upon to calculate the ex-factory export price. As the transactions are on CIF basis, therefore, to determine ex-factory export price, adjustment on account of ocean freight, marine insurance, handling charges, port expenses have been adjusted to arrive at the ex-factory export price. By adopting the above method, the ex-factory export price for exporters from Japan has been determined as US\$ \*\*\* per /Kg.

**L. Dumping Margin**

100. For the purpose of determination of dumping margin the ex-works normal value and export prices so determined have been compared at the same level of trade and dumping margin has been determined for the exporters from the subject countries. Further, being related parties, the dumping margin in respect of M/S Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. and M/S Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd. has been determined on weighted average basis. On the basis of normal values and export prices as determined above, the dumping margins for exporters are determined as per table below: -

US\$/KG

Exporter/Producer From	Normal Value (USD)	Export Price (USD)	Dumping Margin (USD/K G.)	Wt. Avg. Dumping Margin of Taicang and Xi'an (USD/KG.)	Dumping Margin (%)

Japan	***	***	***	---	25 - 35
China PR					
Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang)	***	***	***	***	35 - 45
Sinochem Environmental Protection Chemicals (Xi'an)	***	***	***	***	30 - 40
Du-Pont	***	***	***	---	40 - 50
Others	***	***	***	---	45 - 55

101. The dumping margins so determined are significant and above de-minimis level.

#### **M. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK**

##### **M.1 Views of the Exporters, Importers and other Interested parties during the course of the investigation.**

102. The following views have been offered by the Exporters, Importers and other interested parties during the course of the investigation:

- i. Subject goods are also imported from USA, UK and Germany. Hence the present proceeding is incomplete in respect of the subject goods.
- ii. Since the sales of the Applicant increased by 56.33% in 2008-09, it clearly establishes that the applicant's unit is a profit making unit.
- iii. Applicant has exported subject goods during 2007-08 and 2008-09. It indicates that low price is the applicant's strategy to oust the other players from the market.
- iv. The increase in import is due to manifold increase in demand in the Indian market during the so called injury period.
- v. Both basic customs duty and customs education cess should be included while calculating the landed value.

- vi. Improvement in various injury parameters does not show injury to the domestic industry. The various economic parameters of domestic industry such as Capacity, Production, Capacity Utilization, Domestic Sales, Cost of sales, profitability, etc, do not indicate material retardation to establishment of domestic industry.
- vii. Contrary to the observations of the Authority in the PF, the actual sales volumes of the Applicant have far exceeded the projected sales in the project report.
- viii. During the start up period of an industry the cost remains very high due to unabsorbed overheads and inefficient production process, which results in high raw material consumption. These facts should have been examined by the Designated Authority while coming to a conclusion that purported injury has been caused by alleged dumped imports or the same is due to start up operations.
- ix. The causal link determination is inappropriate in this instant case in view of the following:
- Change in the pattern of consumption despite increase in demand, domestic industry is unable to make profits in the sale of R134a because of its very high cost structure.
  - Poor exports achieved compared to projected export targets were the sole reason for the losses suffered by the domestic industry during 2008-09.
  - SRF is offering significantly low prices, users are forcing exporters also to match the prices set by SRF.
  - There is no causal link between the injury to the domestic industry and the imports from China.
  - Global recession is the main cause of decline in sales prices, decline in demand of finished products and decline in production and sales quantities.
- x. The Domestic Industry has never claimed Material Retardation. Moreover, both Material Injury and Material Retardation to the establishment of the Domestic Industry cannot co-exist. Project report cannot be an authentic document to compare and assess the performance of the Domestic Industry.

## **M.2 Views of the domestic industry**

103. The following views have been offered by the Domestic Industry during the course of the investigation:

- Increase in sale volume by the domestic industry does not mean that the product is profitable.
- Export made by the domestic industry does not mean that the product is not being imported at dumping prices in the Indian market or that the domestic industry is not suffering injury due to dumping.
- The submission of the interested parties that increase in import is due to increase in demand is baseless. Increase in imports is due to dumping.

- The Applicant uses the same technology as the producers in the subject country.
- The project report of the domestic industry is approved by its Board of Directors and is based on verifiable information.
- The argument that the Applicant has operated at its highest level of installed capacity utilization and thus, there is no dumping and no injury is without basis. As stated in the petition and written submissions, that the petitioner has achieved production level of 247 MT in the month of March, 2008, which implies 3000 MT capability on annualized basis [i.e., 100% utilization]. The company again achieved production of 239 MT in Dec., 2008. This clearly establishes technical capability of the petitioner to produce and sell the product. Capacity utilization in fact got impacted due to dumped imports.
- The submission that Domestic Industry had started the production just a few months before POI and that is why, it is suffering from high costs, is without basis. The claim of injury to the domestic industry is not due to start up problems. In fact, the petitioner had achieved 100% plant utilization in March, 2008 itself. However, the plant utilization subsequently declined because of the dumping of the product in the domestic market.
- The project report of the domestic industry is a confidential document.
- None of the interested parties have identified any factor, other than dumping, which could have caused injury to the domestic industry.
- The submission that misleading statistics has been provided by the domestic industry is baseless. The domestic industry has provided all the information based on records maintained by the company and the information has been verified by the Authority.

### **M.3. Examination by the Authority**

104. The following views offered by the interested parties during the course of the investigation are examined by the Authority as follows:

1. The argument of the interested parties that subject goods are also imported from USA, UK and Germany and hence the present proceeding is incomplete in respect of the subject goods is not correct. The Authority notes that the application/petition filed by the Domestic Industry was against imports from China PR and Japan. In respect of imports from USA, UK and Germany, Authority has examined and found that although there have been imports from USA, UK and Germany as well, but they are at much higher prices as compared to the imports from subject countries.
2. The argument of the interested parties that the sales of the applicant increased to the level of 56.33% in 2008-09 and therefore the applicant's unit is a profit making unit, is not correct. Increase in sales volume solely does not mean that the product is profitable. Injury to the domestic industry has to be seen in respect of all injury parameters.
3. With regard to the argument of the interested parties that applicant has exported goods for 2007-08, 2008-09 & 2009-10 indicating it as a strategy to oust the other players from the market, the Authority notes that injury in relation to production and sales of the subject goods has been examined in the context of the domestic market.

With regard to the argument of the interested parties that the increase in import is due to manifold increase in demand in the Indian market during the so called injury period, the Authority notes that increase in demand does not entitle the exporters/producer to export the material at dumped prices. However the market share of subject countries and other countries have gone down during this period. On the contrary, share of the domestic industry has gone up during the POI vis-à-vis the preceding year. The Authority notes that the Domestic Industry has commenced commercial production only in the year 2007-08 and therefore some decline in the imports is obvious as a direct result of commencement of new production facility in the country Increase in imports is due to dumping. In the absence of dumping, the petitioner could have produced and sold more in the market, particularly when demand is increasing.

5. The argument of the interested parties that both basic customs duty and customs education cess should be included while calculating the landed value. The Authority considered the same while calculating the landed Value.
6. The argument of the interested parties that improvement in various injury parameters does not show injury to the domestic industry. The Authority notes that cumulative effect of the factors indicates that in spite of the improvement in production and sales in absolute terms, increase in capacity utilization, increase in productivity, reduction in loss per unit, increase in market share, the domestic industry suffered huge losses due to decrease in selling price as against much high cost of sales and dumped imports from the subject countries. Imports from subject countries are maintaining their significant presence and these had significant price effect resulting in price depression, price undercutting and price underselling.
7. The argument of the interested parties that during the start up period of an Industry the cost remains very high due to unabsorbed overheads and inefficient production process, which results in high raw material consumption and these facts should have been examined by the Designated Authority while coming to a conclusion that purported injury has been caused by alleged dumped imports or the same is due to start up operations. The Authority has examined and found that the claim of injury is not due to start up problems. It is noted that the petitioner had achieved 100% plant utilization in March, 2008 itself. However, the plant utilization subsequently declined due to dumping of the product in the domestic market.
8. The interested parties have argued that the Domestic Industry has never claimed Material Retardation. Moreover, both Material Injury and Material Retardation to the establishment of the Domestic Industry cannot co-exist. Project report cannot be an authentic document to compare and assess the performance of the Domestic Industry. Under the Rules, the Authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in

accordance with the principles set out in Annexure II to the Rules. The Authority notes that while some improvement in these parameters are natural result of commencement of nascent production facilities, the fact that the petitioner has not been able to increase these to the extent of capacity created in spite of significant demand in the Country itself clearly establishes that establishment of domestic industry has been materially retarded. Further, the negative profitability suffered by the domestic industry establishes that the same is on account of the dumped imports.

105. Having examined the degree and extent of dumping from China and Japan, the Authority has examined the injury caused to the domestic industry, if any, and the causal link between the dumped imports and injury so suffered by the domestic industry. The Authority holds that the applicant Company, i.e., M/s SRF Ltd constitutes a major proportion of Indian production of the subject goods during the period of investigation under Rule 2(b) of Anti-dumping Rules. Therefore, for the purpose of injury determination the applicant company has been held to constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.
106. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
107. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
108. The following are the essential facts before the Authority in respect of alleged injury to the domestic industry caused by dumped imports from China and Japan, which will form the basis for the final determination by the Authority. As per practice adopted by the DGAD, the injury period consist of the POI and preceding three years. The period of investigation in the subject case is starting from 1st April 2008 to 31st March 2009 (12 months). However, the injury investigation period will cover the period 2007-08 and the POI, as the applicant has started commercial production in the year 2007-08 only. Thus, all economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above such as production, capacity utilization, sales volume etc. have been examined for the injury period adopted. However, as information pertaining to Imports ( Volume and Value) is available for previous three years as well, the injury analysis has been carried out by adopting the period of four years that is POI and previous three years.

**N. Cumulative assessment of injury**

109. As per annexure-II (iii) of the Rules, in case, imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping Investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article, and,
  - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.
110. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%.
111. With a view to assess the conditions of competition between imported products and the like domestic product, the Authority notes that -
- a. The subject goods supplied by Foreign Producers and by the domestic industry are inter-se like articles.
  - b. The Authority has found that the imported subject goods are commercial substitutes of the domestically produced R-134a.
  - c. The information furnished to the Authority gives a reasonable indication that the exports made from the subject countries compete in the same market, as these are like products.
112. Therefore, the Authority notes that it is appropriate to, cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article, in the light of conditions of competition between the imported products and the like domestic product.
113. The Authority has taken note of various arguments put forth by the Domestic Industry (There was no response from other interested parties).
114. Annexure II of the AD Rules requires that determination of injury shall involve objective examination of both:
- a) The volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and
  - b) Consequent impact of these imports on domestic producers of such products.



115. The Authority while examining the volume of dumped imports is required to examine whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.
116. For the purpose of injury analysis the Authority has examined cumulative effect of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry to evaluate the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. Since significant dumping margins have been established for the exports from the subject countries, entire exports from the subject countries have been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal link examination.

**O. Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry**

117. With regard to the volume of the dumped imports, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, in absolute terms or relative to production and consumption in India. As far as import volume is concerned the DGCI&S import data as well as import data reported in secondary sources i.e. IBIS have been examined. The Authority notes that the DGCI&S data does not capture the imports of the subject goods being imported in to India in different nomenclature and under different Customs classifications and therefore relied upon the data from the IBIS source. Therefore, the transaction level data on the basis of IBIS source has been relied upon and the volume and value of imports have been analyzed as follows:

**P.1 Import volumes and share of subject countries**

118. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.
119. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods from the subject countries based on the transaction-wise import data from the IBIS source as follows:

Qty. in Mt

Period	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Country				
China PR	551	687	1123	1313
Trend	100	125	204	238
Japan	1057	564	992	957
Trend	100	53	94	91
Others	812	1059	1318	1281
Trend	100	130	162	158
Total	2420	2310	3433	3551
Trend	100	95	142	147
Share of subject countries (%)	66	54	62	64
Trend	100	82	94	97

120. The above data shows that volume of imports from China PR in absolute terms has consistently increased from 551 Mt during 2005-06 to 1313 Mt during 2008-09 (POI). In case of Japan the import volume decreased substantially from 1057 Mt during 2005-06 to 564 Mt during 2006-07 and increased substantially thereafter to 992 Mt during 2007-08 and marginally decreased to 957 Mt during 2008-09. Share of subject countries in total imports has remained almost at the same level during POI in comparison to 2005-06 as well as 2007-08.

## P.2. Demand, Output and Market shares

### P.2.1. Growth in Demand

	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Assessment of Demand					
➤ Imports from China	Mt	551	687	1123	1313
➤ Imports from Japan	Mt	1057	564	992	957
➤ Subject countries	Mt	1608	1251	2115	2270

**P.3. Capacity, production and capacity utilization of the Domestic Industry**

	Unit	2007-08	2008-09
Capacity	MT	3,000	3,000
Production	MT	1,061	1,343
Capacity Utilization	%	35.37%	44.77%
Domestic Sales	MT	909	1,421
Demand	MT	4,342	4,972

123. The Authority notes that production, capacity utilization and sales of the domestic industry have increased both in absolute and relative term. However, the domestic industry operated at much lower level of capacity utilization as planned/ projected despite high demand in domestic market. The dumping has thus prevented the domestic industry to adequately utilize its capacity.

**Q. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

124. With regard to the effect of dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18, the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of like product in India or whether effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred to a significant degree.

125. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries have been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

**Q.1. Evaluation of price over period under consideration**

	Unit	2007-08	2008-09
Cost of sales	Rs./Kg	***	***
Trend	Indexed	100	94
Selling Price (NSR)	Rs./Kg	***	***

Trend	Indexed	100	96
-------	---------	-----	----

126. The Authority notes that cost of sales of the domestic industry has gone down by \*\*\*% during POI in comparison to previous year. Similarly, the net selling price of the domestic industry has also decreased by \*\*\*% during the corresponding period.

**Q.2. Price undercutting and underselling effects**

	Unit	2007-08	2008-09
<b>Net sales realization</b>	Rs./Kg	***	***
<b>Landed price</b>			
Japan	Rs./Kg	***	***
China PR	Rs./Kg	***	***
Total subject countries	Rs./Kg	***	***
<b>Price undercutting</b>			
Japan	Rs./Kg	***	***
China PR	Rs./Kg	***	***
Total subject countries	Rs./Kg	***	***
<b>Price undercutting (%)</b>			
Japan	%	---	10 – 20
China PR	%	---	1 – 10
Total subject countries	%	---	5 - 15
<b>Non Injurious Price</b>	Rs./Kg		***
<b>Price Underselling</b>			
Japan	Rs./Kg	-	***
China PR	Rs./Kg	-	***
Total subject countries	Rs./Kg	-	***
<b>Price Underselling (%)</b>			
Japan	%	-	50 – 60
China PR	%	-	40 – 50
Total subject countries	%	-	45 - 55

127. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted. Price undercutting has been determined by comparing the landed value of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the net sales realization of the domestic industry for the same period.

➤ Imports from Other Countries	Mt	812	1059	1318	1281
Sales of Domestic Industry	Mt	-	-	909	1421
Assessed Demand	Mt	2420	2310	4342	4972

121. Though the commercial production of the domestic industry has been started during the year 2007-08, the demand has been analyzed for the year 2005-06 and 2006-07 also basing on the imports. The Authority notes that demand of the subject goods in the country has increased by more than 100% during POI in comparison to the year 2005-06 and by 15% during POI in comparison to immediate preceding year. It is further noted that demand in absolute terms has increased by 630 Mt during POI in comparison to the immediate preceding year and share of domestic industry has increased by 512 Mt during the same period.

## P.2.2 Market share in Demand

Market Share in Demand	Unit	2007-08	2008-09
Imports from China	%	25.86	26.41
Imports from Japan	%	22.85	19.25
Import from subject countries	%	48.71	45.66
Imports from Other Countries	%	30.35	25.76
Domestic Industry	%	20.94	28.58
Other Producers	%	0	0

122. It is observed by the authority that the imports from China has increased marginally and imports from Japan has decreased marginally during POI viz-a-viz. preceding year. However, cumulatively the import share of subject countries and other countries have gone down during this period. On the contrary, share of the domestic industry has gone up during the POI vis-à-vis the preceding year. However, the Authority notes that the Domestic Industry has commenced commercial production only in the year 2007-08 and therefore some decline in the imports is obvious as a direct result of commencement of new production facility in the country. However, the applicant had anticipated/projected (as per their project report) significantly higher sales/ market share in the increasing demand as opposed to much lower levels achieved during the POI.

Price undercutting has been determined individually for China PR and Japan and for subject countries as a whole. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charge and applicable basic customs duty to the value reported in the IBIS data of import prices from the subject countries. The price undercutting from China PR and Japan has been determined as \*\*\*% and \*\*\*% respectively and cumulative price undercutting from subject countries has been determined as \*\*\*% during POI.

128. For the purpose of price underselling the landed prices of imports from subject countries have been compared with the Non-injurious price of the domestic industry determined for the POI. The price underselling from China PR and Japan has been determined as \*\*\*% and \*\*\*% respectively and cumulative price underselling from subject countries has been determined as \*\*\*% during POI.

129. Volume and Import price movement of the subject countries has been analyzed for the years 2005-06 onwards in the following table:

Volume of Imports	Unit	2005-06	2006-07	2007-08	POI
China	Mt	551	687	1123	1313
Japan	Mt	1056	564	991	957
Average import price					
China	Rs./Kg	***	***	***	***
Japan	Rs./Kg	***	***	***	***
Domestic net selling price	Rs./Kg	---	---	***	***

130. The Authority notes that export price from China PR was to the tune of Rs. \*\*\* per Kg during the year 2005-06 and reduced to Rs. \*\*\* per Kg during 2006-07 and further reduced to Rs. \*\*\* during the year 2007-08. Similarly, export prices from Japan was to the tune of Rs \*\*\* per Kg during the year 2005-06 and after marginal increase to Rs \*\*\* per kg during the year 2006-07, steeply decreased to Rs \*\*\* during the year 2007-08 and again marginally increased to Rs \*\*\* per Kg during POI. It is evident that both the subject countries steeply reduced the prices during the year 2007-08 in which the domestic industry started the commercial production. Despite such discouraging market behavior of the subject countries, as the domestic industry could realize prices higher than the import prices, both the subject countries increased their prices during the year POI, still causing injury to the domestic industry.

**Q.3 Price suppression and depression effects of the dumped imports:**

131. Price suppression and depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject countries. The price depression exists when the industry's prices are lower than the level of the previous period. Price suppression occurs when dumping prevents price increase that would otherwise take place due to increase in cost.

Particular	Unit	2007-08	POI
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***
Trend	Index	100	94
Selling Price	Rs./Kg.	***	***
Trend	Index	100	96
Landed Price	Rs./Kg.		
Japan	Rs./Kg.	***	***
China PR	Rs./Kg.	***	***
Subject Countries	Rs./Kg.	***	***
Trend	Index	100	117

132. From the above table it is evident that when the cost of sales reduced from 100 in the previous year to 94 during the POI, selling price reduced from 100 to 96 during the corresponding period and shows the absence of price depression. However, it is noted that cheap imports from the subject countries did not allow domestic industry to increase their selling price and thereby suppressed the prices of the domestic industry.

**R. Examination of other Injury Parameters**

133. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analyzed hereunder as follows:

**R.1. Profits and actual and potential price effects on the cash flow**

	Unit	2007-08	2008-09
Cost of sales	Rs./Kg	***	***
Trend	Indexed	100	94
Selling Price (NSR)	Rs./Kg	***	***
Trend	Indexed	100	96
Profit/Loss	Rs./Kg	***	***
Trend	Indexed	-100	-91
Profit/Loss before Tax	Rs.Lacs	***	***
Trend	Indexed	-100	-142
PBIT	Rs.Lacs	***	***
Trend	Indexed	-100	-150
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***
Trend	Indexed	-100	-183

134. The data indicate that cost of sales of the domestic industry decreased by \*\*\* % during POI as compared TO previous year against which the selling price decreased by \*\*\* % during POI. Though, the loss per unit has come down during POI in comparison to previous year but domestic Industry continues to incur huge losses in the POI.

**R.2. Return on investment and ability to raise capital**

	Unit	2007-08	2008-09
PBIT	Rs.Lacs	***	***
Trend	Indexed	-100	-150
Net Fixed Assets	Rs.Lacs	***	***
Trend	Indexed	100	96
Working Capital	Rs.Lacs	***	***
Trend	Indexed	100	62
Capital Employed	Rs.Lacs	***	***
Trend	Indexed	100	92
Return on Capital Employed (NFA basis)	%	***	***
Trend	Indexed	-100	-162

135. The Authority notes that the return on the capital employed for domestic sales of the domestic industry has declined significantly during the POI as compared to the



preceding year and during the POI as well as the preceding year the domestic industry had a negative return from the subject goods.

### R.3 Productivity

	Unit	2007-08	2008-09
Production	Mt	1,061	1,343
Trend	Index	100	127
No. of Employees	Nos.	***	***
Productivity per employee	MT/No.	***	***
Trend	Indexed	100	113

136. The data on production per employee shows that productivity per employee has increased by 13% in POI as compared TO previous year.

### R.4 Employment and wages

	Unit	2007-08	2008-09
Employment (Manpower strength)	Nos.	***	***
Trend	Indexed	100	113
Wages	Rs.Lacs	***	***
Trend	Indexed	100	111

137. The employment level and wages do not show significant change. This may be attributable to the fact that the domestic industry has commenced its production of the subject goods during 2007-08 only. Despite incurring huge losses, the domestic industry could increase the wages by \*\*\*% during POI.

### R.5 Inventories

Inventories	Unit	2007-08	2008-09
Average	Mt	***	***
Trend	Indexed	100	64

138. The Authority notes that the average inventory of domestic industry has reduced from \*\*\* Mt during the year 2007-08 to \*\*\* Mt during POI. The average inventory in indexed form has reduced from 100 during the year 2007-08 to 64 during the POI.

**R.6. Growth**

139. The Authority notes that the domestic industry has shown positive growth in terms of increase in production and domestic sales, increase in capacity utilization, increase in productivity, reduction in loss per unit and decrease in closing inventory. However, despite such positive growth indicators, the domestic industry continues to incur huge losses due to low selling price.

**R.7. Ability to raise fresh Investment**

140. The authority notes that the domestic industry had not changed the capacity of subject goods and there has been no fresh investment by the domestic industry during the period of investigation as the petitioner has recently commenced commercial production.

**R.8 Magnitude of Dumping**

141. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margins determined against the subject countries, for the POI, are significant.

**R.9. Factors affecting prices**

142. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree. In order to assess the effect of imports on the domestic market, the Designated Authority analyzed import prices over the injury period. It was found that the landed value per KG in POI was lower than both the net selling price and non-injurious price of R-134a in respect of both the subject countries. Change in cost structure if any, due to competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors that might be affecting the prices in the domestic market. The cost of production has decreased by \*\*\*% during POI whereas the net selling prices decreased by \*\*\*% during the same period. However, the Authority notes that despite the second year of its operations, the prices of domestic industry remained significantly depressed at the level significantly below its cost of production. The Authority notes that Landed values of imported material from subject countries are significantly below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting in the Indian market. The price undercutting during POI was in the range of 2-12% and underselling was in the range of 40-50% during POI.

## **S. Conclusion on injury**

143. The above analysis of the factors indicates that in spite of the improvement in production and sales in absolute terms, increase in capacity utilization, increase in productivity, reduction in loss per unit, increase in market share, the domestic industry suffered huge losses due to decrease in selling price as against much high cost of sales and dumped imports from the subject countries.
144. Imports from subject countries are maintaining their significant presence and these had significant price effect resulting in price depression, price undercutting and price underselling.
145. On the basis of above analysis, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

## **T. Causal Link & Other factors**

146. Interested parties have argued in favor of absence of causal link in view of the following:
- a) Change in the pattern of consumption despite increase in demand, domestic industry is unable to make profits in the sale of R134a because of its very high cost structure.
  - b) Poor exports achieved compared to projected export targets were the sole reason for the losses suffered by the domestic industry during 2008-09.
  - c) SRF is offering significantly low prices, users are forcing exporters also to match the prices set by SRF.
  - d) There is no causal link between the injury to the domestic industry and the imports from China.
  - e) Global recession is the main cause of decline in sales prices, decline in demand of finished products and decline in production and sales quantities.

## **Views of the Domestic industry**

147. Domestic industry claimed that the petition, preliminary findings and written submissions are referred to and relied upon, which clearly establishes the causal link between dumped imports and injury to the domestic industry

## **Examination by Authority**

148. Having examined the existence of material injury and volume and price effect of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, price underselling and price suppression and price depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreements on anti dumping, have been examined to see whether there are any other factors, other than

the dumped imports, that could have contributed to injury to the domestic industry. The following parameters have been examined in this regard.

### **U.1 Volume and prices of imports from other sources**

149. The Authority notes that although there have been imports from other countries as well, but they are at much higher prices as compared to the imports from subject countries.

Rs./kg.	2007-08	2008-09
Import price		
China	***	***
Japan	***	***
Third countries	***	***
Difference	83.38%	57.88%

### **U.2 Contraction in demand and / or change in pattern of consumption**

150. The Authority notes that the demand of the product under consideration has not registered any negative growth. In fact, demand shows significant positive growth. Thus, contraction in demand is not a possible reason that could have contributed to injury to the domestic industry. Also, the pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry. The argument of the interested parties that the global recession is the main cause of decline in sales prices, decline in demand of finished products and decline in production and sales quantities is not tenable with the trends reflected by injury parameters.

### **U.3 Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

151. The Authority notes that there is a single market for the subject goods where dumped imports from subject countries compete directly with the subject goods produced by domestic industry. The Authority also notes that the imported product is sold to meet the similar commercial grades and specifications as domestically produced subject goods and that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/ end uses.

152. The Authority notes that there is no restricted practice prevalent in the industry, which could be attributed to the injury to the domestic industry.

**U.4 Development of Technology**

153. On the basis of examination of the records of the petitioner, the Authority holds that development in technology has not been a relevant factor for the injury to the domestic industry. Further, domestic industry as well as the exporters from China PR is following the same process of production and there is no response from Japan.

**U.5 Export performance**

154. The Authority notes that the petitioner also exports a part of their production, and there has been increase in exports from 4 Mt during the year 2007-08 to 87 Mt during POI. But, the quantity that is exported constitutes a meagre amount i.e.; just 6.4 % of the total production of the domestic industry in the POI. Hence, the Authority holds that material injury suffered by the domestic industry may not be as a result of the export performance of the domestic industry.

**U.6. Productivity of the Domestic Industry**

155. Productivity of the domestic industry in terms of production per employee has shown improvement.

156. No other factor, which could have possibly caused injury to the domestic industry, has been brought to the knowledge of the Authority.

**V. Magnitude of Injury Margin**

157. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The landed price of the exports from the subject countries and the injury margins have been worked out as follows:

**V.1. Injury margin Calculations**

Producer	Exporter	Injury Margin (USD/Kg.)	Injury Margin (%)
<b>China PR</b>			
Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co Ltd.	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co Ltd	***	40 - 50
Sinochem Environmental	Du-Pont Trading	***	45 - 55

Protection Chemicals (Taicang) Co Ltd.	(Shanghai) Co. Ltd.		
Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co. Ltd.	Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co. Ltd.	***	30 - 40
Any	Any	***	45 - 55
Japan			
Any	Any	***	50 - 60

#### W. Indian industry's interest & other issues

158. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

159. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

#### X. Conclusions

160. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- a. The subject goods have been exported to India from the subject countries below its normal value;
- b. The domestic industry has suffered material injury, caused by the dumped imports from subject countries;
- c. The dumping margins of the subject goods imported from the subject countries are substantial and above de minimis.

#### Y. Recommendations

161. Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the known interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and

other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and completed the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the Anti-dumping Rules laid down and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports from the subject countries, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping measures is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder from the date of notification by the Central Government.

162. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**Duty Table**

Sl. No.	Sub Heading Of Tariff item	Description of Goods	Country Of Origin	Country Of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.
1	29033919	1,1,1,2-Tetrafluoroetha or R-134 a	China PR	China PR	Sinochem Environmental Protection (Taicang) Co. Ltd.	Sinochem Environmental Protection (Taicang) Co. Ltd.	1.15	Kg	USD
2	- Do -	- Do -	China PR	China PR	Sinochem Environmental Protection (Taicang) Co. Ltd	Du-Pont Trading (Shanghai) Co. Ltd.	1.36	Kg	USD
3	- Do -	- Do -	China PR	China PR	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Xian) Co. Ltd.	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Xian) Co. Ltd	1.15	Kg	USD
4	- Do -	- Do -	China PR	China PR	Any Combination of producer and exporter other than Sl. No. 1 to 3		1.41		USD

5	- Do -	- Do -	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	1.41	Kg	USD
6	- Do -	- Do -	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	1.41	Kg	USD
7	- Do -	1,1,1,2-Tetrafluoroetha or R-134 a	Japan	Japan	Any	Any	0.69	Kg	USD
8	- Do -	- Do -	Japan	Any	Any	Any	0.69	Kg	USD
9	- Do -	- Do -	Any country other than Japan	Japan	Any	Any	0.69	Kg	USD

163. An appeal against the findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority